

Daily सच के हक में...

Tamannaah Bhatia Discusses...

Ranchi ● Thursday, 05 December 2024 ● Year : 02 ● Issue : 312 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com

समन अवहेलना मामले में हाईकोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

सीएम हेमंत को 16 दिसंबर तक

दफोटोनन्यूज Published from Ranchi

E-Paper : epaper.thephotonnews.com

: 80,956.33 निफ्टी 24,467.45

7,310

चांदी 100.00 (नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS आज हेमंत कैबिनेट का

विस्तार, मंत्री लेंगे शपथ

RANCHI: 28 नवंबर को हेमंत सोरेन के शपथ लेने के एक सप्ताह बाद आज यानी 5 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार होगा। इसके तहत 'इंडिया' गढबंधन के तीनों प्रमुख दलों-झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद के विधायक राजभवन में अपराह्न 12:30 बजे मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। जानकारी के अनुसार, झामुमो से ६, कांग्रेस से ४ और राजद से एक मंत्री का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। तीनों पार्टियों ने मंत्री बनने वाले विधायकों का नाम तय कर लिया है।

आरजेडी कोटे से संजय प्रसाद यादव बनेंगे मंत्री

RANCHI: आरजेडी की ओर से



कि यादव ने बीजेपी के उम्मीदवार अमित मंडल को चुनाव में पराजित किया था। संजय प्रसाद यादव लालू यादव के करीबी माने जाते हैं। गौरतलब है कि 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन सरकार की मंत्रिमंडल का विस्तार होना है।

महाराष्ट्र सहित 4 राज्यों में 15 सेकेंड तक हिली धरती

NEW DELHI: बुधवार को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में सबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर आफ सौस्मोलॉजी के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भुकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई। झटके सुबह ०७: २७ बजे महसूस किए गए। भुकंप का केंद्र जमीन से 40 किलोमीटर नीचे रहा। भूकंप के झटके 15 से 20 सेकेंद्र तक लगे। दाटके महाराष्ट्र के नागपुर, चंद्रपुर और गढ़िचरौली और दंतेवाड़ा में महसूस किए गए। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुलुग, हैदराबाद, रंगारेड्डी,भद्राद्री कोठागुडेम, खम्मम और कृष्णा जिलों में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के चलते कई घरों की दीवारों में दरारें आ गई। लोगों ने घरों से बाहर, खुले मैदान में आकर खुद को सुरक्षित किया।

दो दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे भटान नरेश

NEW DELHI: भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक गुरुवार को भारत की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक प्रगाढ बनाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके साथ उनकी पत्नी जेटसन पेमा वांगचुक और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा पर आएंगे। यात्रा के दौरान, भूटान नरेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे।

कोर्ट में उपस्थिति से मिली छुट

PHOTON NEWS RANCHI: बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली। मख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका एमपी-एमएलए कोर्ट से खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर तक समन अवहेलना मामले में मख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान की है। मामले के सनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में हुई। अदालत ने मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से

एमपी-एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत पेशी से छूट वाली याचिका की थी खारिज



को रद्द करने का आग्रह करते हुए दाखिल की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट में मंगलवार को याचिका

सीएम से पूछताछ के लिए कई बार ईडी ने जारी किया था समन

बता दें कि ईडी के समन की अवहेलना के मामले की सुनवाई पहले सीजेएम कोर्ट में चल रहीं थी। तीन जून को सीजेएम कृष्ण कांत मिश्रा ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था। वहां सुनवाई के बाद 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इसका आदेश २६ नवंबर को जारी किया गया। मख्यमंत्री हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित सीआरपीसी की धारा 205 के तहत दाखिल पिटीशन को एमपी-एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया था। हेमंत

सोरेन ने हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इस आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया था। मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ उपस्थिति को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट से समन जारी है। झारखंड की राजधानी रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आरोपी बनाया था। इस मामले में अगस्त 2023 से जनवरी 2024 के बीच ईडी ने पूछताछ के लिए कई बार झारखंड के सीएम को समन जारी किए, लेकिन हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

ऑफिस में हाजिर नहीं हुए।

3-5 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा पारा, सुबह में छाया रहेगा कोहरा

अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई शुरू, अलर्ट

PHOTON NEWS RANCHI: अब झारखंड में कडाके की ठंड पडने की स्थिति स्पष्ट हो

चुकी है। फेंगल तूफान का असर खत्म होने के बाद तापमान में गिरावट शुरू हो गई है। अब झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड पर्डेगी। इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। आने वाले दिनों में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट की संभावना जताई गई है। इस दौरान सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। गुरुवार को न्यूनतम तापमान में हल्की सी गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे अन्य दिनों की अपेक्षा ढंड ज्यादा लगेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, गुरुवार के बाद से कई जिलों में न्यूनतम तापमान ३ से ५ डिग्री गिर सकता है। गुरुवार को संताल परगना के कई जिलों में न्यनतम तापमान 10–11 डिग्री के बीच रह सकता है, जबकि राजधानी 12 डिग्री के आसपास रह सकता है। इस कारण लोगों

आज अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा सर्दी रहने की संभावना राजधानी में 12 डिग्री के आसपास रहेगा मिनिमम टेंपरेचर



८ और ९ दिसंबर को हो सकती है बारिश

अभिषेक आनंद ने बतारा कि 7 दिसंबर से बादल रहने की संभावना के कुछ जगहों पर बारिश होने की आशंका है। 10 दिसंबर से फिर से

आसमान साफ होने का अनुमान है। १० से आसमान साफ होने पर तापमान गिरेगा और फिर से 10 दिसंबर से ठंड और बढ़ेगी।

रांची में रहेगी धुंध

मौसम विभाग के अनुसार, पांच दिसंबर को राजधानीँ रांची में सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। पांच दिसंबर को राजधानी रांची में अधिकतम तापमान २७ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेने की संभावना जताई गई है। बुधवार को राज्य में सबसे अधित ताँपमान जमशेदपुर में 29 .४ डिग्रा साल्सयस दर्ज किया गया। गढ़वा में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ज किया गया।

केंद्र सरकार ने लोस में पेश किया रेलवे विधेयक २०२४

NEW DELHI : बुधवार को केंद्र सरकार ने लोकसभा में रेलवे (संशोधन) विधेयक २०२४ पेश किया। विधेयक १९०५ के रेलवे बोर्ड अधिनियम और 1989 के रेलवे विधेयक को एकीकृत करेगा। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने विधेयक को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड और रेलवे से जुड़े विधेयक को एकीकृत करने से रेलवे का विकास और कार्यदक्षता बढ़ेगी। वैष्णव ने कहा कि पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने रेलवे के बजट में कई गुना का इजाफा किया है। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के तहत केंद्र सरकार रेलवे के संबंध में अपनी शक्तियों और कार्यों को रेलवे बोर्ड में निवेश कर सकती है। विधेयक १९०५ अधिनियम को निरस्त करता है और इन पावधाने को रेलवे अधिनियम, 1989 में शामिल करता है।

मंईयां योजना की राशि जुटाने के लिए हेमंत सरकार ने कसी कमर

५३ लाख महिलाओं मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि जुटाना के लिए हेमंत के खाते में हर माह सरकार ने कमर कस ली है। इस भेजे जाने हैं ₹2500 योजना के तहत अभामां 53 लाख महिलाओं के खाते में ₹2500 जाने हैं। इस माह की किस्त के पैसे 11 दिसंबर को ट्रांसफर किए जाएंगे। एक आकलन के अनसार, इस पर सालाना करीब 16 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार सरकार पर पड़ेगा। लाभुकों को हर माह पैसे मिलते रहें, इसके लिए सरकार कने उन खातों के पैसे का इस्तेमाल करने को कहा है, जिनका इस्तेमाल पिछले दो साल से नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए महिला बाल विकास एवं सामाजिक सरक्षा विभाग काम करते हैं। बता दें कि सरकार ने दिसंबर से योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए भुगतान सुनिश्चित करने का संकल्प जारी कर दिया है। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसके लिए

हजार करोड रुपये का अतिरिक्त भार

खातों में पड़े

पैसे का भी

इस्तेमाल

💻 वित्त विभाग ने पुरी की 10 दिसंबर को पेश होनेवाले द्वितीय अनुपूरक बजट की तैयारी

💻 मूल बजट में नहीं था राशि का प्रावधान

इस विषय पर गंभीर मंथन हुआ। विभागीय सचिवों को योजना मद के राज्य शेयर में से 5 से 50% तक राशि सरेंडर करने का निर्देश दिया है। सरेंडर हुई राशि को पुनर्विनियोग द्वारा समाज कल्याण को मंईयां योजना के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अनुपुरक बजट में राशि का प्रावधान

लाभुकों के खाते में राशि डालने के लिए हर महीने की 15 तारीख तय की गई है। पिछले महीनों में पहले भी भुगतान हुआ है, पर इस बार समाज कल्याण विभाग के पास फंड नहीं होने से कई जिलों में दो-चार दिनों का विलंब भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, विभाग ने फंड के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान करने का पस्ताव दिया है। उम्मीद है कि 9 दिसंबर से शुरू हो रहे विशेष सत्र में मंईयां योजना के लिए अनुपूरक बजट

विभाग के फंड में रकम नहीं हैं।

विभाग ने इसके लिए अनुपूरक

बजट में राशि उपलब्ध कराने के

लिए वित्त विभाग को मांगपत्र

भेजा है। वित्त विभाग ने 10

दिसंबर को पेश होनेवाले द्वितीय

अनुपूरक बजट में इसके लिए

आवश्यक राशि उपलब्ध कराने

के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मंईयां सम्मान योजना के लिए मूल

बजट में प्रावधान नहीं था। मुख्य

सचिव की अध्यक्षता में हुई

विभागीय सचिवों की बैठक में भी

में राशि का पावधान हो जाएगा। 27 नवंबर को राज्य के वित्त सचिव ने विभिन्न विभागों के पीएल खातों में पड़े पैसों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने दो वर्ष से कोषागार से पड़े पैसों को राजकोष में जमा करने का निर्देश दिया था। पीएल अकाउंट में ऐसे करीब 14,000 करोड़ रुपये पड़े हैं। जिन विभागों के पीएल खाते म पस अब तक पड है, उनम पथ, भवन निर्माण, गृह कारा, कल्याण, आईटी, पीआरडी शामिल हैं।

हमलावर खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार

को अन्य दिनों की मुकाबले अधिक ढंड लगेगी।

पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग, बाल-बाल बचे

AGENCY AMRITSAR: बुधवार को अमृतसर स्थित

गोल्डेन टेंपल में पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग की। बादल गोल्डेन टेंपल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें यह सजा दी है। वारदात के वक्त हमलावर ने जैसे ही उन पर गोली चलाई, उसी समय सिविल वर्दी में तैनात उनके



सुरक्षाकर्मियों ने उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डेन टेंपल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर बादल बाल-बाल बच गए। इसके बाद हमलावर ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया।

'प्रोबा-३' अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थगित SRIHARIKOTA : बुधवार को भारतीय

अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 'प्रोबा-3' अंतरिक्ष यान में पाई गई एक विसंगति के कारण पीएसएलवी-सी59 का प्रक्षेपण गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को प्रस्तावित प्रक्षेपण से चंद मिनट पहले अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की। अंतरिक्ष एजेंसी ने मूल रूप से बुधवार को शाम 4 बजकर आँठ मिनट पर यहां अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण की योजना बनाई थी। एजेंसी ने प्रस्तावित प्रक्षेपण से चंद मिनट पहले एक बयान में कहा, प्रोबा-3 अंतरिक्ष यान में पाई गई विसंगति के कारण पीएसएलवी-सी59/प्रोबा–३ का प्रक्षेपण स्थगित कर

दिया गया है। अपनी तरह की दुनिया की पहली पहल के तहत 'प्रोबा-3' में दो उपग्रह शामिल हैं, जिसमें दो अंतरिक्ष यान एक साथ उड़ान भरेंगे, जो सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करेंगे।

आज लेंगे ओथ, मुंबई के आजाद मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस

भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। गुरुवार को वह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

इसके पहले उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चना गया। फिर बधवार को महायुति के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा टोका। शिवसेना प्रमख एकनाथ शिंदे, भाजपा नेता देवेंद्र फंडणवीस, एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने राज्यपाल सीपी

राधाकृष्णन से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। उनके साथ पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपानी भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा।

महायुति के नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का ठोका दावा शिंदे और अजित ने सौंपा समर्थन पत्र

गवर्नर ने सरकार बनाने को किया आर्मेत्रित

महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हमने राज्यपाल से मुलाकात की है और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए समर्थन पत्र सौंपा है। फडणवीस ने बताया, हमारे गढबंधन सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने राज्यपाल से अनरोध किया है कि मझे महायति के मख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाए। राज्यपाल ने सभी अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं और हमें गुरुवार की शाम 5:30 बजे शपथ समारोह के लिए आमंत्रित किया है।

शिवसेना अध्यक्ष और शिवसेना विधायक दल के प्रमुख के तौर पर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के राज्यपाल को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। सिफारिश करते हुए एक पत्र दिया है। कुछ निर्दलीय विधायकों भी ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के पद सिर्फ तकनीकी पद हैं। हम सभी महाराष्ट्र के लिए मिलकर काम करेंगे।

अन्य मंत्रियों के नाम पर आगामी

बैठकों में फैसला लिया जाएगा।

इजाजत नहीं मिलने पर लौटे दिल्ली

सेना की ताकत और रणनीति के हिसाब से गतिविधियों की तय की दिशा नर्ड चाल

आर्मी के लिए चुनौती बनी आतंकियों की बदली हुई स्ट्रेटजी

जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० की समाप्ति के बाद भारतीय सेना ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार शुरू किया। आतंकवादियों ने इसका बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपनी रणनीति में तब्दीली की। गुजरे वक्त की घटनाएं बता रही हैं कि आतंकियों की बदली हुई स्ट्रेटजी सेना के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं है। कश्मीर के बारामूला पुलिस को अक्टूबर में एक अनोखी वारदात की जानकारी मिली। एक सुदूर गांव में जंगल के पास बनी दुकान का दरवाजा रात में आतंकियों ने तोड दिया। खाने-पीने और राशन का सामान ले गए। सामान की कीमत से ज्यादा रुपये एक डिब्बे के नीचे रख गए। दुकान पर 15 दिन में यह दसरी वारदात थीं। दूसरी ओर किश्तवाड़ में हुए एनकाउंटर में रातभर में आतंकवादियों ने सिर्फ 6 फायर किए। इसके बाद भाग निकले। ये दो घटनाएं जम्मू-कश्मीर में पाक से घुसे आतंकियों की बदलती स्ट्रेटजी कर संकेत करती हैं। पहला– न लोकल आतंकी भर्ती किए जा रहे हैं, न लोकल मददगार

रखे जा रहे हैं। सब खुद मैनेज कर रहे हैं।

इनपुट बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में 125 से ज्यादा विदेशी आतंकवादी सक्रिय ऑपरेशन के दौरान 60 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं भारतीय जवान जवान अक्टूबर में हुई अनोखी वारदात

- ने खड़े कर दिए पुलिस और सैन्य अधिकारियों के कान
- गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग लेकर हो रहे पारंगत, पुराने हथियारों को भी त्यागा
- संगठन में लोकल युवकों की भर्ती पर एक प्रकार से लगा दी है रोक
- एनकाउंटर के दौरान कम फायरिंग कर तुरंत भाग निकलने की अपनाई सेफ्टी पॉलिसी



राशन के लिए दुकानों में सेंध जैसे हथकंडे

आतंकी मिनिमम सिविल कॉन्टैक्ट रख रहे हैं। राशन के लिए दुकानों में सेंध जैसे हथकंडे अपना रहे हैं। जंगल में लगातार लोकेशन बदलते रहते हैं। पर्वतारोहियों के लिए बने

एप से जंगल में रास्ते खोजते हैं। नजर में आने से बचने को दो-चार आतंकी ही साथ चलते हैं। इस कारण आबादी से दूरी आर्तोकयों को फायदा पहुंचा रही है।

3 संगढनों की हलचल

कश्मीर में मुख्य रूप से तीन आतंकी संगठन सक्रिय हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयब्बा और हिजबुल-मुजाहिद्दीन। जैश ने कश्मीर में आत्मघाती हमले किए। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सोपोर-बारामूला में करीब 30 आतंकी हैं। बारामूला-पट्टन-किरिरी पट्टी में 10 और सोपोर में 20 से ज्यादा विदेशी आतंकी हैं। बांदीपुरा-हाजिन में यह संख्या १८ तक है। शोपियां-कुलगाम में 18 से 20, पुलवामा में 10 से 15, कपवाडा और अनंतनाग में 10 से ज्यादा विदेशी आतंकी हैं। जम्मू डिवीजन में 45 से 50 विदेशी आतंकवादी सक्रिय हैं।

गृह मंत्री अमित शाह से मिलीं वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा

NEW DELHI : बुधवार को कांग्रेस महासचिव और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाद्रा ने केरल के कई लोकसभा सदस्यों के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित लोगों की मदद का आग्रह किया। संसद भवन परिसर स्थित शाह के कार्यालय में यह मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान केरल से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस, आईयूएमएल और आरएसपी के सांसद के मौजूद थे। शाह से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा, हमने गृह मंत्री जी से मिलकर उन्हें वायनाड के हालात से अवगत करवाया है। वहां के लोगों के जीवन पर भूस्खलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। लोगों के परिवार और घर उजड़ गए हैं, उनके पास कोई सहयोग तंत्र नहीं बचा है। उन्होंने कहा, इन हालात में केंद्र सरकार अगर कुछ न करे, तो लोग किससे उम्मीद करेंगे। हमने गृह मंत्री जी से अपील की है कि राजनीति को परे वायनाड के लोगों की मदद की जाए।

संभल जाते समय गाजीपुर बॉर्डर पर रोके गए राहुल

उत्तर प्रदेश के हिंसा प्रभावित संभल जाते समय बुधवार को गाजीपुर बॉर्डर पर रोके जाने के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट आए। उनके साथ सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी था। राहुल गांधी ने कहा कि वे पुलिस के साथ अकेले संभल जाने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है, जो असंवैधानिक है। लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर यह उनका संवैधानिक अधिकार

है। इसकी अनुमति मिलनी चाहिए

थी। हालांकि राहुल गांधी को रोकने

के क्रम में पुलिस ने जो बंदोबस्त

किए थे, उसके कारण सड़क पर

AGENCY NEW DELHI:

वाहनों का लंबा जाम लग गया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन और पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने से रोकने के लिए पहले ही सीमा पर नाकाबंदी कर दी थी, क्योंकि वहां पर बाहरी लोगों के जाने पर रोक लागू है। जिले में निषेधाज्ञा भी लागू है, जहां पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी (सपा) के कई सांसदों को जिले में

प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

गिरिडीह के तीन गोदामों में लगी आग से करोड़ों की संपत्ति खाक

प्लाईवुड व बिजली के सामान सिहत चपेट में आ गई कार-बाइक भी

जिले के पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो में स्थित प्लाईवुड के दो और बिजली सामान के एक सहित कुल तीन गोदामों में भीषण आग लग मंगलवार मध्य रात्रि की बताई जा रही है। आग लगने की वजह से लगभग दो करोड़ रुपये की संपत्ति की क्षति का अनुमान है। बताया गया है कि घटना में गोदाम में रखे प्लाईवुड सहित कई सामान के अलावा दो मोटरसाइकिल और एक एक्सयूवी कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना को लेकर बाबाधाम प्लाईवुड के संचालक रवि कुमार साहू ने कहा कि बोलो हवाई अड्डा के बगल में झमराज इंटरप्राइजेज, बाबाधाम



BRIEF NEWS

मंईयां योजना के लिए सुबह से जुट रहीं महिलाएं

DHANBAD : मंईयां सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी

दफ्तरों में महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं। हाल यह है कि

सुबह से अंचल कार्यालयों में महिलाओं की जुटान हो रही है। धनबाद

अंचल कार्यालय में बुधवार की सुबह महिलाओं की लंबी कतार लगी

रही। सुबह 10 बजते-बजते कतार कार्यालय परिसर से बाहर सड़क तक

पहुंच जा रही है। दस बजे तक दफ्तर में कोई कर्मचारी नहीं था। समय

पर कर्मचारियों के नहीं आने के कारण महिलाओं में नाराजगी दिखी। ज्ञात

हो कि राज्य सरकार ने दिसंबर से ही मंईयां योजना की राशि में वृद्धि की

घोषणा की है। पहले प्रतिमाह एक हजार रुपये मिल रहे थे। जानकारी के

मुताबिक 11 दिसंबर को पहली किस्त के रूप में 2500 रुपये दिए जाएंगे।

मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी भाकपा-माले : अरूप

DHANBAD: निरसा के विधायक अरूप चटर्जी ने बधवार को कहा कि

भाकपा-माले झारखंड मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि

झारखंड की जनता ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण जनादेश दिया है। भाकपा

माले ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। सभी की इच्छा थी कि

गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिले और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनें।

विधायक ने कहा कि मैं मंत्री बनं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने

वाला है। जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरने का हरसंभव प्रयास

करूंगा और अब वह समय आ भी गया है। निरसा सहित पूरे धनबाद

जिले में विकास को कोई भी काम नहीं रुकेगा। इधर, सिंदरी से भाकपा-

माले के विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो ने भी अरूप चटर्जी

बीआईटी में क्वालिटी क्लब का ओरिएंटेशन सत्र

SINDRI : बीआईटी सिंदरी के क्वालिटी क्लब का ओरिएंटेशन सत्र

बुधवार को हुआ, जिसमें डॉ. घनश्याम, डॉ. माया राज नारायण, डॉ.

ओमप्रकाश सहित कई शिक्षक और क्लब के सदस्य थे। सत्र में क्लब

की शुरूआत की गई और छात्रों को इसके कामकाज और उद्देश्यों की

जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आईएफक्यूएम से जुड़ी बड़ी कंपनियों के

DHANBAD : दिल्ली में 17 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन

कोल माइंस की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता कोयला मंत्री करेंगे। इसमें

की बातों का समर्थन किया।

सीईओं के संदेश भी साझा किए गए।

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 17 को

कोयला खदानों की सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी।

सामान का गोदाम है। बाबाधाम के किया कि गोदाम में आग लग गई संचालक वे खुद हैं। झुमराज है। यह सुनते ही वह आनन-फानन में गोदाम पहुंचे। इसके बाद पंचबा इंटरप्राइजेज उनके ससुर भुनेश्वर प्रसाद साह का है एवं बिजली के थाना एवं फायर ब्रिगेड को सूचना सामान का गोदाम अमित कुमार का दी गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की है। तीनों गोदाम एक-दूसरे से सटे टीम पहुंची लेकिन आग पर काब है। रवि ने कहा कि उसके दो कर्मी पाया नहीं जा सका। उन्होंने कहा गोदाम में ही रहते हैं। रात को कि रात 12:00 बजे से लेकर

आग बुझाने का काम चलता रहा। कई बार वाहन में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन आग नहीं बुझी। आग पर काबू पाने के लिए 10 दमकल वाहनों का सहायता ली गई तब जाकर आग बुझी। रवि ने कहा कि शरूआती जानकारी में आग लगने

चतरा में कोयला ढुलाई में लगे हाडवा में आगजनी

CHATRA: जिले के पिपरवार थाना क्षेत्र में कोयला ढुलाई में लगे हाइवा में आगजनी की घटना को के पीछे टांसपोर्टिंग रोड पर मंगलवार की देर रात यह घटना हुई है। टंडवा एनटीपीसी के कोयला ढलाई वाले हाईवा को आग के हवाले कर दिया फिर किसी नक्सली संगठनों के जरिये अंजाम दिया गया है अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस घटना के बाद ट्रांसपोर्टरों और कोयला व्यवसायियों में दहशत है।



बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ हिंदू संगठनों ने निकाली रैली



पर हो रहे हमलों और आध्यात्मिक नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने रैलियां निकालीं। हिंदू राष्ट्रीय समन्वय समिति (एचआरएसएस) के भाजपा और अन्य संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इसमें विधायक राज सिन्हा नेतत्व में कई संगठनों के लोग हाथों में तख्तियां लिए और बांग्लादेश सरकार के वौक तक मार्च निकाला और वहां लगभग दो घंटे तक प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संस्थापक डॉ . नील माधव दास, इस्कॉन धनबाद से दामोदर प्रभु, विश्व हिंदू परिषद से सुनील कुमार, हिंदू जनजागृतिं समिति से शंभू गवारे और हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति धनबाद के संयोजक डॉ.





नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपते सांसद ढुल्लू महतो

DHANBAD: सांसद ढुल्लू महतो बुधवार को नई दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी से मिले। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से निरसा-गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर की मांग सहित कई मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। मंत्री ने सांसद को आश्वस्त किया कि जल्द ही पहल होगी। इससे पहले सांसद ने लोकसभा में चिरकुंडा में बरकरार नदी पर टू लेन पुल का मुद्दा उठाते हुए जल्द निर्माण कराने की मांग की। सांसद ने कहा कि 2019 में इसका शिलान्यास हुआ था, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। गोविंदपुर व निरसा में जाम लगा रहता है। यह पुल बिहार-बंगाल को जोड़ेगा। सांसद ने ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल से मुलाकात कर डीवीसी के विस्थापितों का मामला उठाया व कार्रवाई की मांग की। सांसद ने कहा कि डीवीसी के विस्थापितों को नौकरी नहीं मिली है। बंगाल के विस्थापितों को ज्यादा

• फोटोन न्यूज

जेल जाने से घबराकर मर्डर केस के दोषी ७० वर्षीय बुजुर्ग ने दे दी जान

जेल जाने से घबराकर मर्डर केस के दोषी बुजुर्ग ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। उसे आज पलामू कोर्ट में सरेंडर करना था। इससे पहले ही उसकी बॉडी बरगद के पेड़ से लटकी मिली। घटनास्थल से एक सीढी, टार्च और एक प्लास्टिक भी मिली है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बुजुर्ग ने आत्महत्या के लिए इन तमाम सामानों का इस्तेमाल किया होगा। जानकारी के अनुसार, जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के शाहद ग्राम निवासी धर्मपाल महतो (70) ने कंदरी वन क्षेत्र में बरगद पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। चरवाहे एवं लकड़ी चुनने वाली महिलाओं ने बुधवार दोपहर एक बजे बरगद के पेड़ में फंदे पर लटके एक बुजुर्ग को देखकर



घटनास्थल पर जुटे लोग

इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी। बाद में शव की पहचान की गई। सूचना मिलने पर लेस्लीगंज पुलिस मौके पर पहुंची एवं फंदे से शव को उतारकर शव को अंत्यपरीक्षण के लिए मेदिनीनगर के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। जानकारी के अनुसार, वर्ष 1997 में ओरिया में अमरेश महतो की हत्या हो गयी थी, जिसमें पूर्व प्रमुख राजनाथ महतो, 74 वर्षीय सिद्धनाथ महतो, 70 वर्षीय मुक्तेश्वर महतो, 65 वर्षीय अनिल को जिला कोर्ट से 20 साल की सजा सुनायी गयी थी। राजनाथ महतो की दो साल पहले ही मौत हो चुकी है। इस फैसले के खिलाफ बचे हुए दोषी उच्च न्यायालय में गए थे, जहां उम्र को देखते हए सभी की सजा आधी कर दी गयी थी। कोर्ट के आदेशानुसर 4 दिसम्बर को सभी दोषियों को सरेंडर करना था। परिजनों के अनुसार, धर्मपाल महतो मंगलवार रात से गायब थे। ज्यादा उम्र होने एवं 10 साल जेल में रहने के डर से धर्मपाल महतो ने खुदकुशी करना उचित समझा। चर्चा है कि कोर्ट के आदेश पर बचे हुए चार में से दो दोषियों ने बुधवार को सरेंडर कर दिया।

हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में धरना



JAMTARA : राष्टीय भारतीय समाज, जामताड़ा की ओर से बुधवार को गांधी चौक के सामने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में धरना दिया गया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की गई। बांग्लादेश में हिंदू पर हिंसा बंद करने, हिंदुओं के मवेशियों की रक्षा करने, बांग्लादेश पुलिस की तानाशाही रोकने आदि को लेकर नारेबाजी की गई। धरना के बाद गांधी चौक से मुख्य बाजार होते हुए चंचल चौक तक सभी ने मार्च निकाला। कार्यक्रम के अंत में शिष्टमंडल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस कार्यक्रम में जामताडा जिले के सभी प्रखंड और गांव से सनातन समाज के

स्कूल से गायब मिले घंटी आधारित शिक्षक, शोकॉज कल्याण बिजय वर्मा ने बुधवार को पलाम् प्रमंडल अंतर्गत लातेहार जिले के राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय

बालक मध्य विद्यालय, छीपादोहर व राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय, हेंदेहास का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मध्य विद्यालय, छीपादोहर में घंटी आधारित शिक्षक रेश्मा कौशर, नंदिकशोर कुमार व विजय दशमी बिना किसी सचना के विद्यालय से अनुपस्थित मिले। उन्होंने इन अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया। इस दौरान अध्यापन के समय कक्षा में पढ़ाने के बजाए कॉपी जांचते नजर आए घंटी आधारित शिक्षक विक्रम कुमार गौरव व अनीस कुजूर को कड़ी चेतावनी देते हुए अध्यापन कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पढाई की मिलने वाली अन्य सुविधाओं से अवधि में विद्यार्थियों को पढ़ाने के

जांच करते उपनिदेशक जाएं। उन्होंने विद्यालय से अनुपस्थित विद्यार्थियों उपस्थिति के लिए उनके अभिभावकों से अविलंब संपर्क स्थापित करते हुए ड्रॉपआउट होने की संभावना से बचाते हुए विद्यालय में उपस्थित कराने एवं उन्हें शिक्षण कार्य से जोड़े रखने का निर्देश दिया। उन्होंने इन विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था की हकीकत को जाना। बच्चों को उपलब्ध होने वाले स्कूल किट (पाठय सामग्री), पोशाक एवं जुतों का भी अवलोकन किया। इसके अलावा विद्यार्थियों को

तिलैया जलाशय में डाले गए मछली के आठ लाख बीज

PHOTON NEWS HAZARIBAG: जिला मत्स्य कार्यालय, हजारीबाग ने बुधवार को तिलैया जलाशय में मत्स्य अंगुलिका (मछली का जीरा या बीज) संचयन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सहायक समाहर्ता लोकेश बारंगे की उपस्थिति में मछली का कुल 8 लाख जीरा डाला गया। लोकेश बारंगे ने केज जलाशय में मछलियों का पालन नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए एक आधुनिक तकनीक है। उन्होंने मत्स्यपालकों के प्रयासों की सराहना की और इस तकनीक को और अधिक प्रोत्साहित करने की बात कही। जिला मत्स्य अधिकारी प्रदीप कुमार ने जानकारी दी कि तिलैया जलाशय में मत्स्य अंगुलिका



मत्स्य पालकों से बात करते सहायक समाहर्ता लोकेश बारंगे

संचयन और केज प्रणाली के माध्यम से मत्स्य उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। इस पहल से न केवल मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। इस दौरान मत्स्य प्रसार पदाधिकारी डॉ. रजनी गुप्ता,

प्रधान लिपिक संजीव कुमार, प्रवीण किस्पोट्टा, जयंत खलखो, मत्स्य पालक संदीप उरांव, राजू निषाद, मो. जसीम, मनोज साव, कल्याण यादव, छोटन भुईयां, संजय कुमार, दीपक कुमार, मुकेश निषाद, मो. मुस्लिम, मुश्ताक मियां

पत्नी गई थी मायके पति ने की खुदकुशी

PALAMU : जिले के रामगढ थाना क्षेत्र के चौपरिया गांव में पत्नी के मायके जाने के बाद घर में अकेले रह रहे पति ने फंदे से लटकर खुदकुशी कर ली। मृतक की पहचान सरेश सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुरेश काफी शराब का सेवन करता था। बिना किसी विवाद के नशे में आत्महत्या कर लेने की है। बुधवार को एमआरएमसीएच में युवक की शव का पोस्टमार्टम किया गया। रामगढ़ के थाना प्रभारी ओम प्रकाश साह ने बताया कि चौपरिया गांव में सुरेश सिंह नामक व्यक्ति के जरिये सुसाइड कर लेने की सचना मिलने पर पुलिस टीम भेजकर शव एमआरएमसीएच में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के समय वह घर पर अकेला था।

अलपिटो पंचायत की मुखिया व पति के विरुद्ध जांच का निर्देश HAZARIBAG : उपायुक्त नैन्सी • मुखिया, तत्कालीन

सहाय ने अलिपटो पंचायत की मुखिया व उनके पति के विरूद्ध जांच करने का निर्देश दिया है। जिला पंचायत राज शाखा हजारीबाग द्वारा आदेश जारी कर बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुगढ़ द्वारा प्राप्त विस्तत प्रतिवेदन के क्रम में ग्राम पंचायत अलिपटो की मुखिया समिता देवी तथा उनके पति धनेश्वर यादव के विरुद्ध मनमाने ढंग से कार्य करने एवं सरकारी दस्तावेजों में गलत तरीके से हस्ताक्षर किए जाने, साथ ही मनरेगा योजना के तहत नियम विरुद्ध कुल 19 योजनाओं का निर्माण कराने के क्रम में संबंधित मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों व वेंडरों पर कुल 27,87,811.68 रुपये सरकारी राशि गबन करने

पंचायत सचिवों एवं अन्य कर्मियों–वेंडरों पर 27,87,811.68 रुपये गबन का आरोप

का आरोप अधिष्ठापित किया इसके साथ ही प्रखंड विकास

पदाधिकारी विष्णुगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अलिपटो के पंचायत भवन में अभिलेख, रोकड़ पंजी, योजना पंजी इत्यादि की चोरी होने संबंधी सूचना प्राप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखंड रांची के कार्यालय ने 15 फरवरी 2019 के आलोक में उक्त संदर्भ में विस्तृत जांच दल गठित किया

पलामू की बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की उपाध्यक्ष विमला कुमारी ने किया सनसनीखेज खुलासा, कहा-

बालिका गृह में चार वर्षों से चल रहा था यौन शोषण का खेल

PHOTON NEWS PALAMU: पलाम् बालिका गृह में बच्चियों से यौन शोषण का मामला सामने आने के बाद इसके संचालक रामप्रताप गुप्ता और महिला काउंसलर प्रियंका कुमारी को जेल भेज दिया गया है। बालिका गृह को सील कर यहां की बच्चियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। सीडब्लूसी और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पर कार्रवाई की गयी है। इस बीच पलामू की बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की उपाध्यक्ष विमला कुमारी ने बुधवार को सनसनीखेज खुलासे करते हुए कहा कि पलामु बालिका गृह में पिछले चार वर्ष से यौन शोषण का खेल चल रहा था। जांच के बाद कार्रवाई के लिए शिकायत की गयी थी, लेकिन पलामू के तत्कालीन डीडीसी एवं डीएसडब्लुओ ने कार्रवाई के नाम



पर केवल कोरम पूरा किया था। इस मामले में दोनों की भूमिका संदेहास्पद है। ऐसे में इन दोनों की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उन्होंने बालिका गृह और कस्तुरबा विद्यालय की निगरानी के लिए स्पेशल कमिटी बनाने की

विमला ने पत्रकारों को बताया कि बालिका गृह को लेकर कई शिकायतें मिली थी। 16 मार्च 2023 को बालिका गृह की जांच की थी। कई गड़बड़ियां पायी गयी। मामले को उठाया, लेकिन पलामू की तत्कालीन समाज कल्याण पदाधिकारी संध्या रानी ने अपने स्तर से जांच कर बालिका गृह को क्लीन चीट दे दी थी, तब तत्कालीन डीसी तक

मामले को पहुंचाया गया। डीसी ने

डीडीसी से जांच रिपोर्ट मांगी, लेकिन डीडीसी ने मामले को रफा दफा कर दिया। जांच के क्रम में डीडीसी ने कुछ कागजात और सीसीटीवी का डीबीआर जब्त किया था। उसकी भी जांच की जाए। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ वहां की वार्डन को हटाने का निर्देश बालिका गृह को दिया गया

विमला ने बताया कि एक बच्ची जिसके दो और नाबालिग भाई-बहन थे। उसे गढवा से रेस्क्यू कर डालटनगंज के दिव्यांग स्कूल में रखा गया था। किसी कारण से स्कूल बंद होने के बाद दोनों बच्ची को बालिका गृह में रखा गया, जब बच्ची बालिग हो गयी तो उसे किसी अंजान व्यक्ति के हाथों शादी के नाम पर पैसे लेकर बेच दिया गया, जबिक कानूनी रूप से अनाथ बच्ची होम में रहते हुए अगर बालिग होती है तो उसके कानूनन अभिभावक एसडीओ या डीडीसी होते हैं, लेकिन इसकी अनदेखी की गयी। विमला ने कई अन्य घटना क्रम पर भी सवाल उठाये और बालिका गृह को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने बताया कि पांच महीने पहले बालिका गृह से दो नाबालिंग संगी बहने फरार हो गयी थीं। दोनों को अघोर आश्रम रोड से बरामद की गयी थी। बड़ी बहन के साथ बालिका गृह में दुराचार हुआ था। छोटी इसकी आइविटनेस थी। दो दिन बाद उसकी मौत हो गयी। मामले को रफा दफा करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिर्गी बता दिया गया। इसकी पुनः जांच होनी चाहिए। विमला कुमारी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन से की है, ताकि घटना की पुनरावृति न हो।

रेलवे यूनियन की मान्यता के लिए पूरे जोन में शुरू हुआ मतदान

दक्षिण पूर्व रेलवे के 76,266 कर्मचारी 90 स्थानों पर करेंगे वोटिंग

पत्नी मायके गयी थी।

AGENCY BOKARO: यूनियन की मान्यता के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के अतंर्गत बोकारो प्रक्षेत्र समेत पूरे जोन में मतदान हो रहा है। बुधवार को सुबह आठ बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। मतदान 4 से 6 दिसंबर तक होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे में स्थायी रूप से कार्यालय व वर्कशॉप में काम करने वाले कर्मचारी चुनाव 4 तथा 5 दिसंबर को मतदान करेंगे, जबिक रनिंग स्टाफ 6 दिसंबर को भी मतदान कर सकेंगे। वहीं, मतगणना की तिथि 12 दिसंबर तय की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे में कुल 76,266 वोटर हैं। इस जोन में 90 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 26 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। पिछले चुनाव में दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस पहले तथा मेंस यूनियन दूसरे नंबर पर रही थी। वैसे दक्षिण पूर्व रेलवे मजदूर



मतदान पदाधिकारी से पर्ची लेते वोटर

संघ ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। मतदान को लेकर मेंस यूनियन, मेंस कांग्रेस व डीपीआरएमएस के कार्यकर्ता पोलिंग बुथ पर तैनात हैं। वे मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आद्रा रेल मंडल में 75 सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे में 7 यूनियन मैदान में हैं। इनमें ऑल इंडिया रेलवे मेंटेनर यूनियन, दक्षिण पूर्व रेलवे

कहां कितने वोटर

6,972

खडगपुर वर्कशॉप 6,878











CITY

THE PH©TON NEWS 03 www.thephotonnews.com Thursday 05 December 2007 Thursday, 05 December 2024

BRIEF NEWS चीफ जस्टिस के पिता के श्राद्धकर्म में शामिल हुए सीएम, दी श्रद्धांजलि



RANCHI: बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव के दिवंगत पिता और सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस एम जगन्नाथ राव के श्राद्धकर्म में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरांग बुरु दिवगंत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुःख की घड़ी सहन करने की शक्ति दें। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर शोषकों और अत्याचारियों के खिलाफ विद्रोह करने वाले, जल-जंगल-जमीन के रक्षक, महान आदिवासी योद्धा जननायक टंट्या भील की शहादत दिवस पर उन्हें याद किया। साथ ही अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के प्रतीक देश के वीर जांबाज नौ सैनिकों और उनके परिवारजनों समेत समस्त देशवासियों को भारतीय नौसेना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।

देवेंद्र फडणवीस को बाबूलाल मरांडी ने दी बधार्ड

RANCHI: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबुलाल मरांडी ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में फडणवीस महाराष्ट्र को विकास एवं उन्नित के शिखर पर ले जाएंगे। बधाई शुभकामनाएं देने वालों में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉ रविंद्र कुमार राय, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि शामिल हैं।

'मंईयां सम्मान योजना में बरती जा रही लापरवाही

RANCHI: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाब्लाल मरांडी ने मंईयां सम्मान योजना में व्याप्त



मंईयां योजना के भुगतान में भी भारी लापरवाही बरती जा रही है। मरांडी ने कहा कि पिछले दो दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद कर रहा हं। इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडीह, जगदीशपुर सहित एक दर्जन से भी ज्यादा अन्य गांवों की अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने कहा कि वे मंईयां सम्मान योजना के लाभ से वे अब तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का

12 से अधिक दुकानें हुईं राख, फायर ब्रिगेड ने पाया काब्र

लालजी हीरजी रोड में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग

बधवार को राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हीरजी रोड में भीषण आग लग गई। आग एक कॉमर्शियल भवन में लगी। आगजनी की वजह से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लालजी हीरजी रोड घनी आबादी क्षेत्र है। ऐसे में जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया तब तक भय का माहौल बना रहा। हालांकि सचना मिलते ही फायर ब्रिगेड पहुंची और घंटे भर से अधिक की मशक्कत के बाद स्थिति नियंत्रण में ले लाया।

इस आगजनी में विभिन्न तरह की 12 से अधिक दकानें जल कर राख हो गई हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहीं पास में बिजली का पोल भी है। ऐसे में आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और तेजी से फैल गई। इलाके में प्लाईवड की दकानें ज्यादा हैं इस वजह से लोगों की सांसें घंटे भर अटकी रही। उसी रास्ते मारवाड़ी कॉलेज के लिए स्टडेंटस भी आते

PHOTON NEWS RANCHI:

रांची विधायक सीपी सिंह ने सीएम

हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर

पलामु के बालिका गृह शोषण

मामले में कार्रवाई की मांग की है।

सिंह ने पत्र में कहा है, पलामू

बालिका गृह में घटी घटनाओं ने

झारखंड के हर नागरिक को

झकझोर कर रख दिया है। यह

शर्मनाक और अमानवीय कृत्य

राज्य की बाल संरक्षण तंत्र पर एक

गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

समाचार पत्रों के अनुसार पलाम्

सदर एसडीएम अध्यक्षता में गठित

समिति की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है

कि सुपरिटेंडेंट ने महिला काउंसलर

की मदद से बच्चियों के साथ

पिछले 3 वर्षों से लगातार शारीरिक

ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित बिरसा

जु के पास 22 नवंबर की शाम दो

युवकों को गोली मारी गयी थी।

गोली बारी की घटना की साजिश

जेल में बंद अपराधी सुजीत सिन्हा

के द्वारा रची गई थी। एसएसपी

चंदन सिन्हा के निर्देश पर गठित

पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते

हए घटना में शामिल कांके थाना

क्षेत्र के रहने वाला जिशान शेख

नाम का अपराधी को गिरफ्तार

किया गया। गिरफ्तार अपराधी का

पर्व से आपराधिक इतिहास रहा

है।एसएसपी चंदन सिन्हा ने

बुधवार की शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर

यह जानकारी दी। घटना की जांच

के दौरान पुलिस को जानकारी

मिली है कि जमीन कारोबारी

संजीव जायसवाल से सुजीत



जाते रहते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह मद्रास कैफे के बाद बगल वाली है। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान होने का अनमान लगाया गया है। बधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की

पूरे मामले में सीडब्ल्युसी (बाल

कल्याण समिति) और अन्य

जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका

मिलीभगत को दशार्ती है। यह

केवल एक आपराधिक मामला

नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए

ने रची थी साजिश, अपराधी गिरफ्तार

गंभीर लापरवाही और

बालिका गृह में शोषण मामले

में हो कडी कार्रवाई : सीपी सिह

सूचना मिली दुकानदारों में भगदड़ मच गई। जितनी दुकानें जली उसमें सबसे अधिक नकसान बैटरी और इन्वर्टर की दुकानों का होने का बताया जा रहा है। आगजनी को नियंत्रित किए जाने के बाद इलाके

पांच विवि को जवाब के साथ एक हजार रुपये जुर्माना देने

दिसंबर को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन विश्वविद्यालयों ने के साथ 10 हजार रुपये जुमार्ना भी जमा करे तब ही उनका जवाब दाखिल होगा। यह याचिका अंजनी कुमार पांडे ने दाखिल की है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय समेत राज्य के पांच विश्वविद्यालयों को प्रतिवादी कि कुलपति नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का पालन नहीं किया गया है।

का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश RANCHI: झारखंड के 5

विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई 18 अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, वे दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करें। साथ ही जवाब बनाया है। याचिकाकर्ता का कहना है

ओरमांझी गोलीकांड : सुजीत सिन्हा मुख्यमंत्री की पहल पर मलेशिया से स्वदेश लौटेंगे

RANCHI: झारखंड के कामगारों और श्रमिकों के प्रति संवेदनशील मख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की पहल पर एक बार फिर विदेश में फंसे 50 राज्य के कामगारों को वापस उनके घर और गांव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी कामगार 11 से 18 दिसंबर तक घर लौट आयेंगे। इसके लिए जरूरी कागजाती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।झारखंडी कामगारों के की इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत 70 कामगारों के फंसे होने की शिकायत राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को 24 सितंबर को प्राप्त हुई। बताया गया कि कामगारों का चार महीने से वेतन लंबित है। साथ ही उन्हें भोजन की अनुपलब्धता और वतन वापसी की समस्याएं सामने आ रहीं हैं।

झारखंड के 50 कामगार

लीडमास्टर

अंडर-14 क्रिकेट दूर्नामेंट में कैराली स्कूल ने विवेकानंद

विद्या मंदिर को हराया RANCHI : आडीसीए की ओर से आयोजित अंडर-14 क्रिकेट ट्रनामेंट में बुधवार को एक रोमांचक मुकाबला हुआ। इसमें कैराली स्कूल ने विवेकानंद विद्या मंदिर को केवल 2 रन से हरा दिया। इस मैच में कैराली स्कूल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 94 रन बनाए, जबकि विवेकानंद विद्या मंदिर की टीम 92 रन पर सिमट गई। कैराली स्कूल की ओर से शानदार प्रदर्शन करते हुए अद्योत सिन्हा ने 3 विकेट लिए, वहीं देव सिंह ने भी 3 विकेट हासिल किए। दोनों गेंदबाजों की सटीक और आक्रामक गेंदबाजी ने विवेकानंद विद्या मंदिर के बल्लेबाजों को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी टीम 92 रन पर ऑल-आउट हो गई। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अद्योत सिन्हा को 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला।

डायन के नाम पर प्रताड़ित हो रही थी महिला, पुलिस की पहल के बाद गांव में रहने को मिला

झारखंड में तमाम जागरूकता अभियान के बावजूद डायन बिसाही का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला राजधानी रांची से 50 किलोमीटर दुर चान्हो प्रखंड के चुटीओ गांव का है। इस गांव में डायन बिसाही के आरोप में एक महिला का गांव वालों ने हुक्का पानी बंद कर दिया। सबसे हैरत की बात यह है कि महिला ने भी माना है कि वो झाड़ फूक करती है। रांची का चान्हो इलाका डायन बिसाही को लेकर अक्सर विवादों में रहता है। एक बार फिर से चान्हो प्रखंड के चुटीओ गांव में डायन बता कर एक 50 वर्षीय महिला के साथ प्रताड़ना का मामला सामने आया है। मामले को लेकर पीडित महिला के द्वारा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। महिला ने अपने आवेदन में लिखा है कि गांव में अलग-अलग कारण से तीन से चार लोगों की मौत हो गई थी। गांव वालों को लगा कि डायन बिसाही के कारण ही ऐसा हो रहा है। मामले को लेकर पूरे गांव ने गोलबंद होकर एक ओझा को बुलाया। ओझा ने महिला को भरी सभा के दौरान ही डायन करार दिया। उसके बाद से ही गांव वालों ने उसका हुक्का पानी बंद

कर दिया। महिला के घर से गांव



बताया कि डायन के नाम पर प्रताडना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तय है। महिला को प्रताड़ित करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। एसएसपी के अनुसार फिलहाल गांव में पूरी तरह से शांति है। पीडित महिला के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वालों ने बिजली और पानी का

कनेक्शन तक काट दिया। परेशान होकर पीड़ित महिला अपने मायके चली गई। लेकिन जब वह धान कटनी के लिए अपने गांव वापस आई तो उसे धान भी नहीं काटने दिया गया। मामला सामने आने के बाद रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने नरकोपी थानेदार को मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए।

हरमू से कडरू रेडिशन ब्लू तक प्रस्तावित फ्लॉईओवर के लिए नहीं मिला कंसलटेंट

के दुकानदार हुई नुकसान का

जायजा ले रहे हैं। मौके पर पलिस

भी मौजूद है। कुछ देर के लिए

अफरा-तफरी मचने की वजह से

ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। अब

धीरे-धीरे सब कुछ सामान्य हो रहा

हरम् से कडरू रेडिशन ब्लू तक फ्लाईओवर का डीपीआर बनाने के लिए कंसलटेंट नहीं मिल रहा है। पथ निर्माण विभाग ने लगातार तीसरी बार कंसलटेंट चयन के लिए बिड जारी किया हैं, इंजीनियरों ने बताया की यह प्रयास हो रहा की इस महत्वपूर्ण फ्लाइओवर की योजना को जल्द ही मंजूरी दिलायी जाये पर इसके पहले विस्तृत डीपीआर जरूरी है। हरम् के विद्यानगर से यह फ्लाईओवर बनाने की योजना है. जिसे सहजानंद चौक से रात रोड तक बन रहे फ्लाईओवर से कनेक्ट



ने हरम् से कडरू तक ब्रिज बनाने के लिए सर्वे का काम पुरा करने के बाद ही इस योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। हरमू रोड में सहजानंद चौक से रातू रोड होते हुए कांके रोड जज कॉलोनी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण के

है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय

के मुताबिक सूचना मिलते ही

पुलिस एक्टिव हुई। फायर ब्रिगेड

को बुलाया गया। अब मामले की

जांच के बाद ही यह ख़ुलासा हो

रेट पर निविदा भरेगी। पथ निर्माण विभाग ने संवेदकों के भरे बिड की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार स्त्र पर इसे लाया जायेगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद ही इस पर आगे बढ़ा जायेगा। बेड़ो-खूंटी रोड दो लेन बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग

मंजूरी दी है और रैयतों से जमीन अधिग्रहण के लिए नोटिस जारी किया है। नेशनल हाइवे 143एजी के दो लेन, पेब्ड़ सोल्डर रोड बनाया जायेगा। करीब 37 किमी यह रोड बेड़ो से खूंटी जाती है। इसके चौड़ीकरण व पुननिर्माण से पूरे इलाके में काफी फायदा होगा। अभी यह रोड सिंगल है, जिसमें रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन होता है। अक्सर कई जगह सड़क संकरी होने पर वाहन फंसते हैं। खंटी जिला भ-अर्जन पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण के पूर्व सारे पक्षों की सुनवाई पूरी कर उचित मुआवजा भगतान करने

यातायात नियमों को लेकर प्रशासन सख्त, काट जा रह हजारा चालान

राजधानी रांची में यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। टैफिक रूल तोडने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। स्थिति ये है कि मिनटों में ही ई-चालान काटा जा रहा है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने राजधानीवासियों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का सावधानीपर्वक पालन करें और दुर्घटनाओं से बचें। बता दें कि हर लोगों का चालान नियमों का उल्लंघन करने पर काटा जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर न केवल जान का खतरा है। रांची में ऑटोमैटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का संचालन किया जा रहा है। इसके

कंटोल एंड कमांड सेंटर से हो रही निगरानी

🗕 रांची स्मार्ट सिटी के



तहत सड़क पर मौजूद विभिन्न उपकरण हर वाहन की निगरानी करते हैं। यदि कोई गति सीमा से अधिक गति से वाहन चला रहा है या रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा है, हेलमेट नहीं पहन रहा है या रेड लाइट जंप कर रहा है, तो उसका चालान कटना तय है। रांची में दो

अधिकारियों ने की लोगो से अपील, नियमों का सावधानीपूर्वक करें पालन

पहिया वाहन चालकों का चालान मुख्य रूप से हेलमेट न पहनने पर कटता है। वर्तमान में हर दिन 3,000 से 5,000 ई-चालान काटे जा रहे हैं। ई-चालान सिस्टम रिंग रोड से शहर में सभी एंट्री और एग्जिट मार्गों पर लागू है। महात्मा गांधी मार्ग, हरमू बाईपास, हिनू-डोरंडा, बिरसा चौक से धुर्वा, कडरू-अरगोड़ा, कटहल मोड़, रेडियम रोड, बरियातू, कांके रोड, रातू रोड, बिरसा चौक से खूंटी रोड, नामकुम, लालपुर, कांटाटोली-कोकर, थड़पखना, चुटिया सहित रिंग रोड के भीतर शहर के अधिकांश इलाकों में ई-चालान

कल होगा जलसा-ए-दस्तारबंदी और शैक्षिक प्रदर्शन : कारी इरफानुल्लाह

PHOTON NEWS RANCHI: शुक्रवार को जलसा-ए-दस्तारबंदी

व शैक्षणिक प्रदर्शन पर एक भव्य कार्यक्रम होगा। बाद नमाज ईशा मकतब दीनियात अल-बिकयात-उल-सालेहात हाजी मतलूब गली, नाला रोड हिंदपीढी रांची में आयोजन होगा। अध्यक्षता हजरत मौलाना कारी मोहम्मद एहसान कडरू करेंगे। मुख्य अतिथि यूपी के शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद मुहम्मद अफ्फान साहब मंसूरपुरी करेंगे। संचालन बिहार के पूर्णिया के हजरत मौलाना मुहम्मद तनवीर जकी करेंगे। इनके अलावा हजरत कारी मुहम्मद अंसारुल्लाह कासमी, मुफ्ती मुहम्मद इमरान नदवी, मौलाना शफीउल्लाह अल कासिमी, कारी मुहम्मद इसराइल कडरू वह अन्य



लोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह जानकारी नजीम मकतब कारी इरफानुल्लाह ने बुधवार को दी। बताया कि जलसे और तालीमी प्रदर्शन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस जलसे में 6 हुफ्फाज के सिरो पर दस्तार ए फजीलत बांधी जाएगी। उन्होंने सभी से इस जलसे में भाग लेने और हुफ्फाज-ए-कराम को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया।

दूर होगी असुविधा : कारगर तरीके से डोर-टू-डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए बनाया मुकम्मल प्लान

शहर के सफाई अभियान को नगर निगम ने किया तेज

निगरानी के लिए घरों के

बाहर लगाया जाएगा

आरएफआईडी

सिन्हा गिरोह ने रंगदारी मांगी थी।

जमीन कारोबारी ने ना तो रंगदारी

दी और ना ही रंगदारी मांगे जाने के

संबंध में पुलिस को बताया।

रंगदारी नहीं देने को लेकर सिन्हा

कारोबारी संजीव जायसवाल को

गोली मारने आये थे। लेकिन

के अपराधी जमीन

कोई लाभ नहीं मिल पाया है।

PHOTON NEWS RANCHI: शहर में साफ-सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के अभियान को रांची नगर निगम ने तेज कर दिया है। शहर को चकाचक बनाने के लिए मुकम्मल प्लान बनाया गया है। इसके तहत नई एजेंसी स्वच्छता कॉरपोरेशन का सेलेक्शन कर लिया गया है। यह एजेंसी अब हर दिन लोगों के घरों से निकलने वाला कचरा कलेक्ट कर ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाएगी। यह कार्य शहर में सफाई और सॉलिड वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से एजेंसी को सहयोग करने की अपील की है। नगर

🗕 काम शुरू करने से पहले एजेंसी करेगी 53 वार्डों में घरों का सर्वे



निगम ने इस पहल को सफल बनाने के लिए शहर के सभी स्वच्छता • अधिकारियों ने लोगों से की एजेंसी को सहयोग करने की अपील

आजाद और जावेद अंसारी दोनों

बीच में आ गये। जिसकी वजह से

दोनों को गोली लग गयी। इस

मामले को लेकर ओरमांझी थाना

में सुजीत सिन्हा और उसके गिरोह

के अपराधी खिलाफ एफआईआर

एकत्रित की जाएगी घरों की जानकारी

बता दें कि स्वच्छता कॉपोर्रेशन को प्राईमरी कलेक्शन कार्य के तहत नगर निगम के सभी 53 वार्डों में प्रत्येक हाउसहोल्ड का सर्वे करना है। इसके बाद एजेंसी सभी घरों व प्रतिष्ठानों के बाहर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटीफिकेशन (आरएफआईडी) डिवाइस इंस्टॉल करेगी। इस प्रक्रिया के दौरान हर घर से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी और प्रत्येक घर के अपशिष्ट को डिवाइस के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा।

प्रतिनिधियों को पूरी तरह से सहयोग प्रदान करें। नगर निगम ने

आरएफआईडी इंस्टॉल करने की प्रक्रिया समयबद्ध और सटीक तरीके से पूरी हो सके। इसके साथ ही निगम ने यह भी कहा कि इस कार्य के दौरान अगर किसी नागरिक को कोई असुविधा होती है तो वे नगर निगम से संपर्क कर सकते हैं। नगर निगम के अधिकारियों की मानें तो इस कदम से शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार होगा। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और समय पर वेस्ट कलेक्शन होगा। इसके साथ ही शहर को स्वच्छ और हरित बनाए रखने में मदद मिलेगी।

इस अभियान के तहत नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की है, सर्वेक्षण

समाचार सार

आदिवासी छात्र संघ के जिलाध्यक्ष बने अजित मुर्म् GHATSILA: आदिवासी छात्र संघ के जिला महासचिव लखाई मुर्मू व कोल्हान प्रभारी सुदाम हेंब्रम के संयुक्त नेतृत्व में बुधवार को जिला समिति



का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अजित कुमार मुर्मू को जिलाध्यक्ष बनाया गया महासचिव व मीडिया प्रभारी लखाई मुर्मू, कोषाध्यक्ष सुपाई सिंह हांसदा, उपाध्यक्ष रेशमा

मांडी, जिला प्रभारी सपाई, सिंह हांसदा व कोल्हान प्रभारी सदाम हेम्ब्रम, जबिक अनुमंडल कमेटी में अध्यक्ष दुर्योधन मुर्मू, कोषाध्यक्ष रायसेन हेम्ब्रम, उपाध्यक्ष तुलसी मार्डी व मीडिया प्रभारी संजू सोरेन को बनाया गया है। बाबा तिलका मांझी मेमोरियल क्लब, फूलडुंगरी में हुई बैठक घाटशिला कॉलेज के स्नातक उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं व इंटर कॉलेज चैंपियन खो-खो एवं कबड्डी के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।

तांतनगर में लगा विधिक जागरूकता शिविर

CHAIBASA: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय



विधिक सेवा प्राधिकार की

न्यायाधीश मोहम्मद शाकिर के निर्देश पर ग्रामीणों के बीच विधान से समाधान कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को कानूनी व लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी गई

एआईडीएसओ ने कुलसचिव को सौंपा ज्ञापन



कमेटी का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को चाईबासा गया था, जहां उन्होंने कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि सत्र 2022-24 के बीएड के विद्यार्थियों को पीजी में नामांकन करने का मौका दिया जाए। ओल्ड कोर्स के सेमेस्टर प्रथम और तीसरे के बैकलॉग स्टूडेंट की यथाशीघ्र परीक्षाएं आयोजित की जाएं। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक जेनेरिक पेपर की परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई हैं, परीक्षा की तिथि अविलंब निर्धारित की जाए। बीएड में दूसरे मैथ पेपर की परीक्षा ली जाए। पीएचडी परीक्षा-2022 की लिखित परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को हुई थी, उसका रिजल्ट जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि इन मांगों पर कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक ने जल्द परीक्षा आयोजित करने की बात कही। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष रिंकी बांसियार, राज्य सचिव मंडली सदस्य शुभम झा, सगुण हांसदा, जितन दास व अमित कुमार शामिल थे।

मेघाहातुबुरु ने यंग झारखंड को हराया

CHAIBASA: पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में



उद्घाटन मुकाबले में गत वर्ष

ए-डिवीजन में खेल रहे मेघाहातुबुरू क्रिकेट क्लब ने तीन विकेट से पराजित कर न सिर्फ पूरे चार अंक बटोरे, बल्कि प्रतियोगिता में भारी उलटफेर भी कर दिया। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस मेघाहातुबुरू क्रिकेट क्लब के कप्तान ने जीता तथा विपक्षी टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया।

फैंसी ड़ेस में नन्हे छात्रों ने बटोरी तालियां



छात्रों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता हुई, जिसमें बच्चों ने कई तरह के चरित्र की वेशभूषा में खुब तालियां बटोरीं। निर्णायक मंडल में शशिबाला व प्रीति कुमारी शामिल थीं। उन्होंने बच्चों

को प्रस्तुति के लिए सराहा। यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रेक्षागृह में हुआ।

श्रमिकों ने उठाया खेलकूद व वनभोज का आनंद



अपने श्रमिकों के लिए खेलकृद व वनभोज का आयोजन किया। सोनुआ रोड, रामचंद्रपुर में हुए कार्यक्रम में महिलाओं ने म्यूजिकल चेयर, बैलून फोड़, मटका फोड़, रस्सा

टान, ज्ता रेस, बोरा रेस, मोमबत्ती रेस, जबिक पुरुषों ने ड्राम शूटआउट, गोलकीपिंग, बास्केट बॉल, रस्सा टान, जूता रेस, ड्राम के अंदर बॉल फेंकना, रिंग, मोमबत्ती रेस आदि खेल का आनंद लिया। इस दौरान मुख्य अतिथि सीआरपीएफ के सेकंडइन कमांडेंट पवन कुमार भी

धालभूमगढ़ में शुरू हुआ विजय बोस क्रिकेट दूनार्मेंट

GHATSILA: झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 17वां



विजय बोस क्रिकेट ट्नार्मेंट का उद्घाटन मैच बुधवार को धालभूमगढ़ की मेजबानी में नरसिंहगढ़ हाई स्कूल प्लस टू मैदान में कसीदा बनाम धालभूमगढ़ के बीच में खेला गया। मैच का उद्घाटन

मुख्य अतिथि मुखिया विलासी सिंह, पूर्व मुखिया पूर्ण चंद्र सिंह, प्लस टू स्कूल के प्रिंसिपल निर्मलेंदु, जीएससीए के लेवल-1 कोच अर्जुन सिंह और शकील अहमद उपस्थित थे। खेल के आरंभ में अमिताभ चौधरी व विजय बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का

गायत्री परिवार का प्रांतीय शिविर 27 से 29 तक

JAMSHEDPUR: नारी सशक्तीकरण एवं युवा जागरण शिविर 27-29 दिसंबर को होगा। इसकी तैयारी के क्रम में बुधवार को गायत्री ज्ञान मंदिर, भालुबासा में गोष्ठी हुई, जिसमें सभी विभागों के प्रभारी ने अपने-अपने विभागों की तैयारी के बारे में बताया। कार्यक्रम की अध्यक्ष जसबीर कौर ने बताया कि टाटानगर में होने वाले शिविर में पूरे झारखंड प्रांत से 1500 भाई-बहन उपस्थित होंगे। गोष्ठी का संचालन प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड के समन्वयक संतोष कुमार राय के साथ भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ झारखंड के प्रभारी ताराचंद अग्रवाल ने किया।

आइसक्रीम कारोबारी के घर पर फायरिंग करने वाले ३ गिरफ्तार

आरोपी रोहित लोहार पहले था फैक्ट्री का कर्मचारी

छोटागोविंदपुर में 17 नवंबर की रात बाइक से आए तीन अपराधियों ने प्रकाशनगर निवासी नवीन सिंह के घर के बाहर हवाई फायरिंग की थी। इस मामले में पलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाशनगर निवासी रोहित लोहार उर्फ गॉड बाबा, गौरव गोस्वामी और अमन महतो शामिल हैं। पुलिस ने अपराधियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कट्टा भी बरामद किया है। बुधवार को एसएसपी किशोर कौशल ने मामले का खुलासा किया। एसएसपी ने बताया कि आरोपी रोहित लोहार नवीन सिंह के यहां काम करता था। पूर्व में नवीन सिंह ने उसे चोरी करते पकड़ा था और पुलिस को सौंप दिया था। हालांकि. इस संबंध में थाने में



मामले की जानकारी देते एसएसपी किशोर कौशल व अन्य

किसी तरह की लिखित शिकायत नहीं की गई थी। इसके बाद थाने से रोहित को छोड़ दिया गया था। इसी बात को लेकर रोहित ने अपने साथियों के साथ नवीन सिंह के घर

के आदिवासी घरों, स्कूलों को

पुलिस और अर्द्ध सैनिक वालों द्वारा

जबरदस्ती कब्जा कर कैंप स्थापित

किया गया है। इसके खिलाफ

जनप्रतिरोध आंदोलन को तेज करने

व केंद्र सरकार के वन संरक्षण

कानून के खिलाफ जल, जंगल,

जमीन पर जनता का अधिकार

कायम करने के लिए जन आंदोलन

तेज करना है। इस तरह के बैनर-

पोस्टर मनोहरपुर के शहरी क्षेत्र से

सटे बस स्टैंड, मनीपुर, कुदासाईं,

प्रनापानी, मेदासाई, बच्चमगुटू

समेत अन्य गांवों की सड़कों पर

काफी संख्या में बिखरे पड़े हैं।

माओवादियों ने की पोस्टरबाजी

मना रहे क्रांतिकारी सप्ताह

सारंडाकोत्स्रत सहित विशित्त्र बत्र प्रसेत्रों के अस्त्रिश दूरों-स्कूलों कोजबरद्दस्ती कृजा कर पुलिस वजह रौतिक बेलों दूरारा स्थापित कैम्पों के खिलापाजन

पूर्वी रीजनल कमान, भाकपा [माओवार्दी]

प्रतिरोध आंद्रोलत को तेज करें।

CHAKRADHARPUR : पश्चिमी

सिंहभूम में नक्सली संगठन

भाकपा-माओवादी ने मंगलवार रात

मनोहरपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न

इलाकों में जमकर पोस्टरबाजी

की। गांवों के रास्तों को बैनर-

पोस्टर से भर दिया है। इसमें कहा

गया है कि भाकपा-माओवादी 2-8

दिसंबर तक पीएलजीए (पीपुल्स

लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) की

24वीं वर्षगांठ को क्रांतिकारी

सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है।

संगठन के पर्वी रीजनल कमान द्वारा

जारी बैनर-पोस्टर में कहा गया है

कि सारंडा समेत विभिन्न वन क्षेत्रों

एसएसपी ने बताया कि रोहित लोहार समेत तीनों आरोपी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। रोहित के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं, जबिक गौरवें के खिलाफ तीन मामले दर्ज हैं। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि तीनों के पुराने मामले भी खंगाले जा रहे हैं। इनसे जुड़े कई अपराध की सूचना

पूर्व में भी जेल जा चुके हैं सभी आरोपी

लोधी क्षत्रिय महासभा ने मनाई स्वामी

ब्रह्मानंद की जयंती



भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा ने बुधवार को शिक्षा के सागर स्वामी ब्रह्मानंद की 130वीं जयंती मनाई। इस मौके पर संस्था ने बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद ओल्ड एज होम में आश्रम के बुजुर्गों के साथ दोपहर का भोजन किया। इस कार्यक्रम सफल बनाने में राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार सिंह, किशनलाल वर्मा, केंद्रीय महामंत्री ज्वाला सिंह, संगठन सचिव हृदयनंद वर्मा, उपाध्यक्ष भूवनेश्वर लोधी, सचिव अवध लोधी, कोषाध्यक्ष शिवकुमार, युवा अध्यक्ष कमल प्रसाद, युवा महामंत्री परमेश्वर लोधी, महिला महासचिव लक्ष्मी देवी, कार्यकारिणी सदस्य सुरेश लोधी, जमुना लोधी, मेघा लोधी, सीमा

समिति का किया गया पुनर्गटन

बासाडेरा गांव में वन अधिकार



ग्रामसभा की बैठक में शामिल महिला व पुरुष

GHATSILA: बासाडेरा गांव में वन अधिकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष भजोधरी सिंह, सचिव रुपचांद सिंह व सदस्य सिमन्त सिंह, धरनी सिंह, गुनाराम सिंह, अजय सबर, दुलारी सिंह, रेवती सिंह, मिलन सिंह आदि शामिल हैं। परंपरागत स्वशासन व्यवस्था पूर्वी सिंहभूम माझी पारगाना माहाल घाटशिला प्रखंड अध्यक्ष सह देश विचार सचिव बाहादुर सोरेन व महासचिव सुधीर कुमार सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को बासाडेरा गांव में ग्राम

प्रधान गौर सिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की गई। अनुसूचित जनजाति व अन्य परंपरागत वन (वन अधिकारों की अधिनियम-2006, नियम-2008 व संशोधित नियम-2012 के सदर्भ में विचार विमर्श किया गया। बाहादुर सोरेन ने कहा कि काफी चिंता का विषय है कि 15 वर्ष बाद भी वन अधिकार कानून धरातल पर उतर नहीं सका है। इसकी वजह से हमारे आदिवासी-मूलवासी अधिकारों से वंचित हैं।

खलिहान में रखे धान के ढेर में लगी आग, लाखों की क्षति

CHAKRADHARPUR

चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड-2 स्थित कुदलीबाड़ी में खिलहान में रखे धान की ढेर में आग लग गई, जिससे तीन किसानों को लाखों रुपये से अधिक का नकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार, कुदलीबाड़ी निवासी किसान लोंबा हांसदा, तीरबाबू हांसदा और बिशू हांसदा बुधवार को धान काटने खेत में गए थे। तभी दोपहर करीब एक बजे खलिहान में रखे धान में आग

लगने की सूचना मिली। आग कैसे लगी, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने नजदीक स्थित संजय नदी से बाल्टी-डेगची आदि से पानी लाकर आग बुझाई। पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश जेना ने थाना को सूचित कर दमकल भेजने को कहा। दमकल भी पहुंचा, लेकिन रास्ता नहीं होने के कारण खलिहान से दूर रह गया। तब तक स्थानीय लोग आग बुझाने में सफल हो चुके थे। किसानों ने बताया कि 8 टैक्टर धान जल गए।

खड़गपुर रेल मंडल के 2200 कर्मचारी कर रहे मतदान



GHATSILA: भारतीय रेलवे में ट्रेड यूनियनों की मान्यता के लिए बुधवार को घाटशिला रेलवे स्टेशन पर मतदान शुरू हुआ। मतदान को लेकर रेलवे के विभिन्न ट्रेड यूनियन द्वारा अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र से दूर यूनियन के प्रतिनिधि मतदाता सूची लेकर बैठे नजर आए। चुनाव के संबंध में पुछे जाने पर इंटक के गिधनी शाखा सचिव डी. त्रिनाथ ने बताया कि खड़गपुर डिवीजन से 22000 रेल कर्मी मतदाता हैं। तीन दिन तक मतदान चलेगा। रनिंग स्टाफ के मतदान को लेकर शुक्रवार तक का समय रखा गया है।

राष्ट्रपति से मिलीं जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू दास

PHOTON NEWS JSR:

जमशेदपर पर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने बुधवार को नौसेना दिवस के मौके पर पुरी राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने राष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ भेंटकर आशीर्वाद व मार्गदर्शन मांगा। राष्ट्रपति ने उन्हें उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य की शुभकामना दी। इस दौरान उनके साथ उनके पति ललित दास भी मौजद रहे। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति ओड़िशा के पांच दिवसीय दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान वे परी में नौसेना दिवस समारोह सहित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। इससे पूर्व विधायक पूर्णिमा साहू ने पुरीधाम में महाप्रभु जगन्नाथ का सपरिवार दर्शन



पुरी में राष्ट्रपति के साथ विधायक पूर्णिमा दास व उनके पति ललित दास

किया। इस दौरान ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास व उनकी पत्नी रुक्मिणी दास भी थीं। विधायक ने महाप्रभु से जमशेदपुरवासियों की खुशहाली, सुख-समृद्धि और क्षेत्र की प्रगति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जमशेदपर की जनता ने जो अपार स्नेह और आशीर्वाद उन्हें दिया है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहुंगी। महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूं कि वे मुझे जनता की सेवा में निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने की शक्ति प्रदान करें।

पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन से मिले सांसद



JAMSHEDPUR: सांसद बिद्युत बरण महतो बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन हंसराज अहीर से मिले। सांसद ने उनसे सुवर्ण विणक जाति को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग रखी। ज्ञापन सौंपते हुए सांसद ने कहा कि झारखंड सरकार ने सुवर्ण वणिक समाज सहित 36 जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने की अनुशंसा की है। इन सबको यथाशीघ्र केंद्रीय सूची में शामिल किया जाए, ताकि इन जातियों को तमाम लाभ मिल सके। सांसद ने बताया कि चेयरमैन ने आश्वस्त किया कि वे इस दिशा में यथाशीध्र कदम उठाएंगे। चेयरमैन ने सांसद से कहा कि वे झारखंड आएंगे।

पूर्व सैनिकों ने नौसेना के शहीदों को दी श्रद्धांजलि



गोलमुरी में जुटे पूर्व सैनिक JAMSHEDPUR : अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, जमशेदपुर के बैनर तले गोलमुरी स्थित शहीद स्मारक पर बुधवार को नौसेना दिवस मनाया गया। इस दौरान नौसेना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन संगठन के अध्यक्ष विनय कुमार यादव ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। पूर्व नौसैनिक सुखविंदर सिंह ने 1971 के युद्ध में नेवी की अचूक रणनीति और अपूर्व पराक्रम को

विस्तार से बताया। पूर्व नौसैनिक राजेश कुमार पांडे, नवेंद्र गांगुली व शशिभूषण सिंह ने भी अपने विचार साझा किए। पेटी ऑफिसर जयप्रकाश ने युद्ध के दौरान आइएनएस वीर निफ्ट और निर्घट के साथ राजपूत और अक्षय जैसे जहाजों और उनकी तकनीकी विशेषताओं का भी जिक्र किया। इसके बाद 1971 के युद्ध में आइएनएस खुकरी के 176 नौसैनिकों की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

क्यूआर कोड की भी होगी शुरुआत, स्कैन कर शिकायत करने की होगी सुविधा

किसी भी समस्या के लिए पुलिस को डायल करें 112

ROHIT KUMAR @ JSR

पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब डायल 112 को क्युआर कोड से जोड़ने की शुरूआत की जा रही है। पहले चरण में इस क्युआर कोड को जिले के शहरी क्षेत्र में 4000 स्थान और ग्रामीण क्षेत्र में 1000 से अधिक ऑटो, बस, दर्जनों एटीएम और स्कूल-कॉलेजों में लगाया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे जगहों को भी चिह्नित किया गया है, जहां इस क्युआर कोड को लगाया

एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि झारखंड पुलिस के तकनीकी सेल ने यह क्युआर कोड विकसित किया है। क्युआर कोड को मोबाइल से स्कैन करते



जाएगा। किसी भी आपात स्थिति में यह सुविधा पुलिस सहायता त्ररंत उपलब्ध कराएगी। इसे पूरे राज्य में लगाने की तैयार चल रही है। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में 3000 क्यूआर कोड लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज के

किसी भी प्रकार की छेड़खानी, या समस्या होने पर Dial 112 QR Code को स्कैन करें एवं शिकायत दर्ज करें। सेवा में तत्पर, झारखण्ड पुलिस

समय में अधिकतर लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर रहे हैं। अगर लोग थोड़ी जागरूकता दिखाएं तो न केवल वे अपनी मदद कर पाएंगे, बल्कि उन लोगों की भी सहायता कर सकेंगे, जिनके पास स्मार्टफोन

महिलाओं और यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच

एसएसपी ने बताया कि अगर कोई महिला या छात्रा ऑटो या बस से सफर कर रही है और कोई शख्स उनके साथ गलत हरकत करता है, तो वे तुरंत ऑटो में लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर पुलिस को सूचना दे सकती है। स्कैन करते ही पुलिस को उसकी लोकेशन और फोन नंबर मिल जाएगा, जिससे त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी। इसी तरह, अगर किसी व्यक्ति के साथ एटीएम में पैसे निकालते समय साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी होती है, तो वहां भी क्यूआर कोड की मदद से पुलिस को सूचित किया जा सकता है।

ऐसे करें शिकायत

क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद मोबाइल में एक पेज खुलेगा। यहां रिक्वेस्ट हेल्प पर क्लिक करने के बाद नाम, पता, मोबाइल नंबर, अपनी समस्या आदि भरें । इसके बाद वेबसाइट को अपनी लोकेशन एक्सेस दें । फॉर्म को सबिमट करते ही पुलिस आपसे खुद संपर्क करेगी। ज्ञात हो कि पहले 100 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी जाती थी, यह सुविधा अब ११२ से परिवर्तित की जा रही है।

पहले चरण में ऑटो और एटीएम में लगाए जाएंगे क्यआर कोड

पहले चरण में जमशेदपुर के सभी ऑटो और एटीएम में यह क्यूआर कोड लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। सभी थानों में कोड भेज दिया गया है। क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस से संपर्क करना अब बेहद सरल हो गया है। स्कैन करने के बाद डायल 112 की टीम स्वयं कॉल करेगी और मोबाइल स्क्रीन पर एक फॉर्म उपलब्ध होगा. जिसमें केवल चार बिंदु भरकर शिकायत दर्ज की जा

बांग्लादेश सरकार को कड़ी चेतावनी दे भारत : कांग्रेस

JAMSHEDPUR : पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि भारत सरकार अविलंब हस्तक्षेप कर बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी जारी करे। बांग्लादेश में जातीय उन्माद को काबू करा कर शांति बहाल कराए। दुबे ने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन समर्थन से भारत की एकता, सर्वधर्म समभाव खतरे में आ गया है। जातीय उन्माद से हर हाल में देश एवं राष्ट्र को नुकसान होता है। इस बात को भाजपा एवं आरएसएस समझने को तैयार नहीं है। भाजपा केवल उन्माद को बढ़ावा दे रही है। भाजपा झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कर रही थी, अब तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारी अत्याचार हो रहा है।

Thursday, 05 December 2024

BRIEF NEWS सड़क किनारे फेंके हुए नवजात का मिला शव

ARARIYA: फारबिसगंज प्रखंड के सैफगंज चौक के पास राज्य राजमार्ग 77 पर स्थित विषहरी स्थान के किनारे बुधवार को नवजात शिशु का शव मिला। नवजात शिशु का शव विषहरी स्थान के पास सड़क के किनारे मिला।नवजात शिशु के शव होने की सूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।नवजात शिशु के शव से एगो में हड़कंप मच गया।नवजात शिशु की उम्र 7-8 महीने के बीच की बताई जाती है। वह मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। घटना की सूचना के बाद लाइफ सेवियर फाउंडेशन बिहार के अध्यक्ष मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और शिशु का शव को उठाते हुए उसे दफनाने की प्रक्रिया पूरी की विहीं ग्रीन घटना से स्तब्ध थे।ग्रामीण इस घटना से पुरी तरह आक्रोशित थे और मां की ममता को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। स्थानीय ग्रामीण इस तरह की अमानवीय घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की।वहीं लाइफ सेवियर फाउंडेशन के द्वारा किए गए पहल की सराहना की गई।

31 लीटर देसी शराब के साथ तीन लोग गिरफ्तार

ARARIYA: फारबिसगंज थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर भागकोहलिया वार्ड संख्या एक निवासी रीता देवी पति -बिंदेश्वरी मंडल के घर में छापेमारी कर नशे की हालत में तीन यवकों को 31 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों में कादरी मोहल्ला वार्ड संख्या 16 के रहने वाले स्व.मो.मुस्लिम के पुत्र 38 वर्षीय मो. मानू और 32 वर्षीय मो.जान् तथा 34 वर्षीय मो.इबराज पिता -मो. इसराइल है।तीनों युवक नशे की हालत में धुत्त था। पुलिस ने बुधवार को तीनों गिरफ्तार युवकों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नशे का कारोबार करने वाली रीता देवी और उसका पति बिंदेश्वरी मंडल मौके से फरार हो गया।मामले को लेकर फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी कांड संख्या 716/24 धारा 30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के

तहत दर्ज किया गया है। रजौली उप प्रमुख सहित नौ पर प्राथमिकी दर्ज

NAWADA : जिले में रजौली थानाक्षेत्र के सवैयाटांड पंचायत में अभ्रक के अवैध खनन को लेकर रजौली रेंजर मनोज कमार ने बधवार को रजौली उप-प्रमुख बिनोद राजवंशी सहित नौ अन्य लोगों के विरुद्ध वन अधिनियम के ससंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है। इस संबंध में रजौली रेंजर मनोज कुमार ने बताया कि सवैयाटांड़ वन क्षेत्र में अवैध अभ्रक का उत्खनन पर अंकुश लगाने के लिए लगातार वन क्षेत्रों में गश्त की जाती है। इसी दौरान बुधवार को भी थानाक्षेत्र के सवैयाटांड़ पंचायत के शारदा सहित कई अभ्रक खदानों का निरीक्षण किया गया इस दौरान वन क्षेत्र में खनन करने वालों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभ्रक का अवैध खनन करने वालों में रजौली उप-प्रमुख कारू राजवंशी के पत्र बिनोद कुमार, युगल सिंह के पुत्र महेंद्र सिंह, बालेश्वर प्रसाद के पुत्र रमेश यादव, जागो यादव के पुत्र घुटर यादव, कार्तिक तुरिया के पुत्र महेंद्र तुरिया, सबदर अंसारी के पुत्र एहसान अंसारी,चितावन साव का पुत्र सिकंदर साव,मुमताज मिया का पुत्र

अवतार मियां का नाम शामिल है।

घर बंद कर एक शादी समारोह में गया था पूरा परिवार

चोरों ने ताला तोड़कर उड़ा ली ₹६० लाख की संपत्ति

पटना के दानापुर में बेखौफ चोरों ने रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी चरित्र सिंह के बंद घर के पीछे से खिड़की का ग्रिल तोड़कर 55 हजार नकद समेत 60 लाख के कीमती जेवरात चरा लिए. इस संबंध में चरित्र सिंह राम ने स्थानीय थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। यह पुरा मामला लखनी बिगहा महर्षि मेंही नगर का है।

लिखित शिकायत में चरित्र सिंह ने बताया कि 2 दिसंबर को पुरा परिवार घर में ताला बंद कर भतीजी की शादी में शामिल होने दुल्हिन बाजार के डुमरी गांव गया था। बुधवार की सुबह जब घर वापस लौटे तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था और अंदर



लाख के सोने-चांदी के जेवरात

कि शादी समारोह में उनके चार बेटे भी आए थे, जिनमें से दो बैंक कर्मचारी, एक रेलवे कर्मचारी और एक बीएचय में कार्यरत है। उन्होंने बताया कि घर में रखे कैश समेत चार बहुओं और पत्नी के कीमती

डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। खगौल पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि चोरों की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि पुलिस की गश्ती टीम कभी भी इस कॉलोनी में नहीं आती है।

हो गए। चोरों ने बड़े आराम से

छह कमरों में 7 अलमारियों का

ताला तोड़कर उन्हें खंगाला।

चरित्र सिंह ने तुरंत ही 112

डायल कर पुलिस को इसकी

सूचना दी। सूचना मिलते ही

नालंदा ने ५० लाख मत्स्य बीज उत्पादन कर बनाया रिकॉर्ड

NALANDA : नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने मंगलवार को सिलाव प्रखंड स्थित मोहनपुर मत्स्य हैचरी मे 50लाख मत्स्य बीज उत्पादन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हैचरी की सुविधाओं, कार्यप्रणाली और समस्याओं का गहनता से जांचा परखा। जिलाधिकारी ने हैचरी के संचालक और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हैचरी में स्वच्छता और सुरक्षा के उपायों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में मछली पालन उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां की जलवायु और जल संसाधन मछली पालन के लिए आदर्श हैं, जिससे यह क्षेत्र रोजगार का एक प्रमुख साधन बन गया है।मोहनपुर मत्स्य हैचरी के संचालक शिवनंदन प्रसाद उर्फ शिवजी ने जानकारी दी कि इस वर्ष हैचरी ने 50 लाख से अधिक

दरवाजे पर खडी थी बेटी की बारात अज्ञात वाहन ने ली पिता की जान अंदाजा लगाइए उस घर में उस

AGENCY MOTIHARI:

वक्त क्या माहौल रहा होगा जब बेटी की बारात दरवाजे पर खड़ी हो और दुल्हन के पिता की मौत हो जाए। कलेजे को चीर देने वाली ये खबर बिहार के मोतिहारी जिले से आई है, जहां के पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र के चैता पंचायत में एक पिता अपने घर के दरवाजे पर बेटी के बारात का इंतजार कर रहा था। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने उसकी जान ले ली। ऐसे में बारातियों ने संवेदनशीलता, मानवीयता और सुझबुझ का परिचय देते हुए एक तरफ पिता के अर्थी उठाने की तैयारी शुरू की तो दूसरी तरफ दुल्हा-दुल्हन की शादी कराकर मिसाल कायम की। इतना ही नहीं इस दौरान बारातियों ने पानी भी नहीं पिया और दुल्हन को आगे की रस्म के लिए लेकर चले गए। मोतिहारी जिले के चैता पंचायत के वार्ड नंबर 5 हसनाबाद निवासी मनोज शाह की मौत उस वक्त हुई जब वह अपनी बेटी के बारात का



नहीं लिखा था। बारात का इंतजार कर रहे पिता घर के सामने हाईवे पर किसी काम से गए। इसी दौरान किसी अज्ञात गाड़ी ने उन्हें ठोकर मार दी। जिससे उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों में भगदड मच गई और आनन फानन में लोगों ने घायल को पकड़ीदयाल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना के बाद ग्रामीणों ने किसी तरह जल्दबाजी में लड़का-लड़की की शादी करवाई। वहीं, शादी के बाद बाराती बिना खाये पिये ही वापस चले गए। वहीं, मौके पर पलिस पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए

संभल में अराजकता फैलाना चाहते हैं राहुल गांधी : सम्राट

कांग्रेस नेता राहल गांधी की संभल यात्रा को पुलिस-प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया है। जिसको लेकर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बिहार सरकार के उपमख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कोई काम नहीं है। इसलिए वह संभल जा रहे है। जब यूपी की सरकार ने पहले ही कह दिया था कि 10 दिसंबर तक कोई भी राजनीति से जुड़ा व्यक्ति नहीं जा सकता है तब संभल जाने की कोशिश क्यों की जा रही है? यह केवल और केवल राजनीति से प्रेरित होकर उठाया गया कदम है। वहीं, राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की यात्रा को सरकारी खजाने का बंदरबांट बताते हुए हमला बोला है। बिहार में अच्छा प्रभाव पड़ेगा।



तेजस्वी यादव से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार में किस तरीके से सरकारी खजाने की लूट की जा रहा थी, यह जगजाहिर बात है। ऐसे लोग अब नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठाते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस पार्टी का भ्रष्टाचार से नाता रहा हो, वह दूसरों को नसीहत न दे तो अच्छा है। वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार की महिला सम्मान यात्रा को लेकर कहा कि इसका

चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एफँआईआर दर्ज

CHAMPARAN: वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र के कमार्बारी गांव की एक मां ने अपने चार वर्षीय बच्ची से दृष्कर्म करने के प्रयास करने का आरोप लगाते हुए अपने पड़ोसी के विरुद्ध वाल्मीकि नगर थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है।उसने अपने आवेदन में लिखा है, कि मंगलवार की शाम लगभग पांच बजे अपने घर में कपड़ा धो रही थी, तभी अपनी बच्ची की रोने की आवाज पड़ोसी के घर में सुनी, तब वह पड़ोसी के घर पहुंची, तब देखी कि उसका पड़ोसी राजन कुमार अपने घर में उसकी बच्ची को बिस्तर पर लेटा रखा है और बच्ची रो रही थी। जब मैं अपनी बच्ची को गोद में उठाया, तो देखा कि उसका फ्रॉक भीगा हुआ था, उससे पूछी कि तुम मेरी बच्ची के साथ क्या कर रहा था।तब मेरे साथ गाली गलौज करते हुए अपने

मोतिहारी में भू-माफिया ने बेच दी सरकारी

स्कूल की जमीन, मंत्री बोले- होगी कार्रवाई **AGENCY MOTIHARI:** कहा जाता है बिहार एक ऐसा

राज्य है जहां कुछ भी असंभव नहीं है। यहां कभी सडक चोरी हो जाती है तो कभी भी पल। लेकिन इस बार इन सब से अलग कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, दरअसल, बिहार में भू-माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि मोतिहारी में भू-माफियाओं ने एक नहीं बल्कि दो-दो सरकारी स्कूलों की जमीन बेच दी। इतना ही नहीं सरकारी जमीन की विक्रेता के नाम पर रजिस्ट्री भी करा दी। यहां तक कि दाखिल-खारिज भी खरीदने वाले के नाम पर करा दिया गया। अब इस मामले को क्षेत्र के विधायक पवन जायसवाल द्वारा उठाए जाने पर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है।



मोतिहारी जिले के ढाका प्रखंड के उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचपकड़ी और उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया की जमीन को बेचने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक फुलवरिया स्कूल की 41 डिसमिल जमीन की पांच साल पहले 2019 में रजिस्ट्री की गई। ढाका के अंचलाधिकारी ने फलवरिया स्कल की दाखिल

खारिज खरीदने वाले के नाम पर कायम भी कर दी। यूं तो इस मध्य विद्यालय में शिक्षक भी पदस्थापित हैं और सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं लेकिन कर्मचारी की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि रिक्त घोषित की गई है, जिस पर विक्रेता का दखल-कब्जा बताया गया है। एक घटना को अंजाम देने के बाद भू-माफियाओं की हिम्मत इतनी बढ गई कि उन्होंने उत्क्रमित उच्चतर

की भिम को भी बेच दिया। जबिक यह जमीन विद्यालय परिसर के अंदर है और बच्चे उसे खेल मैदान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस जालसाजी को गोपनीय रखने के लिए ढाका में निबंधन कार्यालय होने के बावजूद उसकी रजिस्ट्री मोतिहारी निबंधन कार्यालय में कराई गई। मामले की जानकारी होने पर दोनों ही मामलों को ढाका के विधायक पवन जायसवाल ने उठाया। इस पर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मामले की जांच कर रहे अपर समाहर्ता मुकेश सिंह ने स्वीकार किया कि यह गंभीर किस्म का अपराध है। इसमें सम्मिलित किसी भी कर्मचारी अथवा अधिकारी के

पहले जैसे अब नी्तीश् कुमार नहीं रहे, वो थक गए हैं : तेजस्वी यादव

पहले वाले मख्यमंत्री नीतीश कमार अब नहीं रहे, विकास के मामले में मख्यमंत्री का अब कोई विजन नहीं रह गया है। अब वह थक गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यह बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मख्यमंत्री सिर्फ मखौटा हैं। बिहार को आगे बढाने के लिए सीएम के पास कोई विजन ही नहीं है।आज वैकेंसी निकल रही है, लेकिन उसमें आरक्षण नहीं मिल रहा है। जाति आधारित गणना में भी भाजपा के लोग थे वह पूरी तरह आरक्षण संविधान के खिलाफ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोगों ने बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया था। लेकिन वहीं सीएम इसे केंद्र से लागू करवाने में असफल साबित हो रहे हैं। आज बिहार की जनता पुरी तरह परेशान है। स्मार्ट मीटर ,



जमीन सर्वेक्षण से लोग परेशान हो गए हैं। बिजली काफी महंगी हो गई है। हमारी सरकार आएगी तो हम 200 वॉट बिजली फ्री देंगे। हमने 17 महीने में 415 लाख लोगों को नौकरी दी। जनता की समस्याएं दूर की , विधि व्यवस्था आज के दिन में चौपट हो गई है।तेजस्वी ने कहा कि सीएम जनसंवाद कार्यक्रम में ढाई सौ करोड़ खर्च होगा। यह कहां का न्याय है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए जाने के मामले में मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? बाढ़ पीड़ितों को राशि नहीं मिल रही है , लेकिन मुख्यमंत्री

एक जिलों में बैठकर तीन जिलों के लोगों की समस्या सनेंगे। जनता का पैसा है, जनता जानना चाहती है कि एक कार्यक्रम में तीन जिलों के लोगों का संवाद कैसे कर लेंगे। जनता दरबार में भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्या दो घंटा में सीएम समस्या का समाधान कर लेंगे। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग बिहार को अगर आगे बढाने में काम करेंगे, इसका प्लान हम लोगों ने तैयार कर लिया है , हमारे आने से पहले पेपर लीक होता था, लेकिन हमारे समय में पेपर लीक

भारत सरकार लिखी कार से जन सुराज का पर्चा और ₹1.56 लाख बरामद

SITAMARHI: सीतामढ़ी पुलिस ने भारत सरकार लिखी हुई सफेद कलर की कार से जन सुराज पार्टी का पर्चा और 1.56 लाख रुपए बरामद किया है। बताया जा रहा है। कि रुपये वोटरों में बांटने के लिए ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है कि उक्त रुपये किस मकसद से लाए गए थे। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए कल यानी 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। बताया जा रहा है कि डुमरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक लग्जरी कार से पैसों से भरे बैग के साथ तीन लोगों को हिरासत में लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोग जन सराज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि एक लग्जरी कार में बैठे लोग वोटरों के बीच पैसे बांट रहे हैं। इस सचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी से नोटों से भरे बैग के अलावा पंपलेट, चुनाव प्रचार सामग्री समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं।

पप्पू यादव ने कहा- सीबीआई करे धमकियों की जांच, हाईकोर्ट जाऊंगा

बिहार के पर्णिया से सांसद पप्प यादव ने लगातार मिल रहीं जान से मारने की धमिकयों के मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उन्होंने पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय के शर्मा पर एक पार्टी की तरह काम करने का आरोप लगाया। सांसद ने एसपी से बिना वर्दी में सामने आकर बात करने की चनौती भी दी है। बता दें कि एक दिन पहले एसपी ने पप्पू यादव को धमकी भरे मैसेज और वीडियो भेजने के मामले का खुलासा करते हुए इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ होने के दावों को खारिज किया था। उन्होंने आरा से गिरफ्तार एक शख्स के कबूलनामे का हवाला देते हुए पप्पू के सहयोगियों द्वारा ही साजिश रचने का दावा किया था। हालांकि. सांसद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पप्पू यादव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में



कहा कि उन्हें जो धमकी भरे कॉल, मैसेज और वीडियो आदि भेजे गए हैं, बिहार सरकार उनकी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से कराए। उन्होंने इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाने की बात भी कही। सांसद ने पूर्णिया के एसपी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि पलिस द्वारा लगाए गए आरोप अगर सही साबित हुए, तो वह राजनीति छोड़ देंगे। पप्पू यादव ने कहा, ह्रमुझे 23 से 24 धमकी भरे फोन कॉल आए. जिनमें से अधिकतर की अब तक जांच नहीं हुई है। मुझे सुरक्षा की

के साथथ रहना पसंद है। एसपी एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। चंद राजनेताओं के उकसावे पर वह मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। सरक्षा बढाने के नाम पर मुझे फर्जी धमकी देने वाले मेरे करीबी सहयोगी का नाम सार्वजनिक कर दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा ह्व इससे पहले पूर्णिया सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि सत्ताधारी दलों के कछ नेता पलिस के साथ मिलकर उनकी हत्या करवाने की साजिश रच रहे हैं। अगर सरकार इसे गंभीरता से नहीं लेती है तो उनके पास अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पप्पू यादव को धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरा से रामबाबू यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

विस चुनाव की तैयारी : बिहार में महिला संवाद यात्रा से पहले हो रही 'प्लान डब्ल्यू' की चर्चा

महिलाओं को साधने में जुटे सीएम नीतीश कुमार

2025 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से बिहार के औरंगाबाद से अपनी संवाद यात्रा पर निकलेंगे। औरंगाबाद में इसको लेकर तैयारी भी चल रही है। लेकिन, सीएम के इस यात्रा से पहले बिहार में बहुत चर्चा हो रही है। राजनीतिक पंडित से लेकर राजनीतिक दल के नेता भी नीतीश कुमार की बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले होने वाली इस यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल, सीएम नीतीश कुमार अपने इस संवाद यात्रा में महिला से भी बात करेंगे। नीतीश कुमार के 'प्लान डब्ल्यू' को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम ने अपनी इस यात्रा का नाम भी महिला संवाद दिया है। इससे

शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री बन गए लोकप्रिय

बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार को महिलाओं के बीच ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। महिलाओं ने सीएम से उनकी यात्रा के दौरान इसको लेकर अपनी पीड़ा शेयर किया था। सीएम ने इसके तत्काल बाद बिहार में शराबबंदी की घोषणा कर दी थी। इतना ही नहीं सीएम ने इससे पहले स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल और अच्छे नंबर लाने पर पुरस्कार देने की पहल कर बिहार में महिलाओं को मुख्यधारा में जोड़ने का का काम कर चुके हैं। पंचायत चुनाव और नौकरी में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सीएम ने महिलाओं को बिहार में हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर खड़ा करने का प्रयास कर चुके हैं। यही कारण है कि बिहार में नीतीश कुमार को महिलाओं का ज्यादा वोट मिलता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के महिला संवाद यात्रा के दावे से बिहार में सियासी हलचलें बढ गई है। मध्य प्रदेश में चलने वाली लाडली बहन योजना में 1500 रुपये मिला करता है। पहले 1000 रुपया दिए जाते थे। इसी प्रकार झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं को अब तक मईया सम्मान योजना के तहत 1000 रुपया मिला करता था। लेकिन दिसंबर से उनको २५०० रुपया मिलेगा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि दोनों प्रदेश के चुनाव में यह योजना जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

साफ है कि जनता दल (यूनाइटेड) का बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में मुख्य फोकस महिलाओं पर है। सूत्रों

का कहना है शराबबंदी के बाद प्रदेश की एनडीए सरकार महिला संवाद के बाद महिलाओं को साधने के लिए कुछ खास

योजनाएं लागू कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि मध्यप्रदेश के लाडली योजना और झारखंड की मईया योजना की तर्ज पर बिहार

भी चुनाव से पहले सरकार कुछ घोषणा कर सकती है। पार्टी सूत्रों की माने तो योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 2015 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की थी। वर्तमान में राज्य में लगभग 11 लाख समूह सिक्रय हैं, जिनमें प्रत्येक समूह में 10 महिलाएं शामिल हैं। सरकार इन समृहों को दिए गए लोन को माफ करने पर विचार कर रही है, जिससे सीधे तौर पर लाखों महिलाओं को लाभ होगा।

दुष्कर्म के प्रयास मामले में पटोरी थानेदार सस्पेंड

SAMASTIPUR : बिहार के समस्तीपुर जिले के पटोरी थाने में तैनात दारोगा बलाल खान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। दारोगा पर एक केस की पीड़िता को घर में बुलाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप है। पीड़िता के द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। घटना के बाद से दारोगा अपना घर छोड़कर फरार हो गया। जिला पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा ने इस मामले में पटोरी डीएसपी को मामले की जांच का निर्देश दिया था। पटोरी डीएसपी के जांच रिपोर्ट आने के बाद दारोगा को निलंबित कर दिया गया है। जिला पुलिस कप्तान अशोक मिश्रा ने बताया कि पटोरी में पदस्थापित दारोगा बलाल खान ने अपने प्राइवेट आवास में एक महिला बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था।

भ्रष्टाचार में लिप्त चार पदाधिकारी निलंबित

बिहार के उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक रजनीश कुमार सिंह ने मद्यनिषेध विभाग के चार अधिकारियों तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई रजनीश कुमार सिंह ने उस शिकायत के आधार पर की जिसमें सोनू कुमार पोद्दार (पिताः महेश पोद्दार, निवासीः महेन्द्रपुर, पोस्टः मोगमटगामा, थानाः मुफस्सिल रानीपतरा, जिलाः पूर्णिया) ने एक दिसम्बर की रात को व्हाट्सएप पर एक आवेदन और ऑडियो

मद्यनिषेध, पूर्णिया को निर्देश दिया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में निरीक्षक सुमन कांत झा, अवर निरीक्षक

अवर

चंदन कुमार, सहायक

दिनेश कुमार दास,

निरीक्षक

और सिपाही प्रदीप कुमार पर गाली-गलौज करने और झुठे मामले में फंसाने के बदले धन की मांग का आरोप रिकॉर्डिंग भेजकर आरोप लगाया था। आयुक्त ने मामले की सत्यता

लगाया गया। ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच के बाद, चारों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। जांच अधिकारी ने ऑडियो में पैसे के लेन-देन से संबंधित बातचीत की पुष्टि की। चारों अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण असंतोषजनक की जांच के लिए सहायक आयुक्त पाया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संस्थानों पर उटते सवाल

भारतीय संस्थानों से निकले एसटीईएम स्नातकों की एक बड़ी संख्या

ऐसी है, जिनमें आवश्यक कौशल का अभाव है। यह उद्योग और

अनुसंधान प्रगति में बाधा डालता है। संस्थागत रैंकिंग को बढ़ावा

देने के लिए अनुसंधान आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने से कई

शिक्षण-केंद्रित संस्थानों ने अक्सर निम्न गुणवत्ता वाले आउटलेट में

प्रकाशन पत्र और पेटेंट को प्राथमिकता दी है, कई संस्थानों में

संकाय पर अत्यधिक बोझ है, पेशेवर विकास के लिए बहुत कम

समय या प्रोत्साहन है। संकाय भर्ती अक्सर स्थानीयकृत होती है,

जिससे शैक्षणिक प्रदर्शन और दृष्टिकोण की विविधता सीमित हो

जाती है। क्वांटम कंप्यटिंग और कत्रिम बद्धिमता जैसी पहलों के

लिए कशल पेशेवरों की आवश्यकता होती है, लेकिन सीमित योग्य

कर्मियों और अपर्याप्त प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के कारण इन पहलों

का उपयोग कम होने का खतरा है। वर्तमान संरचना संसाधनों,

पाठ्यक्रम या संकाय के आदान-प्रदान की सुविधा नहीं देती है,

जिससे शिक्षा और अनुसंधान के बीच विभाजन मजबूत होता है,

विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में योगदान के अपने समृद्ध इतिहास

के साथ भारत अब एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहां देश में

(विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा के भविष्य को

आकार देने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे-जैसे

दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का

समावेश केवल चलन नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी

छात्रों और शिक्षकों के बीच सहयोग को सुगम बनाती है। ऑनलाइन

प्लेटफॉर्म और उपकरण परियोजनाओं पर वास्तविक समय में

सहयोग को सक्षम करते हैं. टीमवर्क और संचार कौशल को

प्रोत्साहित करते हैं। ये सहयोगात्मक अनुभव पेशेवर दुनिया में

वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की सहयोगात्मक प्रकृति को दशार्ते

हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण कई लाभ लाता है, यह

चुनौतियों को भी सामने लाता है, जिन्हें व्यापक परिवर्तन के लिए

संबोधित करने की आवश्यकता है। डिजिटल डिवाइड एक

महत्वपर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसमें प्रौद्योगिकी और

इंटरनेट तक पहुंच में असमानताएं हैं। इस अंतर को पाटना यह

सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सभी छात्रों को उनकी

सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रौद्योगिकी के

उपयोग से लाभ उठाने के समान अवसर मिलें। शिक्षकों को भी

अपने शिक्षण विधियों में प्रौद्योगिकी को प्रभावी ढंग से एकीकृत

करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षकों के लिए

निरंतर व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना सुनिश्चित करता

है कि वे प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझने के लिए अच्छी तरह से

सुसज्जित हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के नैतिक

उपयोग, जिसमें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा शामिल है, जिसे

प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी की

सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना और शिक्षा प्रौद्योगिकी

उपकरणों के विकास में नैतिक प्रथाओं को सुनिश्चित करना

महत्वपूर्ण कदम हैं। शिक्षण केंद्रित संस्थानों के मूल्यांकन को

अनुसंधान मेट्रिक्स से अलग करके रैंकिंग अनुसंधान आउटपुट पर

शिक्षण गुणवत्ता को प्रतिबिंबित कर सकती है, जिससे इन संस्थानों पर निम्न गुणवत्ता वाले अनुसंधान को आगे बढ़ाने का दबाव कम

हो सकता है। शिक्षण संस्थानों को मूलभूत कौशल को मजबूत करने के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों में अनुसंधान पर शिक्षाशास्त्र को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समर्पित शिक्षण ट्रैक शुरू किया जा सकता है, जिससे शिक्षाशास्त्र में रुचि रखने वाले संकाय सदस्यों को अकेले अनुसंधान आउटपुट के बजाय अपने शिक्षण कौशल के

आधार पर आगे बढ़ने की अनुमित मिल सके। अनुसंधान संस्थान

संयुक्त डिग्री कार्यक्रम बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों के साथ

साझेदारी कर सकते हैं, जिससे उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को

अपना काम पूरा करने में मदद मिलेगी अनुसंधान केंद्रित संस्थानों

में अध्ययन, इस दृष्टिकोण का एक उदाहरण एनआईटी सरत और

आईआईटी बॉम्बे के बीच सहयोग है, जो छात्रों को एक प्रमुख

संस्थान में उन्नत अध्ययन पूरा करने की अनुमित देता है। सरकारी

फंडिंग को शिक्षण संस्थानों के भीतर शिक्षाशास्त्र में उत्कृष्टता केंद्र

स्थापित करने की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये केंद्र

शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास और एसटीईएम शिक्षा में

सर्वोत्तम प्रथाओं के केंद्र के रूप में काम करेंगे, जिससे बड़े

अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बिना प्रणालीगत सधार

होंगे। भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियां

एक बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करती हैं, जिसमें पाठ्यक्रम

आधुनिकीकरण, अनुसंधान वित्त पोषण, संकाय विकास और

विविधता पहल शामिल हैं। सरकार और उद्योग के सहयोग में वृद्धि

से समर्थित नीतिगत सुधार, अधिक गतिशील, उद्योग सरेखित और

समावेशी एसटीईएम पारिस्थितिकी तंत्र बना सकते हैं। भारत में

शिक्षा प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें

शिक्षा तक असमान पहुंच, पुराना पाठ्यक्रम और अपर्याप्त धन

शामिल है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद देश में सम्मानित

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार

ने शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली चनौतियों का समाधान करने

में महत्वपर्ण प्रगति की है। शिक्षा में निरंतर निवेश के साथ भारत में

सीखने और ज्ञान का एक अग्रणी केंद्र बनने और अपने सभी

नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की क्षमता है।

ऐसी सरकार के लिए

लोस चुनाव और महाराष्ट्र विस चुनाव के बीच क्या बदला



पहली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ विधानसभा चुनावों में भारी जीत और दूसरी 500 वर्षों में सबसे बड़ी घटना, 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा लग रहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पूरे देश में गति पकड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ रहा है। इसलिए अब की बार चार सौ पार का नारा चुनाव की मुख्य लग रहा था कि एनडीए के नेता और उनकी जमीनी टीम और समर्थक यह मानकर निश्चिंत थे कि मोदी है तो मुमकिन है। 400 या उससे अधिक सीटों के साथ एक सुनिश्चित जीत के बारे में इस आत्मसंतुष्टि ने उन्हें वैश्विक डीप स्टेट ताकतों से बेखबर कर दिया, जो इंडी गठबंधन, शहरी नक्सिलयों, कम्युनिस्टों और मार्क्सवादियों के समर्थन से एक टीम बना रहे थे, ताकि देशभर में लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी जा सकें। इस तरह की सावधानीपूर्वक योजना, साथ ही झूटी कहानिया गढने और उन्हें प्रत्येक घर में वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन के उपयोग ने मोदी सरकार में लोगों के विश्वास को

शानदार प्रदर्शन किया और लंबे समय से चली आ रही जटिल चुनौतियों का समाधान भी किया। इस चुनाव से पहले दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहली मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में भारी जीत और दूसरी 500 वर्षों में सबसे बड़ी घटना, 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राममंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। ऐसा लग रहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए पूरे देश में गति पकड़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए अब की बार चार सौ पार का नारा चुनाव की मुख्य दिशा बन गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एनडीए के नेता और उनकी जमीनी टीम और समर्थक यह मानकर निश्चिंत थे कि मोदी है तो मुमिकन है। 400 या उससे अधिक सीटों के साथ एक सुनिश्चित जीत के बारे में इस आत्मसंतुष्टि ने उन्हें वैश्विक डीप स्टेट ताकतों से बेखबर कर दिया. जो इंडी गठबंधन, शहरी नक्सलियों, कम्युनिस्टों और मार्क्सवादियों के समर्थन से एक टीम बना रहे थे, ताकि देशभर में लोगों का ब्रेनवॉश करने के लिए फर्जी कहानियां गढ़ी जा सकें। इस तरह की सावधानीपूर्वक योजना, साथ ही झूठी कहानियां गढ़ने और उन्हें प्रत्येक घर में वितरित करने के लिए बड़ी मात्रा में धन के उपयोग ने मोदी सरकार में लोगों के विश्वास को हिला दिया। 400 सीटें मिलने पर संविधान को खत्म करना, आरक्षण को हटाना, बेरोजगारी बढ़ना, मोदी सरकार द्वारा भारी

करने में काफी प्रभावी रहीं। इसका काफी असर हुआ है, जिससे भाजपा को सिर्फ 240 सीटें मिलीं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन उन्होंने पार्टियों के समर्थन और शुरूआत में कम आत्मविश्वास के साथ ऐसा किया। हालांकि गांधी परिवार, इंडी गठबंधन, धार्मिक चरमपंथियों, धर्मांतरण माफिया, शहरी नक्सलियों, वोक और वैश्विक बाजार की ताकतों ढहती मानसिकता ने अचानक उनके आत्मविश्वास के स्तर को बढा दिया। उन्होंने मोदी के लिए कम सीटों की व्याख्या इस संकेत के रूप में की कि हिंदुओं ने खुद को पीएम मोदी से दूर कर लिया है और हिंदुत्व की हार हुई है। उनका मानना था कि जाति के आधार पर हिंदुओं को अलग करना और झुठी कहानियों का इस्तेमाल करकर भ्रमित करना आसान था। हिंदुत्व अब हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आत्मविश्वास में वृद्धि इतनी अधिक थी कि कई मुस्लिम प्रचारकों और चरमपंथियों ने हिंदुओं, हिंदू देवताओं और संस्कृति पर हमला करना शुरू कर दिया, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने और पाकिस्तान और फिलिस्तीन के झंडे फहराने

समय पर बड़ी सभाएं आयोजित की। राहुल गांधी और कुछ अन्य इंडी गठबंधन के नेताओं ने हिंदुत्व पर प्रहार करना शुरू कर दिया, इस्लामी और ईसाई अनुष्ठानों और देवताओं की प्रशंसा करते हुए हिंदू संस्कृति और देवताओं को गाली दी। राहुल गांधी ने हिंदू एकता को कमजोर करने के लिए संविधान और आरक्षण के बारे में गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया। वक्फ बोर्ड की मांगें प्रमखता से उभरने लगीं और जवाहरलाल नेहरू के वक्फ अधिनियम के तहत हिंदुओं की भूमि और संपत्ति की मांग करने लगे. जिसे बाद में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकारों ने मजबूत किया था। राहुल गांधी और उनके इंडी गठबंधन के सहयोगियों ने मोदी सरकार के वक्फ सुधार विधेयक का आक्रामक रूप से विरोध किया, जिसे हिंदुओं की रक्षा के लिए पेश किया गया था। जिस तरह आम चुनाव के दौरान और उसके बाद हिंदुओं और हिंदुत्व को निशाना बनाया गया, उससे हिंदुओं को साफ पता चल गया कि यह देश भविष्य में शरिया कानून और गहरी वैश्विक शक्तियों की इच्छाओं के अनुसार आगे बढ़ेगा। हिंदू (बौद्ध, जैन, सिख) आध्यात्मिक और धार्मिक

अन्य संगठनों ने हिंदू समुदाय के विभाजन के खतरों और राजनीतिक हिंदुत्व पर इसके प्रभाव को पहचान लिया। इसलिए वे सभी एक साथ आ गए। आरएसएस, वीएचपी और अन्य हिंदुत्व संगठनों की मदद से धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं ने वक्फ बोर्ड अधिनियम, लव जिहाद, शरिया कानून, वोट जिहाद के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदुओं की बड़ी सभाओं को संबोधित करके फर्जी आख्यानों पर काम करना शुरू कर दिया। कैसे इस्लामी शासन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को नष्ट कर रहा है, मदरसा घृणित शिक्षा और इसके वित्तपोषण, हिंदुओं का धार्मिक रूपांतरण और इसके घातक प्रभाव और कैसे एकजुट हिंदू संविधान को विनाशकारी ताकतों से बचा सकते हैं। इस ज्ञान ने हिंद समदाय में एक बडी सकारात्मक लहर पैदा की और उन्होंने पहचाना कि एकता कितनी महत्वपूर्ण है, यही वजह है कि 2019 और मौजूदा लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार विधानसभा चुनावों में वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यहां तक कि भाजपा ने हिंदुओं या हिंदुत्व के लिए झूठे सेक्युलरिजम

में महत्वपूर्ण लाभ कमाया। कोई भी मीडिया आलोचना उन्हें हिंदुत्व के कारण का खुलकर समर्थन करने से नहीं रोक सकी। हिंदु और हिंदुत्व भाजप के केंद्र में रहे। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के नारे एक हैं तो सरक्षित हैं और बटेंगे तो कटेंगे ने हिंदुओं में जबरदस्त जागति पैदा की। श्रेष्ठता और हीनता का सीमित जातीय दृष्टिकोण टूट गया है और हिंदू हरियाणा और महाराष्ट्र में इकठ्ठा मतदान करते दिखे। मस्लिम नेता सज्जाद नोमानी और अन्य मौलवी और मुस्लिम संगठनों द्वारा इंडी गठबंधन को वोट देने के लिए फतवा जारी करने से हिंदू एकता बढ़ी है। धुले, महाराष्ट्र लोकसभा सीट वोट जिहाद को हिंदुओं को समझाया गया कि अगर वोट जिहाद के परिणामस्वरूप ऐसी सरकार बनती है, जो मुसलमानों की महाराष्ट्र धर्म और सनातन धर्म विरोधी 17 मांगों को परा करती है, तो यह पूरे हिंदू समुदाय के लिए कितना खतरनाक होगा। हिंदुत्ववादी ताकतों के संयुक्त प्रयासों ने हिंदू एकता को मजबूत किया और साथ ही सभी राजनीतिक दलों, खासकर हिंदुत्व का विरोध करने वाले और शरिया का समर्थन करने वालों को एक मजबूत संकेत दिया कि हिंदुओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। सभी क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों की टीम बनाकर और हर व्यक्ति तक सटीक जानकारी या आख्यान पहुंचाकर झुठे आख्यानों का भंडाफोड़ करना बहुत ही कारगर साबित हुआ है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

एक-दूसरे को मुंह चिढ़ाते दो विधान

वक्फ अधिनियम विचार करने के लिए कुछ और समय मिल गया है। अब यह समिति अपनी रपट संसद के अगले सत्र यानी बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। इस समिति की बैठकों में विपक्षी दलों के सांसदों ने जैसा हंगामा किया, उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि सर्वसम्मति से कोई रपट सामने आ सकेगी। विपक्षी सांसदों की मानें तो वक्फ अधिनियम में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। उनका यह निष्कर्ष तब है. जब हाल में कर्नाटक में किसानों की 15 सौ एकड़ जमीन और केरल में छह सौ ईसाइयों की संपत्ति पर वक्फ बोर्डों के दावे को खारिज करने और पीडितों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन देने के लिए वहां के मख्यमंत्रियों को आगे आने पडा। जो इसका रोना रो रहे हैं कि वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हैं, वे भी वक्फ अधिनियम में बदलाव

परिचित लोग भी यह दावा करने में लगे हुए हैं कि यह महज अफवाह है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी संपत्ति को अपनी बता सकते हैं। यदि यह सही है तो फिर कर्नाटक के किसानों और केरल के ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे कर दिया। ऐसे कई मामले सामने आ चके हैं. जिनमें वक्फ बोर्डों के फर्जी दावे की कलई खुली है। कई राज्यों में वक्फ संपत्ति से जुड़े घोटाले भी सामने आ चुके हैं, फिर भी जिद यही है कि मौजूदा वक्फ अधिनियम में सब कुछ सही है। यदि वक्फ अधिनियम सचमुच न्यायसंगत है, तो क्यों न इसी तर्ज पर हिंदू समुदाय के लिए सनातन भूमि अधिनियम बना दिया जाए। वक्फ अधिनियम के तहत बने वक्फ बोडों के अधिकारों को कितना ही नकारा

कर्ज के कारण देश को बेचना

वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को अपना बता दें तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है कि जिसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया हो। एक ओर वक्फ अधिनियम के रूप में देश में एक ऐसा कानन है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकते हैं और दसरी ओर पजा स्थल अधिनियम के रूप में एक ऐसा कानन भी है. जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है. भले ही इसके अकाटय प्रमाण हों कि 1947 से पहले उसका धार्मिक स्वरूप भिन्न था। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को उसी स्वरूप में बनाए रखना है, जो 15 अगस्त 1947 को था। इस कानून से केवल राम मंदिर मामले को बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का आकलन है कि उक्त कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने का निषेध नहीं करता। इसी कारण वाराणसी में

बहुचर्चित संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसीलिए हुआ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हिंद संगठन कछ और धार्मिक स्थलों के सर्वे की मांग कर रहे हैं। कहना कठिन है कि यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। इस सिलसिले को देखकर यह आवाज उठी है कि पुजा स्थल अधिनियम के तहत किसी भी स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने की अनमति न दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, यह देखना विचित्र है कि एक कानून तो किसी को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार देता है और एक अन्य कानून किसी को अपने धार्मिक स्थलों पर बलात कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोकता है। क्या यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है। यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या उसे उसके खिलाफ

नहीं मिलना चाहिए। क्या एक देश में एक-दसरे के विपरीत दो तरह के विधान हो सकते हैं। यदि मान्यता यह है कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश में जो कुछ हुआ, उसे भुला दिया जाए तो क्या इसी आधार पर कोई यह तर्क भी दे सकता है कि अनुसूचित जातियों-जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ, उसे भुला दिया जाए और उनके उत्थान के जो उपाय किए जा रहे हैं, उनसे मुक्ति पा ली जाए। यह समझा जाना चाहिए कि अतीत के घावों की अनदेखी करने से वे भरते नहीं। वे तब भरते हैं, जब अतीत के अन्याय को स्वीकार किया जाता है। ऐसा तब संभव होता है, जब अतीत के अत्याचारों का पता लगाने के लिए सत्य के सम्मुख जाया जाता है। कई देशों में यह काम दूथ एंड रिकंसलिएशन कमीशन के जरिये हुआ है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में इस आयोग का उद्देश्य अतीत के

अत्याचारों को उजागर करना और श्वेत एवं अश्वेत समुदाय के बीच समन्वय-सद्भाव कायम अलावा कनाडा, कोलंबिया समेत दर्जनों देशों में सत्य एवं समन्वय आयोग बन चुके हैं। भारत में भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचारों का पता लगाने के लिए ट्रथ एंड रिकंसलिएशन आयोग बनाने को कहा था। यदि मंदिर-मस्जिद से जुड़े विवादों का हल करने के साथ हिंदू-मुस्लिम सामान्य-सहज करने हैं तो उसका रास्ता ऐसे किसी आयोग के जरिए ही मिल सकता है, न कि अतीत के अन्याय पर पर्दा डालने से या इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने से। निःसंदेह हर मंदिर पर बनी मस्जिद-दरगाह को खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन उसके मूल स्वरूप का सच जानकर सलह का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया जा सकता है।

Social Media Corner

सच के हक में.

नौसेना दिवस पर, हम भारतीय नौसेना के बहादूर कर्मियों को सलाम करते हैं जो अद्वितीय साहस और समर्पण के साथ हमारे समुद्र की रक्षा करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। हमें भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास पर भी बहुत गर्व है। (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)



झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री एम एस रामचंद्र राव जी के दिवंगत पिता और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्व . एम जगन्नाथ राव जी के श्राद्ध कर्म 🎏 में शामिल होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। मरांग बुरु दिवगंत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति दे।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

पिछले दो दिनों से धनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों से संवाद करने का अवसर मिला। इस दौरान धनवार प्रखंड के कोड़ाडीह, जगदीशपुर समेत एक दर्जन से भी ज्यादा अन्य गांवों की अधिसंख्य महिलाओं ने अपनी समस्याओं को साझा किया। अधिकांश महिलाओं ने बताया कि वे मंईयां सम्मान योजना के लाभ से अब तक वंचित हैं। कई पात्र महिलाओं के फॉर्म भरे ही नहीं गए हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। (पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



अनुमोदित वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ओएनओएस) योजना एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और विकास (आरएंडडी) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। यह भारत में मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के लक्ष्यों को साकार करने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। यह केंद्र सरकार की नई पहल है, जिसे विद्वानों के शोध लेख और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तैयार कई गई है। एक ही प्राधिकरण सब कुछ प्रबंधित करता है, ताकि आपको कई प्लेटफॉर्म पर सदस्यता लेने की जरूरत न पड़े। सिर्फ एक सदस्यता आपको अपनी जरूरत की सभी सामग्री और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है, जिससे

द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आपका समय और प्रयास बचता है। इन संसाधनों तक आसान पहुंच के लिए एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान खंडित सदस्यता मॉडल को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यह योजना एक मंच के माध्यम से 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13, 000 से अधिक पत्रिकाओं तक निर्वाध पहुंच प्रदान करेगी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए 13, 000 से अधिक विद्वानों की पत्रिकाओं तक राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना है। 2025-2027 के लिए 6, 000 करोड़ के बजट के साथ, यह देशभर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए शैक्षणिक संसाधनों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए तैयार

की गई है, जिससे विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। इन संसाधनों तक आसान पहुंच के लिए एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जिससे विभिन्न संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्तमान खंडित सदस्यता मॉडल को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। यह योजना एक ही मंच के माध्यम से 30 अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 13, 000 से अधिक पत्रिकाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगी। भारत के अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित प्रभाव ओएनओएस टियर-2 और टियर-3 शहरों सहित 6, 300 सरकारी संस्थानों में 1.8 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय विद्वान संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। लागत बाधाओं को दूर करके यह योजना कम वित्त पोषित और ग्रामीण संस्थानों के शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक अनुसंधान तक पहुंचने में सक्षम बनाती है,

जिससे अनसंधान एवं विकास परिदृश्य में समावेशी विकास को बढावा मिलता है। उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं तक मुफ्त पहुंच से भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशनों की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे भारत की वैश्विक वैज्ञानिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ओएनओएस अनुसंधान संसाधनों तक पहुंच का विस्तार करके अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) का पुरक है, जिससे सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में नवाचार और अनुसंधान एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। यह योजना भारत की बौद्धिक क्षमताओं को मजबूत करती है, जो आर्थिक आत्मनिर्भरता और अनुसंधान एवं विकास में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। अनुसंधान संसाधनों तक बढ़ी हुई पहुंच नवाचार को गति देती है, 2047 तक तकनीकी रूप से उन्नत भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है।

एक चेतावनी

यहां तक कि घोर निराशावादी आर्थिक पूर्वानुमानकर्ताओं ने भी जुलाई-सितंबर की तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के अनुमानों में परिलक्षित आर्थिक रफ्तार में तेज गिरावट की आशंका नहीं जताई थी। अधिकतर स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों ने जीएसटी राजस्व वृद्धि में कमी और उपभोक्ता टिकाऊ व गैर-टिकाऊ वस्तुओं की कमजोर बिक्री जैसे शहरी मांग के संकेतकों का हवाला देते हुए पहली तिमाही (क्यू1) में 6.7 फसद के पांच-तिमाही के निचले स्तर के बरक्स क्यू2 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 फीसद रहने की उम्मीद जताई थी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने जहां अपनी अक्टूबर की समीक्षा में दूसरी तिमाही की वृद्धि दर सात फीसद आंकी थी, वहीं आरबीआई के अधिकारियों ने इसके तुरंत बाद एक लेख में 6.8 फीसद की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। लेकिन, वास्तविक आंकड़ा महज 5.4 फीसद का ही रहा। 2022-23 की तीसरी तिमाही के बाद से सबसे धीमी वृद्धि दर, जो अर्थव्यवस्था में सकल मुल्य-वर्धित (जीवीए) में 5.6 फीसदी की मामूली बेहतर वृद्धि के साथ एक महत्वपूर्ण झटका है। पिछले साल सकल घरेलू उत्पाद में 8.2 फीसद की जोरदार वृद्धि के बाद 2024-25 के दौरान सात फीसद से ज्यादा की वृद्धि दर वाले एक और साल की उम्मीदें अब बहुत ज्यादा आशावादी नहीं तो अनिश्चित होती हुई जरूर दिखाई देतों है, क्योंकि पहली छमाही में सिर्फ छह फीसद की वृद्धि दर ही दर्ज की गई है। आरबीआई की एमपीसी, जिसकी इस सप्ताह फिर से बैठक होने वाली है, को निश्चित रूप से इस साल के लिए अपने 7.2 फीसद के विकास दर संबंधी पूवानुर्मान को फिर से बदलना होगा और उसके लिए धीमे वृद्धि संबंधी आवेगों एवं निवेश का समर्थन करने के लिए ब्याज दरों में कटौती करने के मंत्रियों के हाल के आह्वान के बीच मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने पर अपना ध्यान केंद्रित रखना मुश्किल हो सकता है।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail: thephotonnewsjharkhand@gmail.com

शोध को मजबूत करेगा वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन

Courts letting ancient sores erupt afresh

WHEN in a hole, stop digging further — thus goes the familiar proverb. After the Ayodhya temple judgments, Indian courts are now sought to be engaged in a frenetic digging up of ancient religious grievances of a similar nature.

The underlying primary assumption is that many mosques were built upon temples that had been demolished by invaders. The second assumption is that notwithstanding the passage of centuries of time, there is today a legal right to restore the old temple by demolishing the existing mosque if necessary. The third assumption is that any court anywhere in India can grant executable decrees of change of character of a place of worship of one faith, to a worshipper of another faith. None of these assumptions was upheld by the five-judge Constitution Bench that passed the Ayodhya verdict. The judgment refutes the claim that a temple was brought down to build a mosque in medieval India. It awards decrees to both religions as having established their rights of worship at the spot. However, using the Supreme Court's special powers under Article 142 of the Constitution, it imposed a majoritarian peace by pushing away the mosque to an alternative site and letting a temple be built on the original site.

Thus, all three assumptions listed above stood legally negated by the judgment that ran into over a thousand pages. Implicit in the judgment was the acceptance that the resolution of the Ayodhya dispute was to be treated as a one-off event and not as a precedent for further claims. However, the message that percolated down to the public was that the Supreme Court had upheld the building of a temple where a mosque once stood. Public perception, therefore, was that all mosques were, henceforth, fair game for conversion. What the courts did soon thereafter only added to the public perception. The Ayodhya judgment had barely been delivered that cases were filed for the conversion of mosques in Mathura and Varanasi. The mosque committees responded that the suits had to be dismissed because the Places of Worship (Special Provisions) Act of 1991 prohibited the change of character of any place of worship that existed as on August 15, 1947. The Act of 1991 had been upheld unanimously in the Ayodhya judgment.

Thus, in the fresh Gyanvapi dispute, when an order of the courts in Varanasi was carried to the SC, the court had an opportunity to nip the trouble in the bud. That was not to be. It was an ill-considered remark by presiding judge DY Chandrachud that the courts could still inquire into what the exact character of the place was on the first day of Independence — that gave a fresh life to the suit and let loose the dragon seeds of fresh hatred.

Running parallel to the Varanasi dispute was the dispute regarding the Eidgah in Mathura. Both suits were allowed by the SC to proceed and work their way through the court system. Some interim orders were also passed, depriving the Muslim side of the use of some portion of the facilities and allowing surveys to be done by the Archaeological Survey of India and various court commissioners. The upshot is that courts are now instruments of an Ayodhyaesque kar seva.

It may well be that the judges of the Supreme Court felt it to be safer for public passions to be expended in the long process of the Indian litigation. They possibly thought that the legal process would help a nation resolve uncomfortable questions from the past. What they did not perceive was that disputes about religious sites are not about religions but about nationalism itself. Are we a nation of unity in diversity or are we a unitarian civilisation? Journalist and author Nilanjan Mukhopadhyay, in his book on Ayodhya, The Demolition and the Verdict, writes: "...'inclusive' or 'multiple sub-nationalisms' (region and religion) were amalgamated into pan-Indian nationalism by the Congress, especially with the advent of Gandhi.

Shaky Dhaka needs a helping hand

EVER since a popular revolt overthrew the government of Sheikh Hasina in Bangladesh, the country has been rocked by violence and disorder. The minority Hindu community there has been targeted. New Delhi has expressed strong concerns about these incidents to...

EVER since a popular revolt overthrew the government of Sheikh Hasina in Bangladesh, the country has been rocked by violence and disorder. The minority Hindu community there has been targeted. New Delhi has expressed strong concerns about these incidents to Dhaka, saying that the primary responsibility for the safety and security of "all citizens of Bangladesh, including minorities, rests with the Government of Bangladesh".

Developments in the country can be seen in two ways. First, after the iron hand of Hasina's Awami League government has been lifted, the country is reverting to a situation of semianarchy, with the Islamists and Pakistan's ISI (Inter-Services Intelligence) holding sway and the Hindu minority being persecuted. The second approach would be to consider that Bangladesh is going through a temporary phase in which the country, which did not have real democracy for the past decade, is trying to find its feet under the aegis of an interim government.

angladesh is perhaps the most consequential neighbour of India in South Asia, being 'India-locked' — of its 4,367-km land boundary, just 271 km is with Myanmar and the remaining 4,096 with India. It borders Tripura, Mizoram, Assam, Meghalaya and West Bengal and holds the key to the economic development as well as security of our northeastern region.

Given the nature of the Bangladesh border, it is difficult to completely seal it; as a result, the policies of various governments of the country have had a vital bearing on our security. India's relations with Bangladesh have seen ups and downs. Beginning with India's role in helping Bangladesh emerge as an independent nation, it has been a rollercoaster ride for bilateral ties as dictators Ziaur Rahman and HM Ershad encouraged the Islamicisation of the country in a bid to maintain their control. As in Pakistan, the Jamaat-e-Islami (JeI) has played a significant role and grown in the process, despite the fact that it fought against the freedom movement of the country. But what happens in Bangladesh is not just about India but the wider region, including China, Myanmar and South-East Asia. The creeping radicalisation of its large Muslim population could have wider global consequences. Besides the JeI, there are other

radical groups, like the Harkat-ul-Jihad-al-Islami and the Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh, as well as elements of the al-Qaeda and the Islamic State. A network of madarsa leaders, Hefazat-e-Islam, too, wants Sharia rule in the country and is opposed to the establishment of a secular polity there. The JeI's alliance with the Bangladesh National Party (BNP), headed by Begum Khaleda Zia, has been a major



problem. As a result, her tenures as Prime Minister in 1991-96 and 2001-06 have been marked by problems arising out of the virtually free rein given to the ISI and the sanctuary provided to an assortment of insurgent groups active against India in the North-East.

The India-Bangladesh relationship stabilised with the establishment of Hasina's government in 2009. Most importantly, it helped check the use of Bangladeshi territory by anti-India elements, be it the ISI or various north-eastern insurgent groups. This led to the reopening of land routes connecting the two nations and signing of the Motor Vehicles Agreement by BBIN (Bangladesh, Bhutan, India and Nepal) to promote regional movement of traffic.China has developed significant interest in Bangladesh both as part of its larger policy of containing India as well as exploiting the country's

location at the head of the Bay of Bengal, next to the Rakhine state of Myanmar, where it has important investments and from where a pipeline carries oil from the port of Kyaukpyu to Yunnan in China, bypassing the Malacca Strait. Beijing has invested large amounts of money in constructing bridges, roads and power plants in Bangladesh and has also emerged as the biggest military supplier to the

country.For many of the reasons cited above, New Delhi needs to handle things with care in Bangladesh. It is true that the situation is extremely volatile and can go out of control, resulting in negative consequences for India. The situation is compounded by the fact that the ISI is likely to be working overtime to impose an anti-India narrative on the popular movement there.

India needs to draw lessons from its successful handling of strained ties with neighbours recently. By providing financial succour to Sri Lanka during its economic crisis, it has bought considerable goodwill, which is paying dividends with the government of Anura Kumara Dissanayake. Likewise, by calmly dealing with President Muizzu of Maldives, New Delhi has managed to blunt his "India out" strategy. Similar dividends are visible in

Nepal — the nominally anti-India Prime Minister KP Sharma Oli, who is on an official visit to China, had made it clear beforehand that his country would not sign any new loan agreement with Beijing under the Belt and Road Initiative (BRI). Indeed, the Nepalese want to sign a new agreement with China that will narrow the scope of BRI in their country.

With Bangladesh, too, India needs to adopt a policy of strategic patience. Bangladesh is a country in transition. New Delhi needs to support the process of restoring democracy there. There has been a tendency to exaggerate the attacks on Hindus. After an initial upsurge, such attacks have come down. We also must understand that our one-sided support to Hasina has resulted in suspicion about our motives and there is need to provide a corrective to our Bangladesh policy.

Population push

RSS chief Mohan Bhagwat has sounded the alarm. He has expressed concern over a paradoxical situation: population growth in the world's most populous country is on the decline. Painting an apocalyptic picture, Bhagwat has warned that a society whose total...

RSS chief Mohan Bhagwat has sounded the alarm. He has expressed concern over a paradoxical situation: population growth in the world's most populous country is on the decline. Painting an apocalyptic picture, Bhagwat has warned that a society whose total fertility rate (TFR) dips below 2.1 could disappear off the face of the earth. He has a solution: Hum Do Hamare Teen every couple should have at least three children. Does the RSS Sarsanghchalak want members of every community in the country — majority as well as minority -- to produce more kids? That seems unlikely, going by what Prime Minister Narendra Modi said at an election rally in Banswara, Rajasthan, in April. In a thinly veiled attack on a particular community, the PM had equated 'infiltrators' with "those who have more children".

Bhagwat is worried most probably because of the findings of a working paper released by the Economic Advisory Council to the PM a few weeks after Modi's controversial speech. It says that the share of Hindus in India's



population decreased by 7.82 per cent between 1950 and 2015, while that of Muslims increased by 43 per cent. The worst-case scenario for the RSS chief is the majority

community being reduced to a minority. Ironically, Health Minister JP Nadda, while addressing a meeting on World Population Day (July 11), stated that 'smaller families' could help India achieve the goal of Viksit Bharat.It's true that India's fertility rate has fallen significantly, in part due to a laudable rise in the contraceptive prevalence rate. A low TFR has prompted Andhra Pradesh to do away with its twochild policy, while Telangana is keen to follow suit. However, various states would be well advised to take stock of the resources available while reversing timetested family planning measures. Can they handle the additional demographic burden in terms of healthcare, education, job generation and poverty alleviation? It's tempting for political and religious leaders to play the numbers game and stoke communal fires, but they should not overlook the implications of such actions for India's long-term social and economic stability.

What holds back Punjab's draft agricultural policy

IAM often asked about my tenure as the Chairman of the Punjab State Farmers' & Farm Workers' Commission (April 6, 2017-September 20, 2021). On the very first day, without even a hint of guidance on what my work entailed, flummoxed...

IAM often asked about my tenure as the Chairman of the Punjab State Farmers' & Farm Workers' Commission (April 6, 2017-September 20, 2021). On the very first day, without even a hint of guidance on what my work entailed, flummoxed but undeterred, I sent a letter to the Department of Agriculture, asking it to provide information on pesticide, seed and fertiliser sample failures in the state.

The data — that would have taken a few hours to put together in the private sector — took two years of dogged perseverance and persuasive cajoling to get. It took six months just to get an officer from the department to assist the commission in its work. Having never worked in the government, the chase taught me a vital lesson: the real problem is not the government, it is the bureaucracy. That was lesson number one.o cut the long story short, the commission found many instances of pesticide, fertiliser and seed sample failures where no cases had been filed for the past 10 years or had been timebarred. Consequently, around 150 officers were charge-sheeted. I was informed that the officers had threatened to go on strike. However, the commission's aim was not to penalise anyone, which it ensured, but thereafter, compliance become 100 per cent. The same happened a little later when we proposed that the government create a price stabilisation fund for milk, food and vegetables by imposing a 20 per cent fee on the charges received by the arhtiyas for the procurement of grains for the FCI. The arhtiyas arrived, flexing their muscles. I told them that if they were to agitate at my doorstep, it would do good for the commission's image. However, they easily convinced the government to

ignore my advice.nitially, different departments were to brief me on their working and issues so as to understand how the system worked. Instead, the commission decided to visit all departments and meet the officers and junior staff in their respective offices. It proved to be an eye-opener. It led to the next

awakening: "inept governance" holds back progress. Consequently, in the draft agricultural policy, the first chapter is on 'governance'. It was the first-ever policy of any kind to identify governance as a problem and a solution. It was not palatable for many but, with time, my stand was vindicated. The commission only has an advisory role. Yet, I have regrets — not for the work I did, but about the decisions I did not make or was dissuaded from taking. It is hard to quantify all the work in brief here, but some laws that got enacted during my tenure were pathbreaking. I was doubtful that the then state Chief Minister, Capt Amarinder Singh, would agree to banning truck unions, but his administrative acumen being outstanding, truck unions were

banned. Though they kept operating in some places like Bathinda. That was the third learning: never be afraid to punch above your weight. On regulating the electricity subsidy to the economically better farmers, the CM was persuaded by his office not to tread the politically contentious path, even though the farmers' unions had concurred with this suggestion. I must acknowledge that farmers' union leaders were

supportive of the commission's efforts in policy

formation. Making the draft of Punjab state farmers

policy taught us the fourth valuable lesson: a

transparent consultation process is a fundamental

Additionally, we ensured that Punjab banned the sale of herbicide glyphosate, the only state to do so. There were other remarkable wins. In 2002, the

requirement for achieving positive policy outcomes.

government had allocated over 300 acres of land in Ladhowal near Ludhiana to a business group for a



measly Rs 2,000 per acre for supporting agriculture. On finding out that the land was not being used for the purpose, the commission submitted a report on the issue, based on which the group returned the land without litigation to the state. That was the fifth takeaway: success is only possible if one works as a team as the commission did; not as individuals.

My own experiences derived from my farm at Abohar helped me in my work at the commission. Agriculture college students train at our farm as a part of their degree course. Their practical knowledge is left wanting in many aspects. After joining the

commission, I was shocked to learn that unlike medical colleges that are regulated by the Union Government, agriculture colleges were not regulated. Agriculture is a state subject and the state did not have any such law. On the commission's suggestion, the state government enacted the Punjab State Council

for Higher Education Act 2017. Out of the 112 colleges in the state, the Punjab State Council for Higher Education (PSCAE) asked students to avoid taking admission in colleges offering BSc (agricultural) which were not fulfilling conditions under the Act. It also released a list of the institutes that complied with the minimum standards prescribed. The list had only 15 names. The farm experience had also taught me about the difficulty of viably operating a greenhouse. We decided to list each greenhouse subsidised by government agencies. To its shock, the commission documented that over 90 per cent greenhouses had stopped operating within three to four years. There were many other

such instances. The commission had a similar experience on the suo motu inquiry report on canal water pollution in the Beas river from the Chadha distillery spill. The sixth learning was that the system tends to turn a blind eye to failures and evidencebased research should influence the policy and action. We, thus, recommended that actual beneficiaries be allowed to assess the programme outcomes. When the commission reached out to district headquarters to follow up on the rehabilitation of families affected by farmers' suicide, it found that, like other laws, it was not even on their agenda.

Government has kept banks stable in last 10 years, says Finance Minister Nirmala Sitharaman

NEW DELHI. Finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday said the Indian banking system is critical to the growth of the nation and the government in the last 10 years has been extremely cautious so that banks remain stable."The intention is to keep our banks safe, stable, healthy, and after 10 years you are seeing the outcome," the finance minister said while replying to a debate on the Banking Laws (Amendment) Bill, 2024 in Lok Sabha. Today the banks are being professionally run, the public sector banks are safe, stable and healthy, and have performed exceptionally well in recent years. She added that the metrics of the banks are healthy so they can go to the market and raise bonds, raise loans and run their business accordingly.

She informed the lower house of parliament that total bank branches of scheduled commercial banks have increased by 3,792 in a year to reach 16,55,001 in September 2024. Out of this 85,116 branches are of public sector banks.

5.5 million customers port numbers to BSNL after private telcos hiked tariff

NEW DELHI. Nearly 5.5 million mobile users (till October 2024) ported their numbers to the stateowned Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) after the tariff hikes announced by private telecom service providers in June 2024.

As per data from the Department of Telecommunications (DoT), there was a major rise in customer migrations from other telcos to BSNL from July to October 2024 period. In July 2024, BSNL saw 1.5 million users joining its network from Reliance Jio, Bharti Airtel, and Vodafone Idea (VIL). This number rose to 2.1 million in August, 1.1 million in September, and 0.7 million in October 2024.In contrast, BSNL experienced only 63,709 port-ins in June 2024, prior to the tariff hikes. At the same time, the number of customers leaving BSNL to switch to other networks had been higher in June 2024, with nearly 0.4 million users porting out. Following the tariff hikes, the rate of customer churn significantly decreased. By July 2024, only 0.31 million users left BSNL, and this number further dropped to 0.26 million in August, 0.28 million in September, and 0.51 million in October 2024.

Overall, the number of customers joining BSNL far outpaced those leaving the network during this period, with many consumers opting for the state-run operator. Additionally, BSNL experienced a surge in new SIM card sales. The company sold just 790,000 SIM cards in June 2024, but this number jumped to 4.9 million in July 2024, 5 million in August 2024, 2.8 million in September, and 1.9 million in October 2024. Meanwhile, the telecom industry saw a decline in subscriber numbers. As per the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), telcos collectively lost 10 million users in September 2024. Jio lost 7.9 million, Airtel lost 1.4 million, and VIL lost 1.5 million subscribers during the month. Robert Ravi, Chairman and MD of BSNL, stated that the company has no plans to increase its tariffs in the near future.

India's Affordable Housing Market To Reach Rs 67 Lakh Cr By 2030, Demand At 31.2 Mn Units

New Delhi. India's affordable housing market is projected to reach Rs 67 lakh crore by 2030, with cumulative demand likely to be 31.2 million units, a report showed on Wednesday. The existing shortage as well as upcoming demand for the affordable housing segment in India is estimated to be 30.7 Mn units by 2030 and the opportunity to finance these units is calculated to be Rs 44 lakh crore, according to the report by Knight Frank India

Led by factors such as urbanisation and employment opportunities, 22.2 million units of housing will be required in urban centres in the country. Almost 95.2 per cent of this demand, equivalent to 21.1 million units, will be concentrated in the affordable housing segment, the report mentioned.

A predominant share of 45.8 per cent of the demand will be concentrated among the economically weaker section (EWS) households as there is already an existing shortage of 10.1 million units. The current portfolio of the affordable housing loan market in India is estimated to be Rs 13 lakh crore, with Housing Finance Companies (HFCs) constituting Rs 6.9 lakh crore and Scheduled Commercial Banks (SCBs) holding a share of Rs 6.2 lakh crore.

As urbanisation accelerates and income levels rise, affordable housing is positioned to play a pivotal role in shaping the country's real estate landscape," Knight Frank India Chairman and Managing Director, Shishir Baijal, said.

Addressing this demand will require innovative strategies, including public-private partnerships, policy interventions, and advancements in construction technologies, making affordable housing not just a social imperative but also a critical driver of economic growth, he added. The loan market in this category is anticipated to experience significant expansion due to the escalating potential demand for affordable housing. The reliance on loans is notably high in the affordable housing segment as compared to premium in India.Based on an assumption of a 77 per cent loan dependency and loan-to-value (LTV) ratios applied at various loan thresholds, the potential financing opportunity for banks and Housing Finance Companies (HFCs) in the affordable housing segment is estimated to be Rs 45 lakh crore, said the report.

IndiGo takes Mahindra to court over use of '6e' name

NEW DELHI. IndiGo has filed a trademark infringement suit against Mahindra Electric Automobile, objecting to the latter naming its upcoming EV as BE 6e as "6E" is the airline's flight code. Mahindra launched the electric car on Nov 26, with company officials insisting then there is no copyright infringement with use of 6e.Indigo went to the court within days. Titled Interglobe Aviation (IndiGo parent) vs Mahindra Electric Automobile, the case was on Tuesday listed to be heard in the court of Justice Amit Bansal. However, the judge recused himself from hearing the matter. The next hearing is scheduled for Dec 9. Appearing for IndiGo, senior advocate Sandeep Sethi informed the court that Mahindra had initiated discussions with the airline to address the issue.In a statement, IndiGo said: "6E mark is an integral part of IndiGo's identity for the past 18 years and is a registered trademark that holds strong global recognition. The 6E mark,



whether standalone or in its variants and formative forms, is extensively used by IndiGo for its offerings and for goods and services provided in collaboration with trusted partners."The airline further said, "Any unauthorised use of the '6E' mark,

whether standalone or in any form, constitutes an infringement of IndiGo's rights, reputation and goodwill. IndiGo is committed to taking all necessary and appropriate steps to safeguard its intellectual property and brand identity."

Mahindra said it revealed EV SUVs - the BE 6e and XEV 9e - late last month. "Mahindra has applied for trade mark registration under class 12 (vehicles) for 'BE 6e' a part of its electric origin SUV portfolio. We hence don't see a conflict as Mahindra's mark is 'BE 6e,' not the standalone '6E.' It differs fundamentally from IndiGo's '6E,' which represents an airline, eliminating any risk of confusion..." The distinct styling further emphasises their uniqueness. We have taken on board the concerns that InterGlobe Aviation Limited have to infringement of their goodwill, which was not our intention. We are engaged in discussions with them to find an amicable solution."This is the second time IndiGo is locked in a legal battle with some other company using a name associated with it. In 2015, the airline had a trademark dispute with Tata Motors which then used to sell its sedan under the name IndiGo.

NTPC Green Energy shares

climb 44% post-listing.

What's driving the rally

NEW DELHI. Shares of NTPC Green Energy, a

commendable surge in prices since their listing.

The stock, which debuted on the stock exchanges

on November 27, has climbed steadily and is now

trading 44% higher than its IPO price of Rs 108, with a fresh all-time high of Rs 155.35 per share on December 4. NTPC Green Energy shares had

hit the 10% upper circuit limit in the previous session.NTPC Green Energy shares were trading

at Rs 147.45, up 3.76%, at the time the article was

being written. Despite starting off modestly on its listing day, NTPC Green Energy shares have quickly gained momentum in subsequent trading

sessions. Analysts attribute the rally to the

company's strong fundamentals and its prominent position in India's renewable energy

subsidiary of NTPC Limited, have witnessed a

Swiggy likely to increase delivery charge on Instamart orders: Report

NEW DELHI. Food and grocery delivery platform Swiggy is considering increasing the delivery fees for its quick commerce arm, Instamart, reported moneycontrol.com.The move aims to improve profitability, according to Chief Financial Officer (CFO) Rahul Bothra, who discussed the plan with analysts after the company announced its Q2 FY25 results on December 3.

Currently, Swiggy subsidises delivery fees through its loyalty program, Swiggy One, and discounts for new users. While delivery is free for Swiggy One members, other customers pay a dynamic fee. Bothra indicated that the company plans to raise these charges



gradually but did not specify a timeline. The competitive quick commerce sector includes players like Zomato-owned Blinkit and Zepto. free delivery for any orders, while Zepto waives fees for loyalty program members.Bothra also highlighted additional measures to boost margins, including increasing platform fees for food delivery orders and monetising Instamart through advertisements.

wiggy has already raised its platform fee fivefold, from Rs 2 to Rs 10 per order, in the past 18 months. The company intends to improve its take rates (commissions) for Instamart from the current 15% to 20-22%.Instamart recorded adjusted revenue of Rs 513 crore in Q2 FY25, more than double the Rs 240 crore earned in the same period last year. However, it still trails Blinkit, which reported revenue of Rs 1,156

crore during the quarter. Unlike Swiggy, Blinkit does not offer At the company level, Swiggy's revenue rose 30% year-on-year to Rs 3,601.5 crore for Q2 FY25, while its losses narrowed to Rs 625.5 crore from Rs 657

sector, which is poised for good growth. The company launched a Rs 10,000 crore IPO last month, which was open for subscription between November 19 and November 22. The issue



December tax deadlines: Your essential guide for ITR compliance

NEW DELHI. As the year comes to a close, December becomes a vital month for taxpayers to fulfil important financial and compliance duties. It is the time to claim deductions, make The deadline for submitting Form 24G advance tax payments, and file returns, ensuring all tax responsibilities

are wrapped up before the year

Failing to meet these deadlines can lead to penalties, which makes early planning essential. Staying on top of the crucial deadlines in December 2024 is key to ensuring smooth compliance and taking full advantage of available tax benefits.By understanding the key dates, taxpayers can avoid

last-minute stress and ensure they complete all obligations on time. Here's a look at the important income tax deadlines to keep in mind for the

DECEMBER 7, 2024

The last date to deposit tax deducted or collected for the month of November 2024. However, all taxes deducted or collected by a government office must

be credited to the Central Government on the same day if no Income-tax Challan is used for payment.DECEMBER 15, 2024

by government offices for TDS/TCS



payments made without a challan for the month of November 2024.

The third instalment of advance tax for The final date to file belated or revised

the assessment year 2025-26. The due date to issue TDS Certificates for deductions made in October 2024 under sections 194S (for specified By adhering to these deadlines, persons), 194-IA, 194-IB, and 194M.The deadline for filing Form 3BB by stock exchanges for modified client codes for the month of

December 2024 holds critical tax deadlines for advance payments, returns, and deductions. Stay on track with key dates to avoid penalties.

November 2024. **DECEMBER 30, 2024**

Last date to furnish challan-cumstatements for tax deductions for the month of November 2024 under sections 194S (specified persons), 194-IA, 194-IB, and 194M.

income tax returns for AY 2024-25, provided assessments are not completed by December 31, 2024.

taxpayers can avoid penalties, stay compliant, and wrap up their tax obligations efficiently before the year received strong investor interest, being oversubscribed 2.55 times.

INDIA'S LEADING RENEWABLE ENERGY

NTPC Green Energy is India's largest renewable energy public sector enterprise, excluding hydro projects, based on operating capacity and power generation as of September 30, 2024.

According to a CRISIL report, the company's solar and wind power assets spread across more than six states, helping mitigate risks related to location-specific variability in power generation. The company's operational capacity consists of 3,220 MW of solar projects and 100 MW of wind projects. In addition, it has a contracted and awarded capacity of 13,576 MW and a total portfolio, including pipeline projects, of 26,071 MW.With 17 offtakers across 41 solar projects and 11 wind projects, NTPC Green Energy has built a robust customer base, primarily from public sector undertakings (PSUs) and Indian corporates.NTPC Green Energy has a clear focus on expanding its utilityscale renewable energy projects. It has been actively working on developing large-scale projects, catering to the growing energy needs of public and private sector entities in India.

Sebi cancels SME IPO of Trafiksol ITS Technologies, orders to refund money

The IPO which was open for subscription between September 10 and 12, 2024 oversubscribed 345.65 times. The issue was priced at the upper end of the price band (Rs 70 per share) and Rs 44.87 crore was raised through the issue.

NEW DELHI. Market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi) has cancelled the SME IPO of Trafiksol ITS Technologies and asked the company to refund the money to the investors for alleged questionable dealings with a 'shell entity'. The IPO which was open for subscription between September 10 and 12, 2024 oversubscribed 345.65 times. The issue was priced at the upper end of the price band (Rs 70 per share) and Rs 44.87 crore was raised through the issue.

After the closure of the issue and allotment of shares, a complaint was received by

SEBI and BSE from the Small Investors' Welfare Association - SIREN which alleged that the objects of the issue by the company included purchase of software valued at Rs 17.70 crore from a vendor which had questionable financials and failed to file its annual financial statements with the Ministry of Corporate Affairs. The BSE then in consultation with the SEBI deferred the listing of the shares of the company."Based on the findings, it is reasonable to conclude that the third-party vendor (TPV) in question is a 'shell entity'. The TPV's office was found locked during a site inspection, and its financial statements for FY22 to FY24, submitted in response to allegations, were obtained under questionable circumstances as it was signed by the auditor on same day it was submitted to the BSE by the MB (merchant banker)," Sebi said in its 16-page order. This was one day after BSE in consultation with Sebi put on hold the listing of the shares of the company and initiated an examination. "Further, the client list and credentials of its directors, presented in its profile, were fabricated. Apart from the above, the ex-director's sworn statement



that the company was sold for a nominal sum of Rs. 20,000 reinforces the conclusion that the TPV lacked the technical expertise and operational capacity to execute a complex project such as ICCC software," Sebi said. Further, the client list and credentials of its directors, presented in its profile, were fabricated. Apart from the above, the ex-director's sworn statement that the company was sold for a nominal sum of Rs 20,000 reinforces the conclusion that the TPV lacked the technical expertise and operational capacity to execute a complex project such as ICCC software, Sebi order said."The question of whether the quotation from the TPV was part of a scheme to divert IPO proceeds will remain moot due to the events triggered

by the complaint and subsequent regulatory intervention. This, however, does not take away the fact that the company relied on a sham entity and participated in a cover-up when the credentials of the TPV were being examined," Sebi said.I cannot also lose sight of the fact that the funds of the investors who have been allotted shares in the IPO have remained locked-in for close to three months now. Therefore, the issue cannot be put on hold till the other findings of the Investigation are adjudicated," Sebi Wholetime Director Ashwani Bhatia said in the order. Balancing these considerations, the most prudent course of action is to direct the company to refund the money raised through the IPO, Sebi said.

The company may approach the market afresh after the ongoing proceedings initiated by SEBI are concluded and subject to any directions issued therein, it said. I cannot also lose sight of the fact that the funds of the investors who have been allotted shares in the IPO have remained locked-in for close to three months now. Therefore, the issue cannot be put on hold till the other findings of the Investigation are adjudicated.

Thursday, 05 December 2024

"Respectfully Disagree": Congress MP Vs Narayana Murthy On Work-Life Balance

New Delhi. After Infosys co-founder Narayana Murthy reignited debates on work-life balance, Congress MP Gaurav Gogoi on Wednesday responded and expressed his disagreement to the tech tycoon's statement supporting grinding, relentless work hours---an 'overwork culture.'Gaurav Gogoi countered Narayana Murthy's beliefs of work-life balance as an indulgent myth and highlighted the perspective where the traditional division of labor between men and women in the household is being Mr Gogoi describes life not only challenged, in context to work-life balance.Mr Gogoi shared his disagreement with Narayan Murthy's view on work-life balance, who is known for his strong stance on the importance of work-life balance.

Gaurav Gogoi suggested that the concept of a "work-life balance" is not as straightforward or achievable for everyone, especially women. Taking to his official handle on X, Mr Gogoi posted, "I also disagree with the view of Narayan Murthy on work-life balance. After all what is life but looking after your children, cooking for them, teaching them, taking care of your elderly parents, being there for your friends in their times of need, making sure that your house in order. The above is just as much a man's job as it is a women's."

in terms of professional work but also as a combination of

various personal responsibilities--raising children, caring for elderly parents, managing the household, and supporting friends. This paints a picture of life as a balancing act between multiple roles, all of which are demanding and require time and energy.Mr Gogoi points to an egalitarian view where both men and women share the burden of maintaining



the household and raising children. His post further read, "Traditionally working women don't even have the choice to cut away life from work.It is a luxury that traditionally men have and one that they have to forego in the modern world."Mr Gogoi suggests that in the modern world, men no longer have the same luxury of "cutting away life from work," implying that both men and women are now

required to manage work and life responsibilities more equally, and that the concept of work-life balance is a challenge for everyone, not just women. Mr Gogoi calls for a more equitable sharing of all roles within the family and workplace. His response comes after a user on X shared an open letter to Narayana Murthy, respectfully disagreeing with his opinion on work life balance.

'I respectfully disagree with you sir on work life balance. Employees are not slaves. Working longer

hours doesn't mean better productivity. Several countries have switched to a 4 day work week and are doing better. Women don't have the luxury of working 70/80 hours a week either," shared the user on X with an attachment of the letter. Narayana Murthy at the CNBC Global Leadership Summit championed a 70-hour workweek as essential for India's economic rise.

BJP forms committees to strategise on Delhi assembly election campaign

With the upcoming election, the saffron party is leaving no stone unturned in its efforts to win.

NEW DELHI. Ahead of the Delhi assembly elections scheduled for February 2025, the Delhi BJP has set up 47 committees, comprising former and current leaders, sitting MPs, and former ministers, to shape the party's election campaign. The committees will focus on key areas, including manifesto preparation, outreach to women, youth, Scheduled Castes (SCs), Other Backward Classes (OBCs), Poorvanchalis, and beneficiaries of central government schemes.

The BJP, which has not been in power in Delhi since 1998, faces a tough challenge after consecutive defeats to Congress in 1998, 2003, and 2008, and to AAP in 2015 and 2020. With the upcoming election, the saffron party is leaving no stone



unturned in its efforts to win.

In mid-November, the BJP formed its Election Steering Committee, which includes prominent members like Delhi BJP president Virendra Sachdeva, Union minister Harshdeep Malhotra, BJP national general secretary Dushyant Gautam, MPs Manoj Tiwari, Arvinder Singh Lovely, Kailash Gahlot, Dr Harsh Vardhan, Ramvir Singh Bidhuri, Vijender Gupta, Satish Upadhyay, Yogendra Chandolia, Kamaljeet Sehrawat, Bansuri Swaraj, and Praveen Khandelwal. Baijayant Panda, BJP's national vice president, has been appointed as the election in-charge, with Atul Garg, MP from Ghaziabad, serving as coincharge. The state unit has also formed a 12member manifesto committee, headed by former south Delhi MP Ramesh Bidhuri, with members including Dr Harsh Vardhan, Arvinder Singh Lovely, Vijay Goel, Satish Upadhyay, Meenakshi Lekhi, and Pravesh Sahib Singh Verma. Additionally, the party has set up a Parivartan Yatra committee to manage its padyatra, which will commence soon. An 11-member Aarop Patra committee (state chargesheet committee) has been constituted to target the AAP-led Delhi government. The committee, led by Leader of Opposition (LoP) in the Delhi assembly Vijender Gupta, includes former MP Ramesh Bidhuri, Manjinder Singh Sirsa, RP Singh, former Delhi mayor Aarti Mehra, LoP in MCD Raja Iqbal Singh, and Kapil Mishra, among others. A senior Delhi BJP leader said, "The BJP is committed to serving the people."

Three of a family stabbed to death in Delhi's Neb Sarai

NEW DELHI. Three members of the same family were stabbed to death at their residence in South Delhi's Neb Sarai area in the early hours of Wednesday.

The deceased individuals were identified as Rajesh (55), Komal (47), and their daughter Kavita (23). According to officials, the police rushed to the spot after receiving the information on the incident around 5.30 a.m. Their son found the bodies lying in the house after he returned from a morning walk, preliminary enquiries revealed. The cops have cordoned off the entire area and the forensic teams are scanning the crime scene.

Meanwhile, strongly reacting over the incident former Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal once slammed



the BJP-ruled central government over the deteriorating law and order situation."Three murders in the same house in Neb Sarai.... This is extremely painful and frightening. Every day Delhiites wake up to such frightening news" Kejriwal posted on X.

'Homes are being destroyed, innocent lives are being lost. Those who are responsible are silently watching it happen. Will the Central government keep quiet and watch the law and order situation in Delhi collapse? Will his party still say that crime is not an issue in Delhi?," the AAP convener questioned.He also alleged that the criminals have been given a free hand

Security remains 'unsatisfactory' at Delhi hospitals: AIIMS RDA chief

NEW DELHI. Months after junior doctors across the country went on strike following the brutal rape and murder of a female colleague in Kolkata, security measures at Delhi's government hospitals remain inadequate. The tragic incident sparked nationwide outrage and calls for a central law to protect healthcare workers, alongside demands for better security, workplace conditions, and swift legal action against those who harm medical professionals.

In Delhi, the Resident Doctors Associations (RDAs) of seven government hospitals led the protests. However, despite several promises from authorities, doctors continue to express dissatisfaction with the progress made."The improvement in security measures is far from satisfactory, even after four months," said Dr Rajat Sharma, president of the RDA at Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital. Recent incidents highlight the risks healthcare workers still face. At Safdarjung Hospital, an IPS officer verbally assaulted a resident doctor, while at GTB Hospital, a crowd barged into the duty room and threatened to kill a medical intern.

Just a few days ago, the administration fast-tracked a proposal to enhance security measures, but only after repeated reminders. This reflects their lack of seriousness in addressing workplace violence," Dr. Sharma added.

Dr Sarada Prasad Sahoo, president of the RDA at Lady Hardinge Medical College, echoed similar concerns. While there has been a slight increase in the number of security guards, key demands, such as the deployment of marshals or bouncers in high-risk areas, remain unmet, said Sahoo."Merely increasing guards isn't enough. We have consistently asked for marshals, CCTV cameras, well-lit corridors, and female security staff for women doctors. Yet, the authorities' standard response is, 'the file is in process," the doctor added.Doctors continue to call for decisive action to ensure their protection, emphasizing that their ability to save lives depends on working in a safe and secure environment.

In an interview with Dr.Indra Shekhar Prasad, president of the RDA at the AIIMS Hospital, Ashish Srivastava discusses the most pressing issue and possible solutions. Excerpts.

Delhi government orders five-year CAG audit of women's university accounts

NEW DELHI. The Delhi Government has decided to conduct a Comptroller and Auditor General (CAG) audit of the accounts of the Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (IGDTUW) for five years, a statement issued by the chief minister's office said on Tuesday.Chief Minister Atishi has approved the audit to ensure financial accountability and transarency, the statement added.

Atishi said this decision will ensure transparency and accountability in the financial affairs of IGDTUW. "Through the audit, any irregularities or financial mismanagement will be identified and addressed," she added. The CM emphasised that improving the quality of education and ensuring efficient financial management are top priorities for the AAP government. "The CAG audit will guarantee that

taxpayers' money is utilised



appropriately and effectively," she added. The chief minister also noted that the audit will ensure a thorough examination of all financial university."This process will not only help curb financial mismanagement The CM emphasised that improving the but also introduce greater transparency across the system. The CAG audit will promote administrative transparency," she said.IGDTUW is an independent government engineering college in the national capital with Delhi L-G

VK Saxena serving as its chancellor. Last week, Saxena wrote to

Atishi over Comptroller and Auditor General (CAG) reports pending tabling in the Delhi Assembly, and called it unfortunate. The L-G said he had raised this issue with her predecessor, Arvind Kejriwal on several occasions and flagged the gross Constitutional "impropriety" of the government in this regard. He also reminded the

Delhi CM that the office of CAG has sent several reminders to my office requesting urgent action in this regard. transactions and expenditures of the Improving quality of education top priority: Atishi

> quality of education and ensuring efficient financial management are top priorities for the AAP government. "The CAG audit will guarantee that taxpayers' money is utilised appropriately and effectively," she

Man shot dead following dispute in Mangolpuri, Kejriwal calls out cops

The probe revealed that Pankaj was gunned down in front of his nephew when the three assailants began **firing** indiscriminately towards the duo. The nephew ran but Pankaj succumbed to his injuries.

NEW DELHI. A 19-year-old man was shot dead in the wee hours of Tuesday in the Mangolpuri area by three men who fired at least half a dozen bullets at him. The deceased, identified as Pankaj was a resident of X block in Mangolpuri and worked at a garment factory.DCP (Outer district) Sachin Sharma said they received information regarding a man being brought dead at a hospital following which a police team reached the hospital and enquired about the incident.

The probe revealed that Pankaj was gunned down in front of his nephew when the three assailants began firing indiscriminately towards the duo. The nephew ran but Pankaj succumbed to his injuries.Based on the nephew's statement, the police registered a case of murder against the accused. "The accused have been identified. Multiple teams are working to



nab the accused. Suspicious persons are being rounded up to know about the whereabouts of the accused," the DCP said. Former Delhi chief minister Arvind Kejriwal criticised the Delhi Police for deteriorating law and order situation in the capital. "Last night, a man was shot dead in Mangolpuri. Day before yesterday three murders happened in Delhi. Delhiites must raise their

voice against crime. The important thing is the safety of yourself and your family," he wrote on X.On Tuesday, the AAP chief met the grieving family of Manish, a young man who was brutally murdered by two boys in Shalimar Bagh area. "The situation has spiraled out of control—people are afraid to step out of their homes after sunset," he said, vowing to stand with Delhiites and fight for their safety.

Kejriwal expressed serious concerns over the way the police is handling the case. "A major concern is that evewitness Himanshu's official statement has not been taken and that the statement recorded in Himanshu's name is false. This clearly indicates that the police are trying to protect the culprits. It raises questions about whether the police are working under some external pressure or orders from higher

'No effective action': NGT pulls up officials for failing to restore ponds

▶The NGT noted that of the six ponds in dispute, five are under DDA's control and one is managed by DSIIDC

NEW DELHI. The National Green Tribunal (NGT) has summoned key officials, including the Delhi Development Authority (DDA) Vice-Chairman, the District Magistrate of West Delhi, and Delhi State Industrial and Infrastructure Development Corporation Managing Director over their failure to restore ponds in the national capital.A bench led by Justice Sudhir Agarwal expressed dissatisfaction with the lack of progress, stating that "no effective action has been taken" and no evidence was



provided to demonstrate steps toward restoring the ponds to their original state. The bench, which also includes expert member Afroz Ahmad, emphasised that the DM, as Chairperson of the District Wetland Committee under the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, is responsible for preventing damage, encroachment, or degradation of water bodies. The NGT noted that of the six ponds in dispute, five are under

DDA's control and one is managed by DSIIDC. Despite assurances from DDA's counsel on October 25, that restoration efforts were underway and substantial progress would be achieved in a month, no compliance report has been submitted. The tribunal criticised the lack of detailed information, stating, "We find no option... but to direct personal appearance of V-C, DDA, District Magistrate, West Delhi, and Managing

Director, DSIIDC before tribunal on the next date."The matter is scheduled for a hearing on December 13, with the NGT directing the authorities to present the current status and steps taken to restore the ponds. The case originated in May 2022 from a letter petition alleging the illegal filling of ponds and their conversion for other purposes, including road construction. The ponds in question include Shangushar, Guga, Johdi, Guhli, and the historic Shishuwala Talab. The NGT had ordered a joint committee of the Central Ground Water Authority, Delhi Pollution Control Committee, and District Commissioner, West Delhi, to report on the issue.

Encroachments persist

The NGT noted that of the six ponds in dispute, five are under DDA's control and one is managed by DSIIDC. Despite earlier directives, the applicant claimed in a November 7 submission that encroachments persist, with BSES Rajdhani Power Ltd allegedly constructing a fenced.

'Bangladesh Govt Has **Absolute Obligation To** Protect Its Hindu Minority': **US Congressman**

Can influential US lawmaker on Tuesday said the interim Bangladeshi government has an absolute obligation to protect the minority Hindu community in the country after the fall of the democratically-elected Sheikh Hasina-led government earlier this year. Over the weekend, Hindus from Bangladesh organised a rally at the White house demanding release of Chinmaya Das and protection for Hindus of Bangladesh.Bangladesh's interim government has an absolute obligation to protect its Hindu minority and meaningfully address the protests of thousands of minority Hindus in outcry over the recent wave of attacks and harassment," Congressman Brad Sherman said in a statement.Bangladesh's interim government has an absolute obligation to protect its Hindu minority and meaningfully address the protests of thousands of minority Hindus in outcry over the recent wave of attacks and harassment," Congressman Brad Sherman said in a statement.Based on the feedback we are getting from #Bangladesh, Hindu monk and civil rights defender Chinmoy Krishna Brahmachari, who has been incarcerated by the interim government, faces a serious threat to his life, in custody," he

US Embassy In South Korea Issues Emergency Alert To Its Citizens After Lifting Of Martial Law

World. Following the lifting of martial law in South Korea, the United States Embassy in the country issued an emergency alert to its citizens on Wednesday, warning that the situation is "fluid" and advising them to take safety precautions.

The embassy posted the emergency information on its website a day after South Korean President Yoon Suk Yeol declared martial law. It was, however, lifted hours later after the National Assembly voted to reject it. "Following President Yoon's announcement to lift the martial law declaration, the situation remains fluid," the embassy said.US citizens should anticipate potential disruptions. When in public, you should pay attention to your surroundings and exercise routine safety precautions," as per the posting. The embassy also advised US citizens to avoid areas of demonstration and to exercise caution near "large crowds, gatherings, protests, or rallies." Peaceful demonstrations can turn confrontational and escalate into violence, it further stated. The embassy also noted that it will cancel routine consular appointments for US citizens and visa applicants on Wednesday.

Gladiator for a night at the Colosseum Some Romans are up in arms

Rome. It has probably been centuries since Romans have been so feverish about happenings at the Colosseum, and it is not because of the recent release of the Ridley Scott "Gladiator" sequel. A plan by the Colosseum and Airbnb to give a select few people the chance to unleash their "inner gladiator" at the most visited site in Italy has caused an uproar among many Romans who say its demeans a treasured cultural icon.

Over two nights in May, a total of up to 32 people will learn the art of gladiator fighting at the ancient arena, taught by Roman history buffs who specialise in historical re-enactments. The project is a partnership between the Colosseum Archaeological Park and Airbnb, the accommodations booking platform, which donated \$1.5 million to spruce up a permanent exhibit inside the arena. The aim, Airbnb said, "was to support the Colosseum's ongoing conservation work to find new ways to inspire and educate visitors on the historical significance of this bygone era."But some Romans and cultural leaders have given the initiative an emphatic thumbs down. (Footnote: While the emperor made such a gesture to condemn a fighter in the original "Gladiator" movie, scholars are uncertain about the direction thumbs actually pointed in ancient arenas for such purposes.) "We're against transforming the Colosseum into a theme park," said Massimiliano Smeriglio, a member of Rome's City Council. "We're all in favour if a company decides to sponsor a monument or a restoration," he said, "but it shouldn't be necessary to get anything in exchange.'

Federico Mollicone, a lawmaker with the Brothers of Italy party of PM Giorgia Meloni, dismissed the criticism as the views of a "radical chic" element in Rome that treated the arena "as something sacred". The Colosseum, he pointed out, had been built for rough-and-tumble entertainment. The center-right govt this year passed a law that supports the promotion of historical reenactments.

Critics also raised questions about Airbnb's involvement at a time when many European cities are struggling to balance the needs of locals with a booming postpandemic tourist industry facilitated by accommodation platforms. This summer, the backlash against mass tourism saw protests in many cities, including Barcelona, Spain, and Athens, Greece. While Romans are frequently incensed by many issues in their city - everything from uncollected garbage to potholes - they can be particularly sensitive about the Colosseum. A kerfuffle erupted last year after Elon Musk challenged Mark Zuckerberg on social media to "a cage match", and it was rumored that the Colosseum could be the venue.

South Korea lifts president's martial law decree after lawmakers reject military rule

SEOUL. The president of South Korea early Wednesday lifted the martial law he imposed on the country hours earlier, bending to political pressure after a tense night in which troops surrounded parliament and lawmakers voted to reject military rule. President Yoon Suk Yeol, who appeared likely to be impeached over his actions, imposed martial law late Tuesday out of frustration with the opposition, vowing to eliminate "anti-state" forces as he struggles against opponents who control parliament and that he accuses of sympathizing with communist North Korea.Police and military personnel were seen leaving the grounds of parliament following the bipartisan vote to overrule the president, and the declaration was formally lifted around 4:30 a.m. during a Cabinet meeting.Parliament acted swiftly after martial law was imposed, with National Assembly Speaker Woo Won Shik declaring that the law was "invalid" and that lawmakers would "protect democracy with the people."In all, martial law was in effect for about six hours. The president's surprising move harkened back to an era of authoritarian leaders that the country has not seen since the 1980s, and it was

immediately denounced by the opposition and the leader of Yoon's own conservative party.Lee Jae-myung, leader of the liberal Democratic Party, which holds the majority in the 300-seat parliament, said the party's lawmakers would remain in the Assembly's main hall until Yoon formally lifted his order. Woo applauded how troops quickly left the Assembly after the vote.

"Even with our unfortunate memories of military coups, our citizens have surely observed the events of today and saw the maturity of our military," Woo said.

While announcing his plan to lift martial law, Yoon continued to criticize parliament's attempts to impeach key government officials and senior prosecutors. He said lawmakers had engaged in "unscrupulous acts of legislative and budgetary manipulation that are paralyzing the functions of the state."Jo Seung-lae, a Democratic lawmaker, claimed that security camera footage following Yoon's declaration showed that troops moved in a way that suggested they were trying to arrest Lee, Woo and even Han Dong-hoon, the leader of Yoon's People Power Party.Officials from Yoon's office and the Defense Ministry did not respond to



requests for comment early Wednesday. Seemingly hundreds of protesters gathered in front of the Assembly, waving banners and calling for Yoon's impeachment.

Some protesters scuffled with troops ahead of the lawmakers' vote, but there were no immediate reports of injuries or major property damage. At least one window was broken as troops attempted to enter the Assembly building. One woman tried unsuccessfully to pull a rifle away from one of the soldiers, while shouting "Aren't you embarrassed?"Under South Korea's constitution, the president can declare martial law during "wartime, war-like situations or other comparable national of military force to maintain peace and order. It was questionable whether South Korea is currently in such a

When martial law is declared, "special measures" can be employed to restrict freedom of press, freedom of assembly and other rights, as well as the power of courts. The constitution also states that the president must oblige when the National Assembly demands the lifting of martial law with a majority

vote.ollowing Yoon's announcement of martial law, South Korea's military proclaimed that parliament and other political gatherings that could cause "social confusion" would be suspended, South Korea's Yonhap news agency said. The military said anyone who violated the decree could be arrested without a warrant.In Washington, the White House said the U.S. was "seriously concerned" by the events in Seoul. A spokesperson for the National Security Council said President Joe Biden's administration was not notified in advance of the martial law announcement and was in contact with the South Korean government.

Hamas, Fatah near agreement on who will oversee postwar Gaza

CAIRO. Palestinian officials say Fatah and Hamas are closing in on an agreement to appoint a committee of politically independent technocrats to administer the Gaza Strip after the war. It would effectively end Hamas' rule and could help advance ceasefire talks with Israel.The rival factions have made several failed attempts to reconcile since Hamas seized power in Gaza in 2007. Israel has meanwhile ruled out any postwar role in Gaza for either Hamas or Fatah, which dominates the Western-backed Palestinian Authority.A Palestinian Authority official on Tuesday confirmed that a preliminary agreement had been reached following weeks of negotiations in Cairo. The official said the committee would have 12-15 members, most of them from Gaza.It would report to the Palestinian Authority, which is headquartered in the Israeli-occupied West Bank, and work with local and international parties to facilitate

humanitarian assistance and

reconstruction.A Hamas official said

that Hamas and Fatah had agreed on the

general terms but were still negotiating

over some details and the individuals who would serve on the committee. The official said an agreement would be announced after a meeting of all No Palestinians have publicly Palestinian factions in Cairo, without providing a timeline.Both officials



spok on condition of anonymity because they were not authorized to brief media on the talks. There was no immediate comment from Israel.Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has vowed to continue the war until Hamas is dismantled and scores of hostages are returned. He says Israel will maintain open-ended security administered by local Palestinians unaffiliated with the Palestinian Authority or Hamas.

volunteered for such a role, and Hamas has threatened anyone who cooperates

with the Israeli military. The United States has called for a revitalized Palestinian Authority to govern both the West Bank and Gaza ahead of eventual statehood. The Israeli government, which is opposed to Palestinian statehood, is reportedly discussing a postwar plan with the United Arab Emirates, which normalized relations with Israel in 2020 and backs a rival Fatah faction.he Hamas official said the emerging Palestinian agreement would fulfill one of Israel's war goals

by ending Hamas' rule in Gaza. It's unclear if Israeli officials would see it that way. The Palestinian Authority, which administers parts of the occupied West Bank, recognizes Israel and cooperates with it on security matters, a policy that is deeply unpopular among Palestinians, many of whom view it as a subcontractor of

Trump's pick Chad Chronister withdraws from DEA nomination, cites commitment to local duties

World. Sheriff Chad Chronister of Hillsborough, US President-elect Donald Trump's pick for the role of Administrator of the US Drug Enforcement Administration (DEA), has withdrawn his candidacy, citing his ongoing commitment to local initiatives."To have been nominated by President-Elect @realDonaldTrump to serve as Administrator of the Drug Enforcement Administration is the honour of a lifetime," Chronister wrote in an X post on Wednesday.

Over the past several days, as the gravity of this very important responsibility set in, I've concluded that I must respectfully withdraw from consideration. There is more work to be done for the citizens of Hillsborough

added.Chronister expressed gratitude for the nomination and vowed to continue serving as sheriff. However, the announcement has sparked mixed reactions. District 1 Lake County Commissioner Anthony Sabatini called the withdrawal a "huge win for liberty," while Republican Congressman Thomas Massie of Kentucky criticised Chronister's past actions during the COVID-19 pandemic."This sheriff ordered the arrest of a pastor for holding services during the COVID panic. He was tapped by Trump to head the DEA. Glad to see him withdraw from consideration. Next time politicians lose their ever-lovin minds, he can redeem himself by following the

Browne, pastor of The River at Tampa Bay Church, for holding in-person services in violation of public health orders. At the time, Chronister defended the decision, "Announcing the arrest of Dr. Ronald Howard-Browne... who intentionally and repeatedly disregarded state and local public health orders, which put his congregation and our community in danger.," he said. The charges were later droppedSome conservatives, including commentator Liz Wheeler. criticised Chronister's nomination. "Chad Chronister is a COVID tyrant who arrested a Christian pastor... Chronister abused his power; he's unfit to lead the DEA," Wheeler wrote on

US President-Elect Donald Trump's Lawyers Urge Judge To Toss His Hush **Money Conviction**

World. President-elect Donald Trump's lawyers formally asked a judge Monday to throw out his hush money criminal conviction, arguing continuing the case would present unconstitutional "disruptions to the institution of the Presidency."In a filing made public Tuesday, Trump's lawyers told Manhattan Judge Juan M. Merchan that dismissal is warranted because of the "overwhelming national mandate granted to him by the American people on November 5, 2024."They also cited President Joe Biden's recent pardon of his son, Hunter Biden, who had been convicted of tax and gun charges. "President Biden asserted that his son was selectively, and unfairly, prosecuted,' and treated differently,'" Trump's legal team wrote. The Manhattan district attorney, they claimed, had engaged in the type of political theater "that President Biden condemned."Prosecutors will have until Dec. 9 to respond. They have said they will fight any efforts to dismiss the case but have indicated a willingness to delay the sentencing until after Trump's second term ends in 2029. In their filing Monday, Trump's attorneys dismissed the idea of holding off sentencing until Trump is out of office as a "ridiculous suggestion." Following Trump's election victory last month, Merchan halted proceedings and indefinitely postponed his sentencing, previously scheduled for late November, to allow the defense and prosecution to weigh in on the future of the case. He also delayed a decision on Trump's prior bid to dismiss the case on immunity grounds. Trump has been fighting for months to reverse his conviction on 34 counts of falsifying business records to conceal a \$130,000 payment to porn actor Stormy Daniels to suppress her claim that they had sex a decade earlier. He says they did not and denies any wrongdoing. Taking a swipe at Bragg and New York City, as Trump often did throughout the trial, the filing argues that dismissal would also benefit the public by giving him and "the numerous prosecutors assigned to this case a renewed opportunity to put an end to deteriorating conditions in the City and to protect its residents from violent crime."Clearing Trump, the lawyers added, would also allow him to "to devote all of his energy to protecting the Nation." The defense filing was signed by Trump lawyers Todd Blanche and Emil Bove, who represented Trump during the trial and have since been selected by the president-elect to fill senior roles at the Justice Department.A dismissal would erase Trump's historic conviction, sparing him the cloud of a

X.Senator Markwayne Mullin of Constitution," Massie wrote on X.Chronister faced backlash in 2020 Oklahoma defended Chronister, "What County and a lot of initiatives I am for arresting Dr. Ronald Howarddisqualifies somebody. committed to fulfilling," he criminal record and possible prison sentence.

after nearly 14 months of war, Palestinians describe long days hunting for flour and bread in the conflict-ravaged Gaza Strip. Every morning crowds form outside Nothing in markets"I walked about eight the few bakeries open in the Palestinian territory, as people desperately try to get a bag of bread at distribution points. Since the outbreak of war in Gaza last year, charities and international aid organisations have repeatedly warned of crisis levels of hunger for nearly two million people.A United Nations-backed assessment last month warned of famine looming in the northern Gaza Strip amid a near-halt in food aid after Israel launched an offensive in the area. Essential goods like water, fresh produce and medicines are also scarce.

Gazans across the territory have told AFP in recent months how they wake up at the crack of dawn just to ensure they can get some flour or bread, with current availability reaching an all-time low.

In the southern city of Khan Yunis, AFP photographers saw dozens of people at a distribution point, bodies pressed against each other. Over each other's heads, everyone tries to reach out as far as possible to grab the round bread.

World Faced with major food shortages A small child, her face covered in tears, squeezes a coin between her fingers as she makes her way through the crowd of

> kilometres (five miles) to get bread," Hatem Kullab, a displaced Palestinian living in a neighbourhood of makeshift tents, told AFP.It was in the middle of one of these crowds that two women and a child were trampled to death in a stampede at a bakery in the central Gazan city of Deir el-Balah Friday."To get a loaf of bread you need a whole day of eight to 10 hours," said the brother of one of the women killed, describing his sister's ordeal as she tried to get bread to feed 10 family members."The suffering that my sister went through is suffered by all the Palestinian people," Jameel Fayyad told AFP, criticising what he described as poor management of the bakeries. Fayyad's anger was largely directed at Israel, but he also blamed the World Food Programme (WFP) and "traders who want to make money on the backs of people". Palestinians from across the Gaza Strip told AFP journalists that it is extremely difficult to find the 50-kilogram (110 pounds) bags of flour that would last



them several weeks before the war."There is no flour, no food, no vegetables in the markets," Nasser Al-Shawa, 56, said, who, like most residents, was forced to leave his home because of the bombings and lives with his children and grandchildren in central Gaza.Shawa, who now lives in a friend's house in Deir el-Balah, says a 50kilogram bag costs between 500 and 700 shekels (\$137 and \$192). Before the war, it cost around 100 shekels. Inside Gaza where more than half of the buildings have been destroyed, the production is at an almost complete standstill. Flour mills, warehouses storing flour and industrial bakeries are unable to function because they have been so heavily damaged by

strikes.Bullet to the headHumanitarian aid is trickling in but aid groups have repeatedly slammed the many constraints imposed on them by Israel, which the country denies. In the latest blow, the UN agency supporting Palestinian refugees (UNRWA) announced Sunday it was halting aid deliveries to Gaza via a key crossing point with Israel.UNRWA said delivery had become impossible, partly due to looting by gangs.

For Layla Hamad, who lives in a tent with her husband and seven children in southern Gaza's Al-Mawasi, UNRWA's decision was "like a bullet to the head". She said her family had regularly received "a small quantity" of flour from UNRWA.Every day, I think we will not survive, either because we will be killed by Israeli bombing or by hunger," she said. "There is no third option."The majority of private companies that Israel had in the past allowed to bring in food to Gaza say they are no longer able to do so. The war in Gaza broke out after Hamas's October 7, 2023, attack on southern Israel, which resulted in the deaths of 1,208 people, mostly civilians, according to an AFP tally based on official data.

Ben Stokes lashes out at ICC after England's WTC points docked

New Delhi. England captain Ben Stokes lashed out at the ICC after the team faced deductions in the World Test Championship points. The sanctions were put against New Zealand and England during the 1st Test of the series in Christchurch. Stokes took to his Instagram and shared a post over the same and captioned, "Good on you ICC. Finished the game with 10 hours of play still left." Stokes was unhappy with the deduction in points and highlighted that the match ended well within time.

Both New Zealand and England were fined 15% of their match fee and three points were docked in the World Test Championship standing. These penalities come in at a very critical juncture of the WTC 23-25 cycle as the teams are fighting it out to finish in top

England's commanding eight-wicket win at Hagley Oval may have been a showcase of dominance, but it does little to alter their fate in the World Test Championship (WTC), as they are already out of contention for the final. However, the victory dealt a



significant blow to New Zealand's campaign.Ben Stokes' Insta storyA points deduction has pushed the inaugural WTC champions down from joint fourth to fifth place in the standings, leaving them with a reduced points percentage of 47.92%. Even if New Zealand secures wins in both of their remaining Tests against England, their maximum possible points percentage rises to just 55.36%. This leaves the Black Caps in a precarious position, needing more than just back-to-back victories. They must rely on favorable outcomes in other matches to keep their slim hopes of reaching the final alive, making their path to qualification a daunting one. The penalties arose as both sides were found to be three overs short of the target after accounting for time allowances. Under competition rules, teams are penalized one championship point for each over they fall short.Captains Tom Latham (New Zealand) and Ben Stokes (England) admitted to the offense and accepted the sanctions, negating the need for a formal hearing. The charges were brought by on-field umpires Ahsan Raza and Rod Tucker, with support from third umpire Adrian Holdstock and fourth official Kim Cotton.

6mm grass, rain on Day 1: Adelaide pitch curator talks conditions for 2nd Test

Adelaide. Adelaide Oval's pitch curator Damian Hough has confirmed that the wicket will have an even covering of grass -6mm to be exact in the 2nd Test match of the Border-Gavaskar Trophy. Speaking to the press on Wednesday, 4 December, Hough said that the conditions will help the seamers. Asked if the conditions will be overwhelmingly favourable for fast bowlers in Adelaide, Hough said that him and his team were trying to make a balanced wicket where batters, pacers and spinners can impact the Test match. However, the curator added that under certain parameters such as



under the lights or overcast conditions, the

seamers will get a lot of help from the

Day 1 of the Adelaide Test match, with 88 per cent chances of rain predicted on December 6. Hough said that in those days, the ball will swing and seam but it will not be because of the pitch, but due to the conditions on the venue."History suggests that it is hard to bat under lights in Adelaide. The pitch will have 6mm of grass. We are trying to produce a pitch that would be a good contest. The pitch did not play a part in the Test match finishing in 3 days last time India were here. I thought that it was really good bowling from Australia. As long as there is something in it for all aspects of the game, I am happy, I just want a good contest," Adelaide Oval curator Damian Hough told the press on Wednesday, 4 December. "The ball hooping around has got nothing to do with the pitch. Under right conditions, right weather, the ball will move," he further added. The last time India played in Adelaide, they were bowled out for 36 - their lowest ever Test total in Test cricket. The team go into the Test match this time around with more confidence. India won the first Test match of the series by 295 runs - their biggest win in Australia by the

The team will try to replicate their success from Perth as they hunt for a spot in the final of the World Test Championship.

Probable top-eight sweat it out ahead of day-night challenge

₩hile nothing is certain as of now, it could well be the top eight of India's XI for the second Test against Australia that begins Friday.

New Delhi. With thousands of fans getting a close-in view, India captain Rohit Sharma had two extensive net sessions ahead of the pink-ball Test in Adelaide on Tuesday.

Sharma, who missed the first Test, having hinted at batting in the middle-order to allow Yashasvi Jaiswal and KL Rahul remain at the top, did show a lot of resolve while facing the Pink Kookaburra. During the session, Indian team had four nets at the practice arena.

In one such net, Jasiwal and Rahul took turns

New Delhi India's veteran speedster Umesh

Yadav reacted to West Indies fast

bowlerJayden Seales, breaking his record of

the most economical spell in Test history.

Umesh congratulated Seales for his

achievement and was elated to witness Test

cricket thrive. The West Indies pacer

delivered an extraordinary bowling

performance in the 2nd Test vs Bangladesh

at Kingstown. He bowled the most economical spell in the history of Test

cricket by a speedster. Seales bowled 15.5

overs, including 10 maidens, conceding just

five runs while claiming four crucial

wickets. He economy rate was 0.30, which is

the second best in Test history."Congrats to

Jayden Seales on an amazing performance-4

wickets with an economy of 0.31! You've

broken my record, and I couldn't be happier

to see Test cricket thriving with such talent.

The purest form of the game tests skill,

patience, and character, and you've shown it



to bat while Shubman Gill and Virat Kohli were in the second net. It was the third net where Rohit was clubbed with the inimitable occupied by Nitish Kumar Reddy and Washington Sundar. While nothing is certain

Umesh Yadav reacts to Jayden Seales breaking

held by the Indian pacer whose economy rate

clocked 0.42 vs South Africa in 2015 Test

match. Until Seales' spell, Umesh Yadav's

0.42 (21-16-9-3) was the best - both among

pacers and among any bowler since that

Nadkarni spell. Apart from Umesh, the only

other 21st-century entry in the top ten is

Nathan Lyon's 0.45, set across his 22-17-10-

as of now, it could well be the top eight of India's XI for the second Test against

in their attempt to get ready for the day-night challenge, the highlight of the day was fans

Australia that begins Friday. Rishabh Pant while the final net was Even as India trained for more than four hours

getting a close-in view of their heroes in the nets. Just next to the enclosed nets was a viewing area where fans, thousands of them stood in line, to get a glimpse of their sporting stars. As it did in 2018-19, a clipping of Virat Kohli batting with the sound of his bat did the rounds on social media.Meanwhile, Rohit faced a lot of side-arm throwdowns from Nuwan Seneviratne along with usual stuff from the right-arm specialist Raghu Raghavendra and Dayanand Garani. The skipper made a conscious effort to leave deliveries on length but whenever anything short was dug in, he would pull effortlessly.

Bengal fast bowling duo of Akash Deep and Mukesh Kumar (reserve pacer) looked impressive during the session. While Mukesh got his deliveries to move in the air creating some sort of a challenge for Virat Kohli, Akash did ask probing questions to Gill, who looked comfortable.

While there are a few questions left to be answered on India's combination for the second game, some of them might get clear when a member of the team/support staff address the media on Wednesday.

Adelaide Test: KL Rahul has press in splits with reply to batting order question

Adelaide. India batter KL Rahul had the press room in splits when he was asked about his batting position in the Adelaide Test match. Rahul told the press that he was told what position he would bat in, but was also told not

Speaking at the press conference on Wednesday, 4 December, Rahul spoke in details about his batting, and how comfortable he is batting in different positions in the line-up. Rahul said that he just wanted to be a part of the playing XI of the Indian Test team and did not mind batting in any position. Rahul's comments come in the background of India potentially making big changes in their batting line-up for the pink ball Test in Adelaide. India are expected to have Rohit Sharma and Shubman Gill back in the side for the 2nd Test match of the Border-Gavaskar Trophy. In case both batters return, KL Rahul might have to drop down to No.5



Bangladesh script history Seales economical spell helped West

wickets included key dismissals of

Litton Das, Mehidy Hasan Miraz, Taskin Ahmed, and Nahid Rana.

Indies bundle Bangladesh out for 164 runs in 1st innings. However, this did not prove to be enough. Bangladesh secured a historic victory in the Caribbean, defeating the West Indies by 101 runs at Sabina Park to draw the Test series. This marked their first Test win in the West Indies in 15 years. Set a challenging target of 287, the West Indies fell short, all out for 185 in less than two



and displace Dhruv Jurel from the playing XI.KL Rahul has batted in a total of 5 positions for India in Test cricket. Apart from the 2 opening slots, Rahul has batted at No.3, No.4, and No.6 as well."I just want to be in the playing XI, go out there and bat and play for the team. I just go there and try and see what I need to do to get runs in a particular situation. Luckily I have batted in different positions. Early on, when I was asked to bat at different positions, it was a bit of a challenge mentally. How to play those first 20-25 balls? how early can I attack? Those things were a problem earlier, but it has gotten easy with the experience of playing in different formats," KL Rahl said. The right-hander batted brilliantly in the second innings of the Perth Test match alongside Yashasvi Jaiswal, where they notched up a partnership of 200+ runs, the first by any Indian opening pair. Rahul said that he was told by the Indian team management that he might open in the Perth

0.Umesh Yadav's tweetSeales scripted his name into the record books by delivering the all," Umesh tweeted. Earlier, the record was We don't talk anymore: Harbhajan Singh's shocking remark on equation with Dhoni

New DelhI Former India spinner Harbhajan Singh said him and MS Dhoni do not talk to each other. Speaking to News18, Harbhajan has revealed that while he does not have a problem with MS Dhoni, him and the former India captain are not friends anymore.

Harbhajan and MS Dhoni were integral parts of the Indian team that won the 2007 T20 World Cup and the 2011 ODI World Cup. While Dhoni captain the team in bot editions

and was the team's brains, Harbhajan shined with 7 and 9 wickets in respective tournaments. The spinner revealed that he and MS Dhoni did not speak outside the field during their years at the Chennai Super Kings as well. Harbhajan played for the Chennai-based franchise between 2018-2020. He further added that he only rings those people who pick up his calls."No, I don't speak to Dhoni. When I was playing at CSK, that's when we spoke, but otherwise,



we haven't spoken. It's been 10 years and more. I have no reason; perhaps he does. I don't know what the reasons are. When we were playing in the IPL at CSK, that's when we used to talk, and that, too, was restricted to the ground. After that, he did not come to my room, nor did I go to his," Harbhajan Singh told News18."I don't have anything against him. If he has something to say, he can tell me. But if he did, he would have told me by now. I never tried to call him because I have a lot of passion. I only ring up those

Former India spinner Harbhajan Singh has said that he does not talk to MS Dhoni. In a shocking claim, Harbhajan has said that friendship is a two-way street, and he only rings up people who pick up his calls.

who pick up my calls. I don't have the time otherwise. I stay in touch with the ones I am friends with. A relationship is always about give and take. If I respect you, I hope you will respect me back. Or you respond to me. But if I call you once or twice but don't get a response, I will probably only meet you as much as I am needed to," the spinner added. The last time Harbhajan and Dhoni represented India together was in 2015 – in an ODI against South Africa. After the 2015 World Cup, Harbhajan and Yuvraj Singh were sidelined from Indian team. While Harbhajan did not play after 2015, he announced his retirement from all forms of cricket in 2021.

WI vs BAN: Taijul stars as Bangladesh draw series with 101-run win in 2nd Test

Bangladesh secured a historic victory in the Caribbean, defeating the West Indies by 101 runs at Sabina Park to draw the Test series. This marked their first Test win in the West Indies in 15 years.

New DelhI. Bangladesh secured a historic victory in the Caribbean, defeating the West Indies by 101 runs at Sabina Park to draw the Test series. This marked their first Test win in the West Indies in 15 years. Set a challenging target of 287, the West Indies fell short, all out for 185 in less than two sessions. Bangladesh had lost their previous seven Tests in the Caribbean, including the first match of this series in Antigua, but their performance in this match brought them level in the short

Taijul Islam was the star performer for Bangladesh, taking 5-50 in the West Indies' second innings. It was his best overseas bowling performance in 2 1/2 years and his best figures in the West Indies since his Test debut in 2014. With the pitch offering grip and occasional low bounce, Taijul's spin caused the West Indies' collapse, with the last six wickets falling for just 42 runs. Taijul Islam was the star performer for Bangladesh, taking 5-50 in the West Indies' second innings. It was his best overseas bowling performance in 2 1/2 years and his best figures in the West Indies since his Test debut in 2014. With the pitch offering grip and occasional low bounce, Taijul's spin West Indies' Struggle in the Chase six wickets falling for just 42 runs.In Bangladesh's second innings, Jaker Ali played a crucial role, scoring a career-best



91. His innings included five sixes and eight boundaries, and he was the last man out just before lunch, giving West Indies a challenging target. Jaker's aggressive batting ensured Bangladesh's total was competitive, despite a lower-order collapse.

caused the West Indies' collapse, with the last West Indies captain Kraigg Brathwaite led a positive start to the chase but could not form a lasting partnership. He was dismissed for 43, and the team struggled to build

momentum. Mikyle Louis and Keacy Carty fell to Taijul and Taskin Ahmed, and Brathwaite's departure further hindered the chase. Kavem Hodge, who scored a half-century, tried to keep the West Indies in the game, but once he fell for 55, the rest of the team quickly followed. Taskin Ahmed, Hasan Mahmud, and Nahid Rana joined Taijul in dismantling the West Indies' lower order. Taijul's brilliant spell earned him

his 15th career five-wicket haul, trapping Joshua Da Silva to seal the victory for Bangladesh. The West Indies' chase began with promise, but they failed to maintain consistency. Brathwaite's 43 and Hodge's 55 were the highlights, but they were unable to sustain the required partnerships. Bangladesh's bowlers, particularly Taijul, exploited the conditions expertly, and the West Indies were bowled out for 185, falling 101 runs short.

Paparazzo Holds Sherlyn

Chopra's Hand As She Struggles

To Walk In High Heels





Sherlyn Chopra and her paparazzi appearance – a love affair that needs no introduction. Often stealing the limelight with her candid conversations with the shutterbugs and head-turning looks, the model and actress dishes out fashion goals with her casual outings. This time around, she decided to take it a notch higher, slipping into a saree as paps captured her in a video. The clip has now surfaced on social media as it shows Sherlyn struggling while trying to walk in high heels. In a kind gesture, one of the paps stationed there extended his helping hand but the struggle was real. The clip opens with a photographer holding Sherlyn Chopra's hands as she tries to step out of a building, wearing a bright yellow saree and high heels. Struggling to walk through the corridor assuming that she may fall, Sherlyn is visibly scared in the clip. may fall, Sherlyn is visibly scared in the clip. Despite the help, she finds it difficult to take a step forward and stops to drink water instead. As the video progresses, another man joins in, holding her another hand but the attempts fail miserably. At the end of the clip, she is seen posing from inside the building and also showcases her beige high heels.

showcases her beige high heels.

Days before her candid appearance, Sherlyn Chopra sat down for an interview with Bollywood Bubble, revealing the illness she has been battling since 2021. The actress shared that she has an autoimmune disorder called Systemic lupus erythematosus (SLE) which led to her kidney failure in 2021. Her doctor advised her to keep this health disorder under control through medication, as she revealed during the discussion. Sherlyn said, "I take it three times a day, morning, afternoon and evening. They also advised that I should never contemplate getting pregnant because it could be life-threatening for both the baby and the mother".

Despite the illness, Sherlyn Chopra holds a

the mother".

Despite the illness, Sherlyn Chopra holds a strong desire to be a mother as she added, "I think I was born to be a mother because whenever I think about children, I feel an indescribable happiness. Even before they arrive, I'm so happy. Just imagine how much joy I'll feel after they're here. "Sherlyn Chopra made headlines in 2012 as she became the first Indian woman to pose for Playboy magazine. Later, she began her career in Bollywood with films like Time Pass (2005), Dosti: Friends Forever (2005) and Raqeeb (2007). She also entered the Bigg Boss Season 3 in 2009.

Taapsee Pannu Shares How Marketing Lesson By Shah Rukh **Khan Changed Her Mindset:** 'Billboards Were Used...'



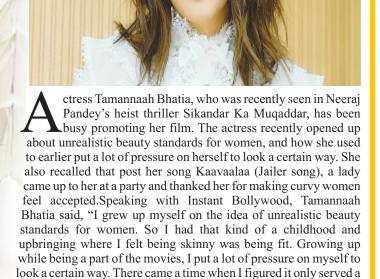


aapsee Pannu is one of the most versatile actresses in the industry. She has worked with many established actors and has also given hits at the box office. Recently, she shared a valuable marketing lesson she learned from Shah Rukh Khan and it has also changed her mindset. In a conversation with Connect Cine, Taapsee Pannu revealed how Shah Rukh Khan's perspective towards marketing helped her rethink. The Phir Aayi Hasseen Dillruba actress revealed that Shah Rukh Khan likes influencers to advertising and think them as advertising tool akin to hoardings or banners which used to promote films in earlier decades. Taapsee shared what King actor said, "Think about it—10 or 20 years ago, billboards were used to publicize films. Now, these individuals are the new marketing tools. Don't see them as people with responsibility; see them as advertising spaces available for sale."

'It's all about perspective. You see it one way; I see it another. Ultimately, it's up to you which side you choose," she said. Taapsee Pannu and Shah Rukh Khan worked together in Dunki. The film garnered immense love from fans and critics alike, with its box office success speaking volumes. The movie also marked the first collaboration between Shah Rukh Khan and Taapsee Pannu. Recently, in an interview, Taapsee reflected on her experience working with the superstar. She lauded his vast knowledge, sharp wit, and undeniable charisma, noting how these qualities make him truly stand out among his peers. Taapsee Pannu has carved a niche for herself in the film industry with acclaimed performances in movies like Pink, Thappad, and Haseen Dilruba. She was last seen in Phir Aayi Haseen Dilruba, alongside Vikrant Massey and Sunny Kaushal. Directed by Jayprad Desai, the sequel premiered on Netflix on August 9. Taapsee's next project, Gandhari, is already generating buzz. Netflix recently unveiled an introductory teaser for the film, which appears to focus on a mother who takes extreme measures to protect her children when they are in danger.



Discusses Beauty Standards; Recalls Fan's Reaction Post Kaavaalaa: 'You Were So Big And Fat...'



certain utility, but it didn't actually make me feel beautiful. Times that I actually started to feel good about myself had rarely anything to do with how thin I was. I somewhere feel like maybe Aaj Ki Raat helped me accept my body."

She then recalled the incident when a fan walked up to her and thanked her for representing curvy women. "When Kawala came out, one lady walk up to me at a party and said, 'Thank you! Because of you, us curvy women feel accepted. You were so big and fat and yet you were enjoying.' For the first time I registered that according to this lady, I was fat. I didn't completely understand that till I didn't hear it from a person. I thought it was normal. I thought that was beautiful. That was my understanding. But I understand that today everyone has a phone, everyone has a camera, everyone is posting pictures on Instagram. So, everyone has this pressure. Early on, I was an actor it was a part of my job. I had to look at my body. But today every young girl is doing that," said the actress. She said that now that she is in a position of power, and has agency, she wants to emphasize that beauty has nothing to do with how thin or how fair one is. She then recalled a time when she was dressed to the nines, yet she hated herself because she was uncomfortable and couldn't breathe. It didn't make her feel beautiful. "But I felt beautiful sometimes when I was naturally dressed, sometimes without my makeup or hair done. So beauty has literally nothing to do with all those standards," said Tamannaah.

Pushpa 2 The Rule:

Sreeleela

Sets The Stage Ablaze With Her Performance On Kissik At Pre-Release Event

ushpa 2: The Rule, starring Allu Arjun, Rashmika Mandanna and Fahadh Faasil is among the most highly anticipated upcoming films. With just two days to go for the film's release, the excitement among fans is sky-high. Last night, the pre-release event of Pushpa 2 was held in Hyderabad, and visuals from the grand event have gone viral on social media. One such video shows Sreeleela setting the stage on fire with her performance on the fiilm's song Kissik.Dancing queen Sreeleela, who has a guest appearance in the Pushpa 2 song Kissik, was seen grooving to the song during the pre-release event. She left her fans mesmerized with her sizzling dance moves. She aced the hook step of the Kissik song, while fans cheered for her. She was also seen waving at her fans! Sreeleela looked gorgeous in a white,

pink and green striped saree, and left her hair open. Check out the video below!

The foot-tapping number Kissik from Pushpa 2: The Rule was unveiled by the makers in November. Composed by Devi Sri Prasad, this dance anthem has been sung by Lothika and Sublahshini. Meanwhile, the promotion of Pushpa 2: The Rule has been taking place in full swing. Allu Arjun, Rashmika Mandanna and other team members of Pushpa 2 are leaving no stone unturned to ensure that the film is a huge success. The trailer launch of Pushpa 2 was held in Patna, followed by pre-release events in Chennai, Kochi and Mumbai.

Meanwhile, at the event in Hyderabad, Pushpa 2 director Sukumar lauded Allu Arjun for his dedication and hardwork, and it left the actor in tears. The filmmaker said, "Pushpa-1 and Pushpa-2 happened because of the love I have for Bunny. Our bond is like an exchange of energy. For even the smallest expression, Bunny puts in incredible effort—whether it's moving an eyelid or delivering a perfect voice modulation. That level of commitment inspires any filmmaker."The grand event was also attended by Rashmika Mandanna and director SS Rajamouli. The film is set to release in theatres on December 5.

